C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXVI, Twelfth Session, 2017/1939 (Saka)
No. 15, Friday, August 4, 2017/Shravana 13, 1939 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
REFERENCE BY THE SPEAKER	
72nd anniversary of the dropping of atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki	7-8
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 281 to 285	10-66
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 286 to 300	67-110
Unstarred Question Nos. 3221 to 3450	111-515

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 517-535

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and DIPAM, Ministry of Finance

Shri Arun Jaitley 536

(ii) Organization of India International Science Festival (IISF)

Dr. Harsh Vardhan 537-538

BUSINESS OF THE HOUSE 539-545

MOTION RE: ELECTION OF TWO MEMBERS TO CENTRAL ADVISORY BOARD ON DISABILITY 546

MOTION RE: ELECTION OF FOUR MEMBERS TO CENTRAL SILK BOARD 547

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i)Re: Need for exemption from GST on ongoing Government sponsored schemes 548-551

(ii)Re: Exclusion of Ms. P.U. Chitra, the Asian Gold medallist from the list of the 24-member team from India to take part in the World Championship in London 648-649

INDIAN INSTITUTE OF PETROLEUM AND ENERGY BILL, 2017 553-634

Motion to Consider 553-557

Shri Dharmendra Pradhan 555-557, 623-628

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 558-562

Dr. Kambhampati Haribabu 563-567

Prof. Saugata Roy 568-572

Shri Tathagata Satpathy 573-577

Shri G. Hari 578-580

Shri Arvind Sawant 581-583

Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi) 584-588

Prof. A.S.R. Naik 589-591

Shri P.K. Biju 592-595

Shri Y. V. Subba Reddy 596-598

Shrimati Bijoya Chakravarty 599-601

Shri Jai Prakash Narayan Yadav 602

Shri Dushyant Chautala 603-604

Shri Raghav Lakhanpal 605-606

Shri Prem Singh Chandumajra 607

Dr. Ratna De (Nag) 608-610

Shri Kaushalendra Kumar 611-612

Shri A.T. Nana Patil 613-615

Shri Bhagwant Mann 616

Dr. Arun Kumar 617

Shri N.K. Premachandran 618-619

Shri Ravindra Kushwaha	620
Shri Rajesh Ranjan	621-622
Clause 2 to 45 and 1	628-634
Motion to Pass	634

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	665
Member-wise Index to Unstarred Questions	666-671

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	672
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	673

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 04, 2017/ Shravana 13, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

REFERENCE BY THE SPEAKER

72nd anniversary of the dropping of atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको याद होगा कि 72 वर्ष पूर्व 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराये गये थे, जिसके कारण दोनों शहर तहस-नहस हो गये थे। इस त्रासदी में हजारों लोग मारे भी गए थे तथा लाखों लोग घायल हो गए और कई लोग तो जीवन भर के लिए अपंग हो गए।

72 वर्ष के बाद आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी उन हमलों में हुए परमाणु विकिरण के दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं।

भारत की अहिंसा के सिद्धान्तों के प्रति सदैव अटूट आस्था रही है तथा हमने शान्ति और स्थिरता बनाये रखने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत सदैव 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के लिए प्रयासरत रहा है।

फिर भी आज भी विश्व में परमाणु ऊर्जा के मिसयूज, गैर वापर के लिए सदैव आशंका बनी हुई है। आइए, आज के दिन हम इस नरसंहार के हथियारों को समाप्त करने तथा विश्वभर में शान्ति और भाईचारे के संवर्धन हेतु एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लें और एक प्रार्थना भी हम कर सकते हैं।

"ऊँ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु।
सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलम् भवतु।।
ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः"

मतलब (May all attain peace, may all be healthy – may all enjoy good fortune, may none suffer misery and sorrow, OM!! Peace Peace Peace)

अब यह सभा जापान में परमाणु बम त्रासदी से पीड़ित हुए व्यक्तियों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

11.01 hours

(The Members then stood in silence for a short while.)

माननीय अध्यक्ष : ऊँ शान्तिः शान्तिः।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 281

…(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, मुझे दो मिनट का समय दीजिए।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow you after the Question Hour.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन ऑवर के बाद आपको बोलने का मौका दूँगी।

…(व्यवधान)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Madam Speaker, I would like to raise an important issue… (*Interruptions*) There are huge losses owing to GST implementation… (*Interruptions*) We want to raise it for the sake of our State. I will finish within two minutes… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you after the Question Hour.

… (*Interruptions*)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : महोदया, यह एक महत्वपूर्ण इश्यू है। मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन ऑवर के बाद बोलने का मौका दूँगी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ। मैं क्वेश्चन ऑवर के तुरन्त बाद आपको बोलने का मौका दूँगी।

…(व्यवधान)

11.04 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Question No. 281

(Q. 281)

श्री रवीन्द्र कुमार राय: अध्यक्ष महोदया, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप से उत्तर दिया है और विस्तृत उत्तर के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। निःसंदेह, सरकार के और खासकर, दिल्ली के जो केन्द्रीय अस्पताल हैं, वहां अधिक रोगियों का दबाव बढ़ा है और उसमें से एम्स पर रोगियों का दबाव बहुत बढ़ा है। पूरे देश भर से लोग एम्स में इलाज़ कराने आते हैं। व्यावहारिक तौर पर, पूरे देश में अभी एक ही एम्स काम कर रहा है, वह है दिल्ली का एम्स। पूरे देश भर में जो थके-हारे, निराश रोगी होते हैं, वे यहां दिल्ली में इलाज़ कराने के लिए पहुंचते हैं। वैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जितने रोगियों का पंजीयन होता है, उतने रोगियों का इलाज़ हो जाता है।

मेरा सुझाव है और उनसे अनुरोध है कि एक तो पंजीयन कराने में ही बहुत बड़ी कठिनाई हम लोगों को, क्षेत्र से आए हुए लोगों को और ऐसे लोग, जिन्हें सामान्य बीमारी होती है, उन्हें हो रही है। विडम्बना यह है कि डॉक्टर ही इलाज़ करके कहते हैं कि यह जो आपकी बीमारी है, इसका इलाज़ दो महीने के अन्दर हो जाना चाहिए, लेकिन जब वहीं उसका इलाज़ करने की बात आती है तो वे कहते हैं कि आपको तीन वर्ष के बाद का समय दिया जाता है। यह ऐसी अव्यावहारिक बात है कि वहीं के डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको दो महीने के अन्दर ऑपरेशन करा लेना है और जब ऑपरेशन कराने की तिथि की मांग की जाती है, तो वे कहते हैं कि आपका समय तीन वर्ष के बाद आएगा। अब वह रोगी कठिनाई में पड़ जाता है कि हम कहां जाएं। डॉक्टर उसे यह चिन्हित करते हैं कि आपको दो महीने के अन्दर इसका इलाज़ करा लेना जरूरी है, ऑपरेशन करा लेना जरूरी है। वह रोगी चाहता है कि वहीं पर वह किसी तरह से इलाज़ करा ले।

अध्यक्ष महोदया, इन्होंने दिल्ली के केन्द्रीय अस्पतालों की चर्चा की है। मेरी प्रार्थना है कि कई बार ऐसी व्यावहारिक कठिनाई आती है कि एम्स के डॉक्टर बगल के हॉस्पीटल सफ़दरज़ंग में रेफर करते हैं और वहां के डॉक्टर्स उसका इलाज़ करने से इन्कार कर देते हैं। यदि वे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसे रेफर करते हैं तो वहां के डॉक्टर भी इलाज़ करने से इन्कार कर देते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि एक तो समयावधि के अन्तर्गत, आवश्यकता के अनुसार जो डॉक्टर यह फिक्स करते हैं कि इतने दिनों के अन्दर इसका इलाज़ होना चाहिए तो वह इलाज़ कराने की समयावधि

निश्चित करनी चाहिए। दिल्ली के जो केन्द्रीय अस्पताल हैं, उन्हें एम्स के साथ जोड़ा जाए, ताकि उनके रेफरेंस को वे स्वीकार करें और उन लोगों का इलाज़ हो सके।

माननीय अध्यक्ष : ये सुझाव वे मान्य कर रहे हैं कि नहीं, यह आप बोलना चाहते हैं?

श्री रवीन्द्र कुमार राय: महोदया, मैं प्रश्न कर रहा हूं कि क्या वे दिल्ली के सभी हॉस्पीटल्स को एम्स के साथ जोड़ेंगे और इलाज़ के समय की निश्चितता को स्वीकार करेंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदया, सबसे पहली बात तो यह है कि जहां तक 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' का सवाल है, 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' ने स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है। इसलिए सबका प्रिफरेंस 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' से ही इलाज़ कराने का है। लेकिन, इसके साथ-साथ हम लोगों ने इसी को विभिन्न राज्यों में इसी को रेप्लीकेट करने की कोशिश की है।

हम दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' की कपैसिटी को हम डबल कर रहे हैं और उसका उत्तर हमने विस्तृत रूप से दिया है। 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' में अभी जो काम चल रहा है, उसके कैम्पस में हम लगभग 1,563 बेड्स एडिशनल जोड़ रहे हैं और लगभग 3,119 करोड़ रुपये इस पर खर्च हो रहा है। इस तरीके से, हम 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' के लिए काम कर रहे हैं।

दूसरा, हम लोगों ने स्टेट्स में जो फेजवाइज 'ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' खोले हैं, उनमें भुवनेश्वर, जोधपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर में ये बहुत हद तक ऑपरेशनल हो गए हैं और इसके माध्यम से वहां के पेशेंट्स की जो डिमांड है, उसे कवर करने के लिए वे सक्षम हो रहे हैं। धीरे-धीरे हम सभी की कपैसिटी बढ़ा रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है, हमारे यहां यही व्यवस्था होती है कि यदि किसी भी पेशेन्ट को रैफर किया जाता है, तो हम उसको जरूर इंटरटैन करते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं, जिनको दूसरे हॉस्पिटल्स भी कैटर कर सकते हैं, लेकिन पेशेन्ट की इच्छा होती है कि उनको इसी हॉस्पिटल में कैटर किया जाए, इसलिए यहां पर प्रेशर बढ़ रहा है। Sometimes, they again refer back to Safdarjung or Ram Manohar Lohia Hospital because that facility is available there. वहां वह किया जा सकता है और जो केसेस लाइफ सेविंग की सिचुएशन में आ जाते हैं, जहां पर करने की जरुरत होती है। हमने अपने आई.सी.यू. को भी बढ़ाया है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ इसको कैटर कर रहा है। हमारे लिए यह बड़े ही संतोष की बात है और सारे देश के लिए गर्व की बात है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, नई दिल्ली क्वालिटी वाइज भी तथा जितने

नंबर ऑफ पेशेन्ट को इंटरटैन करता हैं, दोनों को मेंटेन करते हुए बैलेंस बना रहा है। यह दुनिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, जिसका दुनिया में एक स्थान बना है।

श्री रवीन्द्र कुमार राय: अध्यक्ष महोदया, मेरे दूसरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जवाब भी दिया है। पूरे देश तथा हम लोग अपने राज्य में भी देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों में अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल बने हैं और ये हॉस्पिटल्स देखने लायक हैं। वास्तव में अगर उनमें सुविधा हो जाए, तो शायद बहुत ही कम रोगियों को दिल्ली आना पड़ेगा। लेकिन, दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, निसंदेह उसमें राज्य सरकार की भी भूमिका है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बने हुए अस्पतालों में डॉक्टर्स तथा स्वास्थ्य की उपलब्धता बनायी जाए, इसके लिए राज्य सरकारों से मिलकर पहल करने की कोशिश क्या केंद्र सरकार एवं माननीय मंत्री जी करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: हमने नेशनल हैल्थ मिशन के तहत इसके लिए पहल कर रखी है। हम उनको इंस्टीट्यूशन के स्ट्रैंथनिंग के लिए पैसा देते हैं और टेक्निकल सर्पोट भी देते हैं। इसके साथ-साथ उनके एक्विपमेंट्स के लिए भी हम पैसा देते हैं। हम उन्हें ह्यूमन रिर्सोस डेवलपमेंट के लिए पैसा देते है, उनकी ट्रेनिंग के लिए पैसा देते हैं और उनकी तनख्वाह की भी व्यवस्था करते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का जो उनका स्टेट प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन प्रोग्राम है, उसमें डालना पड़ता है। यदि वे उसमें डालें, तो जरूर उनका जो एन्वलप है, उसके तहत हम इसके लिए सपोर्ट करेंगे।

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: Madam Speaker, thank you.

As all of us know, the expenditure which has been incurred for the purpose of medicine and related medical expenditure in our country is less than many other countries of the world. Here, my specific question is about the North-Eastern States in general and the State of Tripura in particular. To the Question as to how much expenditure was incurred on these States, the Minister has given a detailed reply.

You can see that in the case of hospital strengthening, the North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur and Meghalaya are getting more funds than the State of Tripura. I am not unhappy. Of course, I am happy because after all, our North-Eastern States are getting more money. But, as you know, Tripura is the second most populous State in the North-Eastern region, but it is getting only Rs. 250 lakh.

In the case of hospital strengthening and also in the case of new construction of hospitals, the State of Tripura is getting less amount. Our State Government has sent so many proposals for the purpose of establishing a regional cancer centre for prevention and research. Such a type of institution is necessary in the North-Eastern region. So, our State Government has sent a proposal on 18th February of this year. For establishing that centre only Rs. 400 crore is required. It can cater to all the patients belonging to the North-Eastern States. So, one regional cancer centre should be established.

Another proposal for establishing a regional nursing college has also been sent and that proposal has been sent six times. The DPR has also been sent six times.

HON. SPEAKER: What is your question?

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: As per the initiative of the Central Government, our Government has allotted three acres of land near the medical college. My specific question to the Minister is this. I would like to know as to by what time the amount which is required for the purpose of establishment of this institute in the State of Tripura would be allocated so that the patients of the North East get benefited.

SHRI JAGAT RAKASH NADDA: Madam, I would like to make it very clear to the hon. Member that we do not differentiate between the States. There is a broad policy which has been formulated under which the North Eastern States have got their own parameters based on which allocation of fund is decided. In the same way, there are high focus States, there are States which are not on high focus. According to the disease and other things, high focus States are decided. The envelope of the National Health Mission is decided according to the population also. The State Programme Implementation Plan is with the State Government. Whatever proposals come, your envelope is there and it is not differentiated from State to State. There are States which have also got less because the proposals have not come. I assure the hon. Member that within the envelope, whatever

proposal will be coming from the State Programme Implementation Plan, we will be considering it and giving the money accordingly.

As far as the Regional Cancer Institute is concerned, it comes under a different head and certainly if there is a proposal, we will look into it.

SHRI M. I. SHANAVAS: Madam Speaker, I thank you for giving me the opportunity to ask a question from this seat.

The question is pertaining to the General Hospitals in Delhi. But all over India, the General Hospitals lack infrastructural facility, medicines, treatment etc. Now, the point is, running of private hospital has become a lucrative business in India. The Shylockian methods followed by private hospitals are torturing the poor patients. Poor patients cannot go to private hospitals. So, let me put a specific question to the hon. Minister.

Does the Government have the guts to enact a legislation to control the mercantile goals of private hospitals so that poor people can also go to private hospitals and have treatment there?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, I would like to make it very clear that when he is talking about the hospitals, the answer which I have given about Delhi is about the hospitals which are run by the Central Government. We are not talking about the hospitals which are run by the State Government even in Delhi and outside. In States, it is the responsibility of the State to run those hospitals. We give them infrastructural support and 73 hospitals have been given the facility of Super Specialty Block and Rs. 150 crore is being given to them for that purpose. In the same way, upgradation of District Hospitals to Medical Colleges is being done and 58 Medical Colleges have been selected in this project. We are working on it and we are giving an amount of Rs. 189 crore for each hospital to develop. But it is the responsibility of the States to develop them. So, giving a general statement is not correct. The Central Hospitals in Delhi are Safdarjung Hospital, Lady Harding Hospital, Ram Manohar Lohia Hospital, All India Institute

of Medical Sciences and Vallabhbhai Patel Chest Institute. Therefore, there is a distinction between the two.

Secondly, the hon. Member has mentioned about private hospitals. Although that question does not pertain to the main question, still I would like to answer him. He asked whether the Central Government has got the guts to enact a new legislation. The Central Government has passed the Clinical Establishment Act. Now it is for the States to adopt. It is they who have to show whether they can adopt or not. It is for them to do it. We are ready for it and the Clinical Establishment Act covers all those things which the hon. Member has mentioned and that will be taken care of only when the States adopt the Clinical Establishment Act.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Madam Speaker, according to a report, it is estimated that 14.5 lakh people are living with cancer in our country, over seven lakh cases get registered every year, out of which 5.5 lakh cases result in death due to cancer. Most of the cancer patients require radiotherapy or chemotherapy. Some require only radiotherapy and some require only chemotherapy. But in the Government hospitals, there is a huge scarcity of these radiotherapy machines. Patients have to wait for four to six months to get radiotherapy. Even if the surgery is over, they have to wait for four to six months. Therefore, they are referred to private hospital for radiotherapy. But what about those patients, who cannot afford this treatment? Due to lack of this treatment, over a period of four to six months, the cancer reaches its next level.

HON. SPEKAER: Please ask your question.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Yes, Madam.

My specific question to the hon. Minister is: whether the Government is planning to provide these radiotherapy machines in every Government hospitals where this cancer treatment takes place.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, as I have already stated, we have started 20 State Cancer Institutes and 50 Tertiary Cancer Centres.

His question is not specific, but it is general. In general, not only this, we are also going in for early screening of cancer. This year, we have taken 100 Districts where we are going to go for universal screening of cervix cancer, breast cancer and oral cancer. So, an early screening is also going on.

As far as the treatment is concerned, it is a continuous development process, which we are doing. But if the hon. Member asks about any specific hospital, we would look into it.

HON. SPEAKER: Now, Shri P. Karunakaran. You have to ask a pointed question and not to make a speech.

SHRI P. KARUNAKARAN: Though there are difficulties in the Government hospitals and there are less facilities, yet these hospitals are a gift for the common people because the treatment they may get there, is free of cost, without any charge.

In this connection, I would like to know from the hon. Minister, whether the Government has any proposal to put some selective Government hospitals in the hands of the private sector. If it is so, it would be really harmful for the society and the common people. There are some reports, which suggest that the Government is going to take such a decision.

So, I need a clarification from the hon. Minister on this issue

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, no such proposal is there; and the Government is not considering it.

HON. SPEAKER: Very good.

Now, Shri Varun Gandhi. You have to ask a very specific question and nothing else.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : About 13 per cent of all the babies that are born in India are born premature; and we have the largest amount of preterm infant deaths in the world. The Government realizing this problem has made a National Human Milk Bank in a hospital in Delhi, which is a very welcome move to

address the problem through breasts feeding and lactation deposits. Will this be spread in hospitals across the country?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: This is a new initiative taken by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India; and we are going to enhance it.

HON. SPEAKER: Thank you.

(Q. 282)

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल: अध्यक्ष महोदया, हमारा देश मातृ शक्ति और नारी शक्ति की पूजा करना जानता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मातृशक्ति और नारीशक्ति की पूजा करता है लेकिन हमारा देश का दूसरा पहलू यह भी है कि अगर कोई महिला विधवा या तलाकशुदा हो जाती है या बलात्कार पीड़ित होती है तो पूरे समाज का नजरिया उसकी तरफ देखने का बदल जाता है। ऐसी स्थिति में उनको जिन्दगी जीना दुष्कर हो जाता है। मजबूरन उनको आत्महत्या कर लेनी पड़ती है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्रालय ने कोई ऐसी योजना बनाई है। मेरी जानकारी में एक वन स्टॉप सेंटर जैसी कोई योजना देश में चली है। वन स्टॉप सेंटर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और हिंसा पीड़ित महिलाएं जो शारीरिक और मानसिक हिंसा से पीड़ित होते हैं उनको क्या सेवा और सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हमारे देश में ऐसे कितने सेंटर हैं खासकर गुजरात में मेरी कंस्टीट्यूएंसी भावनगर में ऐसा कोई सेंटर खोला गया है?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Hon. Speaker, there are 151 centres as of now. These were started as a new initiative by the Modi Government. These centres cater to women, who have been subjected to violence or who anticipate violence. The purpose of these centres is that women who have no access to medical facilities or who have no access to police legal facilities or who are too scared to go to police stations, they can come here. In each Centre that has begun, we have a psychologist, a doctor, a nurse, a lawyer and a policeman. We have a facility with eight beds primarily, which can be expanded. We have got 30,000 women who come to these centres.

In Gujarat, we have made 2 centres so far – one in Sabarkantha district and another one in Rajkot. We are trying to get 600 centres primarily before this term is finished.

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल: माननीय अध्यक्ष जी, हमें अपने देश की बेटियों पर गौरव महसूस होता है कि एवरेस्ट और स्पेस पर पहुंची हैं। देश के लिए क्रिकेट भी खेलती हैं। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर देश का मोर्चा भी संभालती हैं। इस पर हमें गौरव होता है। हमारे देश में तीन साल में हर डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी आई है, बेटियां अपने स्वयं के टैलेंट के कारण भारी मात्रा में जॉब करने लगी हैं, कामकाजी महिलाएं बन रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को दिक्कत तब होती है, जब जॉब करने अलग क्षेत्रों में जाती हैं तो रहने के

लिए बहुत मुश्किल होती है। बड़े शहरों में वर्किंग वूमेन होस्टल हैं लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम है जिसके कारण बहुत महिलाएं इनमें नहीं रह पाती हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सरकार हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट और तहसील लैवल पर वर्किंग वूमेन होस्टल चलाने का इरादा रखती है ताकि देश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो कर आत्मसम्मान से जी सकें?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, under the Scheme of Working Women's Hostels, financial assistance is provided for the construction and running of a hostel for those who may be single, widowed, divorced, separated or married and for those whose husband or immediate family do not reside in the same area. So far, we have made 940 hostels from when the Scheme was started in 1972. These have been sanctioned all over. They have benefited about 70,600 women. In Gujarat, we have 26 hostels. If the State Government applies to us, we are happy to recommend them. These are mainly run by NGOs. We give a one-time grant for construction. We give a rent component and the rest of it is self-financed by charging, I think, a small amount. These are basically for cities and towns because I am not so sure that we need them in rural areas.

HON. SPEAKER: Shri Radheshyam Biswas – not present.

Shrimati Mamata Thakur.

श्रीमती ममता ठाकुर: स्वाधार योजना के तहत रहने वाले बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस नीति का पालन किया जाता है? उसे शिक्षित करने और बाल मजदूरी से बचाने के लिए तीन साल में कितनी राशि का आबंटन किया गया है? अन्य राज्यों में राष्ट्रीय महिला हैल्पलाइन नंबर 181 ठीक से काम नहीं कर रहा है। राज्यों में अलग हैल्पलाइन नंबर भी है लेकिन उनमें बहुत से काम नहीं कर रहे हैं। इससे ग्रामीण महिलाएं मदद पाने के लिए भ्रमित हो रही हैं।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार ने संकट में महिलाओं के लिए व्यावहारिक रूप से संयुक्त हैल्पलाइन द्वारा मदद करने की कौन सी योजनाएं बनाई हैं और कब तक केवल एक हैल्पलाइन नंबर रहेगा?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, actually, this question is completely outside the ambit but I will try and answer.

The helpline has been set up in some States. It is not active in others. In some of the States, for instance, when it was set up in Delhi, two lakh crank calls came in the first day which almost collapsed the system. I think, as time goes on, it will get better. Wherever there is a One Stop Centre, the helpline is connected to that Centre and we send an ambulance out for any woman who is in trouble. The women's helpline has started in April, 2015 and it will provide, ultimately, 24 hours emergency and non-emergency responses to women affected by violence. It has been operational so far in 22 States but with varying degrees of success. Apart from that, we have a panic button on mobile phones which has been delayed but every single new phone has that device. When I say delayed, I mean that I would like the old phones also to get this device through apps. But that should be done by the end of September.

We also have a proposal which has been accepted by the Home Ministry and it is underway, which is 33 per cent reservation for women police officers. With sensitization, if more women come into the police, we certainly will do much better at women protection all over India. So far, seven States have agreed and all the UTs have agreed and have started recruitment.

We also have, something called, the Mahila Police Volunteer force which is based on the very good work done by the Madhya Pradesh Government. They call their women protection units, the Shaurya Dal. Haryana has been the only State to operationalise the Mahila Police Volunteer scheme. We will see how it works and then see whether we can apply it to the other States.

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Madam, my question is regarding Swadhar Greh. I come from a State which has maximum Swadhar Grehs in the country. You have heard about the Manjula case that has happened. A lot of these Swadhar Grehs are well intended. But, in your Reply, in Point 'd', it has been said that there has been no detailed assessment done about how effectively these Swadhar Grehs have been in the last decade. So, what is really the impact assessment? In Manjula's case what had happed, it came out. So, how do we make sure that

every woman in the Swadhar Greh is totally protected? If there is any exploitation, how does she reach out to somebody who will protect her from the exploitation that happens, which does happen in the society, unfortunately?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: That is a good question. The Swadhar Grehs are run almost entirely by NGOs. They come under the District Social Welfare Officer who has to pay them a weekly visit. He then reports to the district level unit which is run by the Collector, the Chief Medical Officer, the SP and, of course, the Social Welfare Officer. These plus two women in each district. This has to meet once every three months. The NGOs have to give a quarterly report to the District Committee and then from there it goes to the State Committee which is run by the Secretary, Social Welfare which meets twice a year. This is actually the chain of inspection. We step in only to give funds. If something goes wrong there, then there are other backup systems. There are the one stop centres. If any specific complaint comes to us, then we take it up through the National Commission for Women. We have other mechanisms both at State and Central levels.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA: Thank you, Madam Speaker for giving me an opportunity to ask a question on the Swadhar scheme. This scheme is actually derived by the Central Government and it an umbrella scheme for women in difficulties. As per the requirement of this scheme, there is a 30-member Woman Committee that has to be constituted at the district level to address to their needs and also to allocate funds. It is seen from the report given by the Minister that Rs. 1.3 crore have already been allotted to Andhra Pradesh in 2016-17. This has been done, but I believe that none of the MPs in the Parliament know how this scheme is functioning and how its implementation is being done. I would like to know from the Minister, through you, Madam, whether the Ministry has any policy to be evolved to include the MPs in monitoring and effective functioning of this scheme so that we all ensure the end point delivery mechanism. Thank you, Madam.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: We conducted an exercise looking at institutions under us. We only fund Swadhar Grehs, as I said before. However, that does not absolve our responsibility from their running in whatever way. I have again and again requested the Members of Parliament to inspect all the institutions that are run in their own districts, whether for children or for women. We have also said that it should be a part of the DISHA, when you take it up. Now, I am going to write all of you formal letters in which I will list all the institutions for women and children in your own constituencies and ask you to give us a report on them. We have already received a report of 9000 institutions. Some of them are running well; some are not running so well; and some are really running very badly. So, if you could do the checks for us regularly, we would be very grateful.

(Q. 283)

ADV. JOICE GEORGE: Madam, despite collective and concerted efforts, we could not eliminate the transmission of endemic measles. There are two types namely genotype D4 and genotype D8 measles virus strains. This is common in India, but recently circulation of measles genotype B3 was reported from Thiruvananthapuram in Kerala indicating either importation from other countries or unidentified indigenous measles strain.

In these circumstances, studies on genetic and anti-genetic properties of circulating wild type virus will be important.

Madam, my question, through you, to the Minister is whether the Ministry has got any specific proposal or plan to establish mechanism to conduct studies on the genetic and anti-genetic properties of circulating wild type viruses. This is my question.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): अध्यक्ष महोदया, जहां तक मीज़ल्ज़ का सवाल है, तो हमने इसे यूनीवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लिया था। इसमें कई स्टेजेज में काम हुआ है। हमने इसे वर्ष 1985 में यूनीवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के फर्स्ट फेज में जोड़ा था और सैकिंड डोज़ हमने वर्ष 2010 में जोड़ी। फर्स्ट फेज में 9 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चों को दिया जाता था और सैकिंड फेज में 16 महीने से लेकर 24 महीने तक के बच्चों को दिया जाता था। उसके बाद लगभग 14 स्टेट्स ऐसे थे, जहां मीज़ल्ज़ की दृष्टि से इम्यूनिटी लैवल 80 परसेंट से कम थी। उसके लिए हमने एक स्पेशल राउंड लिया और उसके तहत लगभग 12 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। हम 14 स्टेट्स में उन्हें 80 प्लस लैवल पर लेकर आये हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने अभी वर्ष 2017 में मीज़ल्ज़ और रूबेला, दोनों का वैक्सीनेशन सिंगल डोज़ में कर दिया है। We have taken in our Universal Immunisation Programme. यह फाइव स्टेट्स में लांच हुआ था। Now, हम अदर स्टेट्स को भी फेज मैनर में ले रहे हैं। As far as Kerala is concerned, that is also in the second phase. They have said because of Dengue and other things जिसमें वे इन्वाल्व्ड हैं। They want to start this programme in the month of October.

As far as the genetic virus is concerned, that is also the part of the surveillance. So, that is also taken care of. We are going very aggressively on this and we are trying to see to it that measles, rubbela दोनों को हम सब स्टेट्स में रोल आउट कर सकें और बच्चों की इम्यूनिटी लैवल को बढ़ा सकें। हम मीज़ल्ज़ को एलिमिनेट कर सकें।

ADV. JOICE GEORGE: Madam, it is a common phenomenon in our nation that we have migrant labourers. They are moving from one part of the country to the other parts of the country. It is very difficult for us to conduct immunization programmes and all these things.

When there is epidemic outbreak, there is no system in place to track all these things. My question is this. There is a surveillanced couple with genotyping of virus strains that have generated data for tracking and transmission routes.

Madam, I want to know whether the Government has got any plan to establish such a system of surveillance and tracking the route so as to contain all these measles and other epidemic diseases in one region in the event of its outbreak.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: We have a very robust system of surveillance. The National Centre for Disease Control takes care of it. I am happy to share here with the hon. Members that we have been able to even see one case of Ebola and we were able to trace three or four Zika cases. So the surveillance part is very robust which we have and it is a continuous process which is going on. So we have it for this also.

As far as the migrant labourers are concerned, we have got the programme called, Mission Indradhanush where we also see and track and see to it that every child is taken care in regard to immunization.

HON. SPEAKER: Very good.

SHRI M.B. RAJESH: Madam Speaker, the hon. Minister just now stated that the Government has started MR vaccines, that means, Measles-Rubella vaccines. However, the public health experts have been demanding the introduction of

MMR, Mumps-Measles-Rubella vaccines. Instead, the Government has started only MR vaccines.

Secondly, the other issue involved in this is that of coverage. Kerala has achieved 80 per cent coverage, thanks to the excellent and one of the best public health systems in our country. I hope the Minister will take note of the positive things about Kerala also. We have achieved 80 per cent of coverage while the rest of India has achieved only less than 50 per cent of coverage. So my specific question is: will the Government take steps to introduce MMR vaccines? Also, what steps are you proposing to enhance the coverage? Are you going to emulate the Kerala model to enhance the coverage?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, we have a system where we ask the States to showcase their best practices and we leave it to other States to replicate as far as this is concerned. As far as the Government of India is concerned, the Measles-Mumps-Rubella programme is not under consideration because now Mumps is not a case which is considered to be a public concern. It is the NTAG, National Technical Advisory Group which decides about which immunization is to be taken. Kerala has done good. I appreciate it.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is not like this.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: So what I would like to suggest is that when the NTAG is going to say, certainly we will be taking care of it.

DR. KULMANI SAMAL: Hon. Speaker Madam, thank you very much for giving me an opportunity to raise an important supplementary question.

Madam, I have gone through the reply tabled by the hon. Minister. I find that a lot of efforts need to be started by the Central Government soon to eliminate this menace. The health sector in India is very challenging. There are certain other diseases having signs and symptoms just like Measles. Is it not a fact that there are only 11 laboratories in the country that are part of the WHO's Measles Laboratory Network to detect Measles and the laboratory-based confirmation of Measles has begun only in 2015? A huge shortage of laboratories is a very big problem that

should bother us. My question is: would the Government consider opening laboratories in each of the State Capital to detect Measles and make these laboratories functional so that the disease is detected at an early stage?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: It is an on-going process. As and when we feel, we will certainly enhance it. But at this point of time, as far as vaccination is concerned, we are taking care; we are rolling out and we will see in coming times how it works.

(Q. 284)

DR. J. JAYAVARDHAN: Hon. Speaker Madam, the rate of caesarean delivery has increased in both developed and developing countries of the world. As per the WHO, the rate of caesarean delivery should not exceed 10-15 per cent in a country. As with any other surgery, C-section is associated with a short-term and a long-term risk which can extend to many years beyond the current delivery and can affect the health of the woman, her child and future pregnancies. The C-section costs 2-5 times more than that of a normal delivery. Further, primary caesarean births account for an increase in the caesarean rate. What I would like to ask from the hon. Minister is this. What are the effective steps taken by the Government to bring down the rate of C-section surgeries in our country? It is because it is not mentioned in the written reply.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE(SHRI JAGAT PRAKASH NADDA) : Madam, as far as the Government institutions are concerned, we see to it that we have cases of normal delivery as far as possible. We have also made it mandatory that there should be a display of how many caesarean sections have been done. We try to make the patient understand through Information Education and Communication (IEC) as to how they can go for normal delivery and what its benefits are. Through Accredited Social Health Activists (ASHA) workers, we also undertake counseling of pregnant mothers and tell them as to what aspects have to be taken care of.

Yes, I agree with the hon. Member that the number of C-section has increased and that too also mostly in private institutions. There are various reasons for it like personal preference of the patient. There is an increase in personal preference of the patients where they want to go for C-section. Then, there are cases of high risk pregnancy. The time constraint of the pregnant mothers is also an aspect which is leading to C-section deliveries. Mothers are having one or two issues. So, the life is very precious. That way also, the mothers prefer for C-sections. Then, sedentary life of the mother is also one of the reasons which lead

to C-section. So, there are various reasons because of which C-section has increased.

DR. J. JAYAVARDHAN : Hon. Speaker, Madam, what I would like to mention is that a robust primary health care system is the need of the hour to reduce C-section rates. Early detection of complications at the primary health care level and availability of resources, equipment along with availability of doctors at the primary health care will go a long way in reducing the C-section rates immensely.

Even though providing health care is the primary responsibility of the State, the allocation of funds by the Central Government to supplement the efforts of the State Government is grossly inadequate and it does not cater to forming a robust primary health care system. The Central Government has fallen short of its objectives of providing better faculties at primary health care level.

Hon. Speaker, I would like to mention here that the policy initiative taken by our State has been thwarted by the policy initiative taken by the Centre to increase the primary health care system at the State level.

I would also like to mention that the policy initiative of introducing the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) by the Central Government has nullified the policy initiatives of the State to achieve socio-economic objectives. For post graduate courses, the Government of Tamil Nadu gives preference to those, who have served in rural areas with special weightage to those working in hilly and tribal areas. Madam, now the policy and approach of the Central Government has totally nullified the strengthening of the rural health care system in our State.

I would definitely like to ask the hon. Minister whether the policy will be taken back and the admission to post graduate courses will not be taking place through NEET whereby the existing system in the primary health care centers could be strengthened by our State Government.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, there are two questions. One is related to the health care facilities of primary health care centers and the other is

about NEET. The question in respect of NEET is a separate question and that has to be answered separately.

As far as the primary health centers are concerned, the initiatives are taken by the respective States and they have to take care of it. There is no dearth of funds as far as Central Government is concerned. It is an envelope which has been given to a State and it has to see to it where it is going to spend it.

I can assure the hon. Member that whatever the Programme Implementation Plan (PIP) of a State brings forward, we give funds accordingly. So, there is no shortage of funds with the Central Government as far as healthcare is concerned.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT: Thank you, Madam Speaker, for allowing me to ask a supplementary question on a very important issue of caesarean section.

Madam, caesarean sections are carried out on a routine basis in all the private hospitals. The hon. Minister in his reply has mentioned the reasons as to why caesarean sections are done. But, Madam, I would like to highlight some data, which the hon. Minister has given in respect of CGHS empanelled private hospitals, around 55.75 per cent caesarean sections are done.

Madam, I would like to give some data related to my State, that is, Maharashtra. In the Government hospitals, the percentage of caesarean sections done is around 27 per cent whereas in the private hospitals it is around 70 to 80 per cent. One reason for this is, in private hospitals there is something called as the VIP Syndrome. When some VIP goes there, the doctors ask them not to go for normal delivery and to just go for caesarean section.

Second, improper counselling is done by the doctors. They do not inform the patient that even if a mother goes for a normal delivery, she can stay fine and have a normal delivery without any complications. There is always a counselling done in favour of caesarean section.

Madam, for improving the maternal mortality rate, the Government has formed a committee consisting of experts from the fields of gynaecology and

paediatrics and it reviews each and every death of a mother during ante-natal and post-natal period. Through you, I would like to know from the hon. Minister whether we can have a committee formed by the Government for reviewing the cases which are specially done for caesarean section on a regular basis so that it can be ascertained whether there was really an indication for a caesarean section or just for the sake of getting money and exploiting the mothers, the caesarean section was done.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: It is a good suggestion.

HON. SPEAKER: The suggestion is well taken.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, the hon. Member has raised a very pertinent question.

As per the figures stated by the hon. Minister, 55 per cent of CGHS approved private hospitals are doing this thing. Of course, there is an unhealthy practice going on throughout the private hospitals of doing the caesarean surgery. Therefore, there has been a need of actual action taken by the Government of India in this regard. I know that the hon. Minister is a gentleman. He should take sufficient action to address this concern.

Madam, the hon. Minister had promised Kerala of starting an All India Institute of Medical Science in 2014 itself. Already, two years have been over. The people of Kerala are suffering. Only one year is there. So, I want to know whether the Minister is going to announce an AIIMS for Kerala or not.

HON. SPEAKER: The Question is different. Your question is not related.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, the concern of increasing caesarean section is for all of us. What we are doing is that we are initiating the counselling process. That is being done at the level of the hospital and at the level of the doctors. That is what we can do.

Actually, it is an understanding between the doctor and the patient. Every child is precious to her mother. Because of that, whenever the doctor suggests, the patients also go for it.

We are trying to go forward as far as the counselling is concerned and that is the only method.

श्री भोला सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, सीजीएचएस के अंतर्गत निजी पैनल वाले अस्पतालों द्वारा सी-सेक्शन सर्ज़री एवं नॉर्मल डिलीवरी के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 444 और मेरठ में 177 अस्पतालों की संख्या माननीय मंत्री जी के लिखित उत्तर में दी गयी है। यदि देखें, तो यह संख्या अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम नज़र आती है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में विभिन्न स्थानों पर इस सर्ज़री के लिए प्राइवेट अस्पताल पैनल पर हैं या नहीं, यदि हैं, तो उनकी कितनी संख्या है? इसके अलावा ऐसी कितनी डिलीवरियाँ वहाँ पर हुई हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैडम, इस प्रकार की जानकारी हमारे पास नहीं है। माननीय सदस्य अलग से इस संबंध में प्रश्न करेंगे, तो उनको उत्तर दे दूँगा।

(Q. 285)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर काम करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा-रेखा है, वैसे तो वहाँ पर हमारी सरकार ने बहुत-सी व्यवस्थाएँ की हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी नापाक़ हरक़तों से बाज़ नहीं आता है। वह लगातार हमारे सैनिकों की हत्याएँ कर रहा है, हमारी सीमा-चौकियों पर हमले कर रहा है। इसके साथ ही, हमारे नागरिकों पर भी आक्रमण कर रहा है।

वैसे तो, उन्होंने लिखित उत्तर में बताया है कि सीमा को सील करने के लिए बाड़ आदि और आधुनिक उपकरण लगाये जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उसमें कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है तथा उस काम को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ताकि पूरी सीमा सील हो जाए?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, सीमा को सुरक्षित करने का काम एक कंटिन्युअस प्रोसेस है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं रहता है, जो अधूरा हो। बॉर्डर फेन्सिन्ग के अतिरिक्त वहाँ 'एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्सटिकल सिस्टम' भी है, जिसके माध्यम से वहाँ आने वाले घुसपैठियों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए कई टैक्निकल गैजेट्स की भी आवश्यकता होती है, जिन्हें सेना सीमा पर लगाती है। यहाँ उनकी डिटेल्स देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल को सेना ने सुरक्षित किया हुआ है। आज पूरी सीमा और वेस्टर्न बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारी सेना का प्रभाव और डॉमिनेशन है।

माननीय अध्यक्ष : सैकेण्ड सप्लिमेंट्री।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: माननीय अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री ने जो कहा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। उन्होंने बताया है कि वे हमारी सीमाओं पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं और हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, लेकिन आज हमारे सैनिक ऐसी जगहों पर काम करते हैं, जहाँ ज़ीरो तापमान रहता है। हमारे सैनिक ऐसी जगहों पर अपनी बहादुरी प्रदर्शित करते हैं। कारगिल युद्ध में भी उन्होंने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया था और समय-समय पर ऐसी विशम परिस्थितियों और विशम मौसम में रहकर भी वे अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे ये सैनिक जो ज़ीरो तापमान से नीचे रहकर भी काम करते हैं, उनके लिए सरकार ने क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं? हमारे इन सैनिकों को प्रोत्साहन देने के लिए और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए, क्या उनके लिए विशेष भत्ते और विशेष इंक्रीमेन्ट देने के लिए क्या मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री अरुण जेटली : मैडम, जो सैनिक इस प्रकार के कठिन स्थानों में कार्य करते हैं, यह स्वाभाविक है कि वहाँ जितनी भी सुविधाएं दी जा सकें, वे वहाँ की आवश्यकताओं की तुलना में कम रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कठिन मौसम और डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं।

इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सैनिकों के लिए इन विशेष स्थानों में काम करने के लिए विशेष अलाउंसिज़ होते हैं, जो उन्हें वेतन के अतिरिक्त इंसानों की सेवा करने के लिए मिलते हैं। हाल ही में सातवें वेतन आयोग ने उन अलाउंसिज़ को अनाउंस किया था। उन अलाउंसिज़ पर पुर्नविचार करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। जो सैनिक सियाचिन ग्लेशियर में काम करते हैं, उनके लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में सरकार ने थोड़ी और बढ़ोत्तरी की है, जिसकी घोषणा सरकार ने कुछ दिन पहले ही की है।

माननीय अध्यक्ष : श्री रवनीत सिंह, शॉर्ट क्वेश्चन।

श्री रवनीत सिंह: मैडम, आपका धन्यवाद।

मैडम, मैं खास तौर पर पंजाब की बात करना चाहता हूँ। मंत्री जी भी इस बात को जानते हैं। वहाँ ड्रग्स का इन्फ्लो बहुत ज्यादा है। वहाँ कांग्रेस गवर्न्मेन्ट ने बहुत काम किया है। वहाँ की पिछली सरकार में बहुत खामियाँ थीं। एन.डी.ए. गवर्न्मेन्ट के मेन मेनिफेस्टो में 'बॉर्डर मॉडर्नाइज़ेशन' का वादा था। वहाँ बहुत बड़े रिवराइन्स और दरिया हैं। वहाँ 'अनमैन्ड एरियल व्हीकल' की जरूरत है। जब हमारे प्रधान मंत्री इज़रायल गए थे, तो वे यह बोल के गए थे कि वे वहाँ से ये सारी चीज़ें लाएंगे। वहाँ पर लेज़र टैक्नोलॉजी की लेज़र वॉल्स की भी जरूरत है।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन दोनों चीज़ों के बारे में सरकार कोई विचार करेगी, क्योंकि ये दोनों ही बातें, खास तौर पर वहाँ ड्रग्स रोकने की बात वहाँ के नौजवानों से संबंधित है। पठानकोट अटैक भी इन चीज़ों की वजह से ही हुआ था।

मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इन दोनों चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएं।

श्री अरुण जेटली : मैडम, मैंने पहले भी कहा है कि इस संबंध में जो स्पेसिफिक इंस्ट्रुमेंट्स वहाँ हैं, उनकी विशेष जानकारी यहाँ देना उपयुक्त नहीं है। जितनी भी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशल बॉर्डस हैं, वहाँ रडार्स, सेंसर्स, थर्मल इमेज़िंग के द्वारा उनकी सर्विलेन्स की आवश्यकता होती है। इसको इस सरकार या पिछली सरकार की दलगत राजनीति के रूप में न देखें। देश में जो भी सरकार रहती है, वह इसके लिए दिन-प्रतिदिन व्यवस्थाएं बढ़ाती चली जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में हमारी सेना ने न केवल पंजाब बल्कि जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में भी जितने अधिक इन्फिल्ट्रेशंस रोकने में सफलता प्राप्त की है, उसमें इन सबका योगदान है।

श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, मेरा प्रश्न संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए होगा और ज्यादा ब्योरा वह नहीं देना चाहें और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन भारत-पाकिस्तान सीमा पर पिछले एक साल में कितने इनक्र्शन और एक्सकर्शन हुए हैं और उनमें हताहत होने वालों की संख्या कितनी है? सैनिक, अर्द्ध-सैनिक और सीविलयन्स की संख्या पिछले एक साल में कितनी थी, यह मैं जानना चाहता हूं।

12.00 hours

श्री अरुण जेटली : महोदया, दो प्रकार के एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे हैं, जिनको आर्मी गार्ड करती है और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, जिनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सिस गार्ड करती हैं। इन दोनों का अलग-अलग कार्यक्षेत्र होता है। आप यह समझ लीजिए कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वह आर्मी के तहत है, कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर का हिस्सा आर्मी के पास होता है, बाकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गार्ड करती है। वर्ष 2016 में सीज़फायर वॉयलेशन आर्मी के क्षेत्र में लगभग 228 हुए और बीएसएफ नियंत्रित क्षेत्र में 221 के करीब हुए थे। जिसमें आठ आर्मी की केजुअल्टीज़ हुईं। मेरे पास आर्मी की केज़ुअल्टीज़ का डेटा है। इस साल पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर इंफल्ट्रेशन बढ़ाने की काफी कोशिशें हुई हैं और यह संख्या 1 अगस्त, 2017 तक 285 हो चुकी है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस सबमें दूसरी साइड से इंफिल्ट्रेट करने की वजह से भी केज़ुल्टीज़ हुई हैं, इस वजह से भी रिकार्ड हाई है।

HON. SPEAKER: Question Hour is over.

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from some Members on different issues. No doubt, they are important. But they can be raised through other opportunities. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

12.03 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, मुम्बई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, मुम्बई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT-7350/16/17)

(2) भारतीय महिला बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(Placed in Library, See No. LT-7351/16/17)

(3) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसी धारकों के हित का संरक्षण) विनियम, 2017 जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआरडीएआई/रेग./8/145/2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT-7352/16/17)

(4) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(1) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 893(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 894(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 895(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 896(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 897(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, अहमदाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 898(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, अहमदाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 899(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 900(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) ऋण वसूली अपील अधिकरण, औरंगाबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 901(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, बेंगलुरू (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 902(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, चंडीगढ़ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 903(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, चंडीगढ़ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 904(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 905(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 906(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) ऋण वसूली अपील अधिकरण-तीन, चेन्नई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 907(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(16) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोयम्बटूर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 908(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(17) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कटक (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 909(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(18) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 910(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(19) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 911(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(20) ऋण वसूली अपील अधिकरण-तीन, दिल्ली (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 912(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(21) ऋण वसूली अपील अधिकरण, एर्णाकुलम (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 913(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(22) ऋण वसूली अपील अधिकरण, गुवाहाटी (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 914(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(23) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, हैदराबाद (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 915(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(24) ऋण वसूली अपील अधिकरण, जबलपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 916(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(25) ऋण वसूली अपील अधिकरण, जयपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 917(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(26) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 918(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(27) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 919(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(28) ऋण वसूली अपील अधिकरण-तीन, कोलकाता (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 920(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(29) ऋण वसूली अपील अधिकरण, लखनऊ (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 921(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(30) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मदुराई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 922(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(31) ऋण वसूली अपील अधिकरण-एक, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 923(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(32) ऋण वसूली अपील अधिकरण-दो, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 924(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(33) ऋण वसूली अपील अधिकरण-तीन, मुंबई (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 925(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(34) ऋण वसूली अपील अधिकरण, नागपुर (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 926(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(35) ऋण वसूली अपील अधिकरण, पटना (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 927(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(36) ऋण वसूली अपील अधिकरण, पुणे (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 928(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(37) ऋण वसूली अपील अधिकरण, राँची (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 929(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(38) ऋण वसूली अपील अधिकरण, विशाखापत्तनम (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 930(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. LT-7353/16/17)

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.722(अ) जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित वस्तुओं का पुनर्निर्यात (सीमा शुल्क की खामी) संशोधन नियम, 2017 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.727(अ) जो 29 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.853(अ) जो 10 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.881(अ) जो 14 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि.762(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 16 सितम्बर, 1993 की अधिसूचना संख्या 171/1993-सी.शु. को निरस्त करना है एवं उत्तरवर्ती रूप से उपहार आयातों पर कोई छूट नहीं होगी और उत्तरवर्ती रूप से सदाशयतापूर्ण उपहारों पर 28 प्रतिशत आईजीएसटी लगेगा एवं लागू होने वाला बुनियादी सीमा शुल्क लगेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.763(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या 151/1982-सी.शु. को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.764(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा स्पेसीमेन, माडल्स, वाल पिक्चर्स और डायग्राम पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.765(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सचल तस्वीरों, संगीत, गेमिंग सॉफ्टवेयर पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.766(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दावा नहीं किए गए डाक आर्टकिल्स के पुनआयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है एवं इसे समेकित कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.767(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 100 वर्ष से अधिक पुरानी कलाकृतियों और पुस्तकों पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.768(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रक्षा इकाइयों द्वारा जीते गए चैलेंज कप और ट्राफियों पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है एवं इसे समेकित कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.769(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा टैक्स और लेवल्स या मरम्मत और लौटाने के लिए विदेशी मूल के आयातित छपे हुए थैलों पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.770(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इंडियन एयरलाइन्स, यूनाइटेड अरब एयरलाइन्स और भारतीय वायुसेना द्वारा वायुयानों के टैंकों में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर बुनियादी सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क से मिली छूट

को जारी रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.771(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति द्वारा आयातों पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है एवं इसे एकीकृत कर एवं माल तथा सेवा प्रतिकर उपकर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.772(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बलों से जुड़े आयातों पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है एवं इसे एकीकृत कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.773(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वायुयानों के इंजनों और कलपुर्जों के पुनआयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है एवं इसे एकीकृत कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.774(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जनवरी, 1957 की अधिसूचना सं. 3/57-सी.शु. में संशोधन किया गया है ताकि राजनायिकों द्वारा आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखी जा सके एवं इसे एकीकृत कर एवं माल तथा सेवा प्रतिकर उपकर से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि.775(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भूटान और नेपाल से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.776(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए चैलेंज कप, ट्राफियों और पद को एवं पुरस्कारों आदि पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है एवं इसे समेकित कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.777(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 14 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 102/2007, 8 जनरवरी, 1999 की 4/99 और 30 सितम्बर, 1994 की 172/1994 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.778(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय रक्षा, सुरक्षा, खिलाड़ियों आदि द्वारा पुनआयात, द्वपक्षीय/बहुपक्षीय समझौतों, आयातों से जुड़ी कतिपय छूट वाली अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि.779(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति, वारंटी के अंतर्गत निःशुल्क आपूर्ति की गई वस्तुओं, निःशुल्क उपहारों, परोपकारी संगठनों आदि द्वारा अभिदान से जुड़ी विशिष्ट छूट वाली अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.780(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 1 जुलाई, 2017 को या उसके पश्चात् शुल्क वापसी, शुल्क में छूट या बाण्ड के अधीन निर्यातित वस्तुओं के पुनआयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा गया है एवं इसे एकीकृत कर और माल एवं सेवा प्रतिकर उपकर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.781(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय अधीसूचना सं. 94/1996-सी.शु. का अतिक्रमण करना है ताकि 30 जून, 2017 को या उसके पश्चात् शुल्क वापसी, शुल्क में छूट या बाण्ड के अधीन निर्यातित वस्तुओं के पुनआयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखा जा सके एवं इसे एकीकृत कर और माल एवं सेवा प्रतिकर उपकर से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि.782(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय शुल्क वापसी, शुल्क में छूट या बाण्ड के अधीन निर्यातित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत वस्तुओं के पुनआयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना है एवं इसे अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि.783(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय इंडियन एयरलाइन्स, द्वारा कैटरिंग केबिन इक्यूपमेंट के पुनआयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से मिली छूट को जारी रखना और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि.784(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत शामिल वस्तुओं पर सैड से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि.785(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 17.03.2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.शु. का अतिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्तीस) सा.का.नि.786(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय अधिसूचना सं. 21/2012-सी.शु. का अतिक्रमण करना है ताकि परिवहन क्षेत्र में उपयोग हेतु पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैसों और ईंधनों एवं सीएनजी पर विशेष अतिरिक्त शुल्क शून्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि.787(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, के अध्याय 27 की मदों पर बुनियादी सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क की प्रभावी दर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाना जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि.788(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एलएनजी एवं प्राकृतिक गैस पर विशेष अतिरिक्त शुल्क जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि.789(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जिसका आशय वस्तुओं के आयात पर प्रतिकर उपकर एवं आईजीएसटी पर शिक्षा उपकर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.का.नि.790(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वस्तुओं के आयात पर प्रतिकर उपकर एवं आईजीएसटी पर सैकेंडरी और उच्चतर शिक्षा उपकर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT-7354/16/17)

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 755(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित दस अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 931(अ) जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पूर्ववर्ती केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत क्षेत्र आधारित छूट से जुड़ी छह जारी अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 932(अ) जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पूर्ववर्ती केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3क के अंतर्गत जारी पांच केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गैर टैरिफ) अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 791(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय माल और सेवा कर में वस्तुओं को छूट प्रदान करने वाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) सा.का.नि. 792(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके आधिकारिक उपयोग की उत्पाद शुल्क युक्त वस्तुओं की आपूर्ति से छूट देने के लिए अधिसूचना सं. 108/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 793(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय पेट्रोल, ईथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मिश्रित एचएसडी, जैव डीजल एविएशन टर्बाइन ईंधन, एलएनजी और प्राकृतिक गैस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

की प्रभावी दर निर्धारित करने के लिए अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 794(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 30 जून, 2017 को या इसके पूर्व विनिर्मित वस्तुओं परंतु 1 जुलाई, 2017 के पूर्व उत्पादन कारखाने से नहीं भेजी गई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 795(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय भारतीय नौ सेना और तट रक्षक को वैसेल पर उपभोग के लिए भंडार के रूप में आपूर्ति किए गए सिगरेट और पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट जारी रखने के लिए अधिसूचना सं. 64/95-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अतिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 796(अ) जो 30 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 क चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को ही अधीसूचना सं. 52/2002-के.उ.शु., 8/2003-के.उ.शु., 3/2006-के.उ.शु. एवं 29/2008-के.उ.शु. में प्रदत्त छूटों को सीमित करने के लिए इन अधिसूचनाओं में संशोधन करना तथा अधीसूचना सं. 38/2004-के.उ.शु., 62/2008-के.उ.शु. और 21/2009-के.उ.शु. में विनिर्दिष्ट स्थानों पर ''उपयुक्त उत्पाद शुल्कों'' शब्दों को ''उपयुक्त केनद्रीय कर, राज्यकर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर '' शब्दों से प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 823(अ) जो 3 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 13 मई, 2002 की अधिसूचना सं. 28/2002-केउशु में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT-7355/16/17)

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.954(अ) जो 26 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्तूबूर, 2016 की अधिसूचना सं. 131/2016-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निपटान आयोग (संशोधन) प्रक्रिया, 2017 जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 447(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT-7356/16/17)

(8)प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.938(अ) जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय किसी गैर-प्रदायकर्ता से ऐसे व्यक्ति, जो पुराने सामानों की खरीद और विक्रय का काम करता हो और ऐसे पुराने सामान पर केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 32 के उपनियम(5) के अंतर्गत यथाअवधारित विक्रय और खरीद मूल्य के बीच के अंदर की राशि पर माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर का संदाय करता हो, के द्वारा प्राप्त पुराने माल की अंतरराज्यीय प्रदाय पर माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर से पूरी तरह छूट प्रदान करनी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT-7357/16/17)

(9) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 878(अ) जो 13 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना सं. 36/2012-सी.शु.,(एडीडी) के अंतर्गत थाईलैंड और चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स (फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बाल्स को छोड़कर)'' के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को बढ़ाना है और उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा(5) के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाने की अनुशंसा की थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT-7358/16/17)

(10) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा(4) के अंतर्गत सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जो 22 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.625(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT-7359/16/17)

(11) अधिसूचना सं. सा.का.नि.647(अ) जो 27 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय यह विहित करना है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में रजिस्ट्रीकृत कोई

पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 75 लाख से अनधिक था, सम्मिश्रण उद्ग्रहण का पात्र होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में रजिस्ट्रीकृत कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 50 लाख से अनधिक था, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 की उप-धारा(1) के अंतर्गत सम्मिश्रण उद्ग्रहण का पात्र होगा। इसके अलावा अधिसूचना का आशय यह उपबंध करना है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति निम्न माल का विनिर्माण करता है तो वह सम्मिश्रण उद्ग्रहण का विकल्प चुनने का पात्र नहीं होगा (एक) आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे कोको युक्त हो या नहीं (दो) पान मसाला (तीन) सभी माल अर्थात् तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प।

(Placed in Library, See No. LT-7360/16/17)

(12) अधिसूचना सं. सा.का.नि.648(अ) जो 27 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय यह विहित करना है कि कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 75 लाख से अनधिक था, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 की उप-धारा(1) के अंतर्गत सम्मिश्रण उद्ग्रहण का पात्र होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। इसके अलावा अधिसूचना का आशय यह उपबंध करना है कि संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति निम्न माल का विनिर्माण करता है तो वह सम्मिश्रण उद्ग्रहण का विकल्प चुनने का पात्र नहीं होगा (एक) आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे कोको युक्त हो या नहीं (दो) पान मसाला (तीन) सभी माल अर्थात् तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प।

(Placed in Library, See No. LT-7361/16/17)

(13) धन-शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) दूसरा संशोधन नियम, 2017 जो 1 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 538(अ) में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) संशोधन नियम, 2017 जो 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 347(अ) में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. LT-7362/16/17)

(14) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT-7363/16/17)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 30 of 2017) (Department of Revenue-Direct Tax)-Payment of tax by certain companies under special provisions of section 115JB.

[Placed in Library, See No. LT 7364/16/17]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 31 of 2017) (Indirect Taxes-Service Tax)-Levy and Collection of Service Tax on Entertainment Sector, Department of Revenue for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7365/16/17]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2016-2017.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7366/16/17]

(3) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Third Amendment) Regulations, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/004 in Gazette of India dated 29th May, 2017 under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 7367/16/17]

(4) A copy of the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Amendment) Regulations, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.635(E) in Gazette of India dated 23rd June, 2017 under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999.

[Placed in Library, See No. LT 7368/16/17]

(5) A copy of the Reserve Bank of India Monetary Policy Committee and Monetary Policy Process Regulations, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. M.P.D.P.M.D.No.17/02.02.015/17-18 in Gazette of India dated 20th July, 2017 under sub-section (4) of Section 54 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 7369/16/17]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 25 of the Coinage Act, 2011:-

(i) The Coinage of One Hundred Rupees and Ten Rupees Coins to mark the occasion of Birth Centenary Commemoration of Swami Chinmayananda Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.335(E) in Gazette of India dated 30th April, 2015.

(ii) The Coinage of One Hundred Fifty Rupees and Ten Rupees Coins to mark the occasion of 150th Birth Anniversary of Lala Lajpat Rai Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.381(E) in Gazette of India dated 13th May, 2015.

(iii) The Coinage of One Hundred Fifty Rupees and Ten Rupees Coins to commemorate the occasion of "International Day of Yoga" Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.487(E) in Gazette of India dated 12th June, 2015.

(iv) The Coinage of One Hundred Twenty Five Rupees and Ten Rupees Coins to commemorate the occasion of 125th Birth Anniversary of Dr. S. Radhakrishnan Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.512(E) in Gazette of India dated 25th June, 2015.

(v) The Coinage of Fifty Rupees and Five Rupees Coins to Commemrate the occasion of "Golden Jubilee of Indo Pak War 1965" Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.667(E) in Gazette of India dated 28th August, 2015.

(vi) The Coinage of Five Hundred Rupees and Ten Rupees coins to commemorate the occasion of 3rd India-Africa Forum Summit Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.798(E) in Gazette of India dated 21st October, 2015.

(vii) The Coinage of One Hundred Twenty Five Rupees and Ten Rupees coins to commemorate the occasion of 125th Birth Anniversary of

Dr. B. R. Ambedkar Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.815(E) in Gazette of India dated 29th October, 2015.

(viii) The Coinage of One Hundred and Ten Rupees coins to commemorate the occasion of 475th Birth Anniversary of Maharana Pratap Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.947(E) in Gazette of India dated 9th December, 2015.

(ix) The Coinage of Two Hundred Rupees and Ten Rupees Coins to commemorate the occasion of 200th Birth Anniversary of Tatya Tope Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.816(E) in Gazette of India dated 29th October, 2015.

(x) The Coinage of Five Hundred Rupees and Ten Rupees Coins to commemorate the occasion of "500th Anniversary of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu's Coming to Vrindavan Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.116(E) in Gazette of India dated 28th January, 2016.

(xi) The Coinage of One Hundred Fifty Rupees and Five Rupees Coins to commemorate the occasion of 150th Birth Anniversary of Allahabad High Court Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.191(E) in Gazette of India dated 24th February, 2016.

(xii) The Coinage of One Hundred Rupees and Five Rupees Coins to commemorate the Occasion of "Biju Patnaik Birth Centenary" Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.172(E) in Gazette of India dated 17th February, 2016.

(xiii) The Coinage (issue of commemorative coins on the occasion of one hundred twenty-fifth Year of National Archives of India) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.197(E) in Gazette of India dated 26th February, 2016.

(xiv) The Coinage (Issue of Commemorative Coins on the occasion of centenary celebration of Banaras Hindu University) Rules, 2016

published in Notification No. G.S.R.292(E) in Gazette of India dated 11th March, 2016.

(xv) The Coinage (Issue of Commemorative Coins on the occasion of "University of Mysore Centenary Celebrations") Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.825(E) in Gazette of India dated 26th August, 2016.

(xvi) The Coinage (Issue of Commemorative Coins on the occasion of Birth Centenary of Pandit Deendayal Upadhyaya) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.836(E) in Gazette of India dated 31st August, 2016.

(xvii) The Printing of One Rupee Currency Notes Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.192(E) in Gazette of India dated 24th February, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7370/16/17]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

(i) The Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.307(E) in Gazette of India dated 30th March, 2017.

(ii) The Companies (Meetings of Board and its Powers) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.309(E) in Gazette of India dated 30th March, 2017.

(iii) The Companies (Registration of Charges) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.339(E) in Gazette of India dated 10th April, 2017.

(iv) The Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.355(E) in Gazette of India dated 13th April, 2017.

(v) The Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.368(E) in Gazette of India dated 13th April, 2017.

(vi) The Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.454(E) in Gazette of India dated 11th May, 2017.

(vii) The Companies (Audit and Auditors) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.621(E) in Gazette of India dated 22nd June, 2017.

(viii) The Companies (Transfer of Pending Proceedings) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.732(E) in Gazette of India dated 30th June, 2017.

(ix) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.839(E) in Gazette of India dated 6th July, 2017.

(x) The National Company Law Tribunal (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.840(E) in Gazette of India dated 6th July, 2017.

(9) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

[Placed in Library, See No. LT 7371/16/17]

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 467 of the Companies Act, 2013:-

(i) G.S.R.308(E) published in Gazette of India dated 30th March, 2017, making certain amendments to Schedule III of the Companies Act, 2013.

(ii) S.O.2113(E) published in Gazette of India dated 6th July, 2017 making certain amendments to Schedule IV of the Companies Act, 2013.

(11) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) of (10) above.

[Placed in Library, See No. LT 7372/16/17]

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 462 of the Companies Act, 2013:-

(i) G.S.R.582(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2017 making certain amendments in the Notification No. G.S.R.463(E) dated 5th June, 2015.

(ii) G.S.R.583(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2017 making certain amendments in the Notification No. G.S.R.464(E) dated 5th June, 2015, together with a corrigendum thereto published in Notification No. S.O.2218(E) dated 13th July, 2017.

(iii) G.S.R.584(E) published in Gazette of India dated 13th June, 2017 making certain amendments in the Notification No. G.S.R.466(E) dated 5th June, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 7373/16/17]

(13) A copy of the Companies (Removal of Difficulties) Order, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.2042(E) in Gazette of India dated 30th June, 2017 under sub-section (2) of Section 470 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 7374/16/17]

(14) A copy of the Statement (Hindi and English versions) of the Market Borrowings by Central Government during 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 7375/16/17]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं -

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7376/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI C. R. CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 18 of 2017)-Compliance Audit on Food Corporation India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, for the year ended March, 2016 under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 7377/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the Mazagon Dock Shipbuilders Limited and the Ministry of Defence for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7378/16/17]

(2) Memorandum of Understanding between the Goa Shipyard Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7379/16/17]

(3) Memorandum of Understanding between the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and the Ministry of Defence for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7380/16/17]

(4) Memorandum of Understanding between the Bharat Dynamics Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 7381/16/17]

12.03 ½ hours

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and DIPAM, Ministry of Finance*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, Speaker, I rise to lay a statement regarding Status of Implementation of the recommendations contained in the 46th Report of the Standing Committee on Finance for Demands for Grants 2017-18 pertaining to the Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, DIPAM in the Ministry of Finance.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7382/16/17.

12.04 hours

(ii) Organization of India International Science Festival (IISF)

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF EARTH SCIENCES AND MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): Madam, Speaker and hon. Members, I stand before the House to present about an upcoming momentous programme of the Ministry of Science and Technology and Earth Sciences. The India International Science Festival, popularly known as `IISF', is all set to enter its third edition in October 2017. This festival of sciences is organized by the Ministry in association with Vijnana Bharati (VIBHA). The first IISF was held at IIT, Delhi and the second edition was held at CSIR – National Physical Laboratory, New Delhi. Both were successful events and my Ministry had succeeded in its objective of `propagation of science to the general masses'.

Madam Speaker, the India International Science Festival is a serious attempt to inculcate scientific temper in the general public, particularly through the participation of the youth and children, to fast-track India's march towards technological self-reliance and scientific advancement. This festival of science highlights the Government flagship programmes such as "Swachh Bharat Abhiyan", Swasth Bharat Abhiyan", "Make in India", "Digital India", Smart Villages" "Smart Cities" etc.

In the first edition, we achieved the 'Guinness world record for the largest science practical session' which is now inscribed in India's name. IISF 2015 also provided a vibrant platform to young students, scientists and technocrats from all across India for exchange of scientific knowledge and ideas.

In the second edition of the 'Festival of Science' in 2016, several events like the Young Scientists Conclave, DST – INSPIRE National Camp, Science Film Festival, NGO meet, Industry-Academia Interaction were held at National Physical Laboratory, Delhi. A footfall of over 5 lakh people were recorded at the

IISF 2016 with active participation of over 10,000 delegates from R&D institutions and science organisations.

HON. SPEAKER: You can lay it on the Table of the House.

DR. HARSH VARDHAN: Madam, I beg to lay the rest of the *Statement on the Table of the House.

---

* The rest of the statement laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7383/16/17.

12.07 hours

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): With your permission, Madam, I rise to *lay a statement regarding Government Business for the remaining part of the Session. It will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:-

   (It contains consideration and passing of (i) The Indian Institute of Petroleum and Energy (IIPE) Bill, 2017 and (ii) the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Amendment Bill, 2017)

2. Consideration and passing of the following Bills: -
   (a) The State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2017.
   (b) The Repealing and Amending Bill, 2017.
   (c) The Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017.
   (d) The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017.
   (e) The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2017.

* Laid on the Table

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया जी, धन्यवाद। कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए :-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा हॉकी प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया गया है। वहां पर इनडोर गेम्स के लिए हॉल भी बनवाए गए तथा मैदान भी है परंतु बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है। अतः देश के सभी क्रीड़ा स्थलों के साथ ही टीकमगढ़ में भी खिलाड़ियों के लिए छात्रावास भवन निर्माण कराने हेतु खेल प्राधिकरण से राशि दिलाए जाने की आवश्यकता है।

2. मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स उपलब्ध है। खनन का कार्य केवल निजी क्षेत्र के सम्पन्न लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। ग्रेनाईट यहां से बड़ी मात्रा में कांडला बंदरगाह से होकर विदेशों में जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा वहां प्लांट लगाकर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Madam, I would like to submit the following two matters to be included in the list of business for the coming week:

1) Attention needed for Non-Corporate Sector in our economy: It is observed that the fuel to our high economic growth especially after the 1991 reforms came from the Unincorporated Sector businesses (Mostly partnership and Proprietorship). In 2012, this sector contributed about 45 per cent of National Income whereas the corporate sector contributes only about 18-21 per cent. These P&P firms are counted under household for savings data and it is observed that households contribute 60-65 per cent of savings in our economy whereas their share of formal credit has declined from 58 per cent in 1990 to 36 per cent in 2012. For the corporate sector which contributes lesser to savings, the share of credit has increased. There is, therefore, a mismatch in sectoral credit allocation and economic planning in our country.

2) Need to revise the criteria for IGNDP: The disability pensions in India play a significant role in ensuring social security for the most vulnerable in the society: The Divyang. In this light, it has been observed that the Indira Gandhi Disability Pension (IGNDP) has some strict eligibility criteria like 18 years and above, income below poverty line, minimum 80 per cent disability and the amount paid if a beneficiary is eligible under all these criteria is Rs.300. These stringent criteria especially the 80 per cent disability one, excludes the vst majority of Divyangs and, therefore, needs immediate change. There are

best practices like the criteria under Madhu Babu Pension Yojana of Odisha State, in which everyone above the age of 5 with a disability of minimum 40 per cent is eligible.

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में मेरे दो विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. मेरे द्वारा गोद लिए गये 'सांसद आदर्श ग्राम पंचायत-मल्हीपुर,' थाना-चेनारी, जिला-रोहतास (सासाराम) बिहार में इस क्षेत्र के नागरिकों के सर्वांगीण विकास एवं मूलभूत सेवाओं को विकसित करने हेतु 'प्लास्टिक पार्क' स्थापित किया जाए, जिससे इस क्षेत्र के बेरोजगार युवक-युवतियां व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्म निर्भर हो सकें। यहां पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन विभाग की बेकार पड़ी भूमि भरपूर मात्रा में उपलब्ध है।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम (बिहार) में योग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर सभी विद्यालय/महाविद्यालयों में योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। योग गुरू बाबा रामदेव जी एवं माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'योग दिवस' का शुभारम्भ कर देश को शिखर पर पहुंचाया, जिसके लिए हम सब आभारी हैं। योग के निरंतर अभ्यास से शरीर ही नहीं बल्कि मन एवं मस्तिक भी स्वस्थ रहता है, जिससे मैं स्वयं लाभान्वित हूं। योग भावनात्मक और अध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ रहने की जीवन शैली है।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदियां यमुना, चम्बल, क्वारी, सिंधु और पहुज के जनपद जालौन उ.प्र. में संगम स्थान पंचनदा पर बांध निर्माण को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने का कट करें।

कोंच-जालौन-उरई रेल मार्ग परियोजना जिसका सर्वे अभी हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे द्वारा पूरा कर लिया गया है, इस परियोजना को मंत्रालय द्वारा स्वीकृत करने को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): The declaration of a Railway Coaching Yard at Nemom in Pallichal Gram Panchayat in Attingal Lok Sabha Constituency is yet to be fulfilled. Railway traffic congestion is increasing day by day in the Thiruvananthapuram Division. Hence, I request for the formation of a Railway Zone having its headquarters at Kerala. There is a long pending demand of the people in the Chirayinkeezhu for a two-minute stoppage for Parasuram Express.

113 years old Kadakkavur Railway station should be declared as a Heritage Station and stoppages for more trains may be allowed at Varkala Sivagiri Station should be provided.

The Attingal town is the centre of my Lok Sabha Constituency and is one of the oldest ones in the whole State of Kerala having its history and tradition from the pre-Independence era. This ever growing urban area is experiencing severe traffic jams and congestions on the NH-47. At present, the Attingal Municipality is trying its best for widening the portion of the NH-47 which passes through the town with people's participation. The construction of a by-pass for the existing NH at Attingal is also envisaged by the NHAI simultaneously. So, I request you to be kind enough to take urgent steps for the construction of the said Attingal by-pass in this stretch of NH-47.

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): महोदया, निम्नलिखित दो विषयों पर अगले सप्ताह की कार्यसूची में सबमिशन के अंतर्गत मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

(1) मेरा छोटा उदयपुर लोक सभा संसदीय मत क्षेत्र आदिवासी जनसमुदाय एवं पहाड़ी पिछड़ा क्षेत्र है। छोटा उदयपुर जिला के कवांट तहसील के ''पडवानी,'' ''कोटंबी,'' नसवाडी तहसील के ''केवडी-घारसीमेल'' बोडेली तहसील के ''झंड हनुमान'' एरिया में बीएसएनएल टेलीफोन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा न होने की वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द यह सुविधा देने का प्रबंध किया जाए।

(2) मेरा लोक सभा संसदीय मत क्षेत्र आदिवासी जनसमुदाय एवं पहाड़ी पिछड़ा क्षेत्र है और देश की सबसे बड़ी योजना सरदार सरोवर नर्मदा योजना का मूल स्थान मेरे संसदीय मत क्षेत्र नर्मदा जिले के नांदोद तहसील के ''उमरवा'', ''नावरा,'' ''राजपरा,'' ''खुटा-आबा'', ''बोरी,'' गरुडेश्वर तालुका का ''साकवां,'' ''भीलसी'' एरिया में मोबाइल ब्रोडबैंड इंटरनेट की सुविधा न मिलने के कारण जैसे कि 108 और इमरजेन्सी आपातकालीन सेवा में आम जनता को परेशानी हो रही है और हमारी जनता नाराजगी महसूस कर रही है।

इसको मद्देनजर रखकर हम टेलीफोन और ब्रोडबैंड की सुविधा शुरू करना चाहते हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की ओर से कोई ठोस कदम उठाये जाने के लिए मैं निवेदन एवं अनुरोध करता हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करते हुए चर्चा कराने की कृपा की जाए।

(1.) धनबाद, कतरास, चंद्रपुरा रेल लाइन विगत दो माह से बंद होने के कारण भारी संख्या में आम जनता को कठिनाई हो रही है। विभिन्न संगठन एवं आम जनता विगत दो माह से लगातार आंदोलनरत है। इसलिए भारत सरकार से माँग करता हूँ कि धनबाद मण्डल के अंतर्गत उक्त रेल लाइन को अविलंब चालू किया जाए।

(2.) कोल इण्डिया की अनुषांगिक कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का कथारा क्षेत्र के अंतर्गत कथारा बाशरी एवं स्वांग बाशरी में वर्षों से स्थायी प्रकृति के कार्य में लगातार कार्यरत सैकड़ों ठेका श्रमिकों की अचानक छँटनी कर दी गयी है। उनका बकाया वेतन का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। अतएव उक्त श्रमिकों को पुनः नियोजित किया जाए एवं उनके बकाया वेतन का भुगतान कराने हेतु यथोचित कार्रवाई की जाए।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित विषय आगामी सप्ताह की कार्य सूची में शामिल करने का कष्ट करें।

(1.) प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य लोगों से सस्ते दामों पर दवाएं उपलब्ध कराना है। उक्त औषधि केन्द्रों को लाइसेंस व स्थान उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकारों व संबंधित अधिकारियों व विभागों को स्पष्ट व व्यावहारिक निर्देश दिए जाएं। ...*

माननीय अध्यक्ष : श्री अश्विनी कुमार चौबे - उपस्थित नहीं।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में उक्त विषय का समावेश किया जाए।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन के जीर्णोद्धार के लिए गुजरात सरकार ने छह करोड़ रूपये की धनराशी आवंटित की है। उक्त फाउंडेशन के लिए केंद्र सरकार भी इतनी ही धनराशी आवंटित करे, जिससे उक्त फाउंडेशन में स्थित लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम व रिसर्च सेंटर को वातानुकूलित एवं अन्य सुविधाओं से सुशोभित किया जाए।

* Not recorded.

12.16 hours

MOTION RE: ELECTION OF TWO MEMBERS TO CENTRAL ADVISORY BOARD ON DISABILTY

HON. SPEAKER: Now we take up Item No. 10. The hon. Minister Shri Thawar Chand Gehlot to move the motion.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

" निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा(2) के खण्ड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय निःशक्तता सलाहकार बोर्ड के सदस्यो के रूप में सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। "

HON. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (c) of sub-section (2) of Section 60 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Central Advisory Board on Disability for the period till they cease to be members of the House, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

The motion was adopted.

12.17 hours

MOTION RE: ELECTION OF FOUR MEMBERS TO CENTRAL SILK BOARD

HON. SPEAKER: Now we take up Item No. 11. The hon. Minister Shrimati Smriti Zubin Irani to move the motion.

THE MINISTER OF TEXTILES AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): I beg to move:

> "That in pursuance of clause (c) of sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, four members from amongst themselves to serve as members of the Central Silk Board for the period till they cease to be members of the House, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (c) of sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, four members from amongst themselves to serve as members of the Central Silk Board for the period till they cease to be members of the House, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

The motion was adopted.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Hon. Speaker Madam, I would request you to take up the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill 2017 immediately. … (*Interruptions*) It is an important Bill. I would also request my friends from the Opposition that the Zero Hour can be taken up later. … (*Interruptions*) Let us first consider and pass the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill 2017 Bill and we can take up Zero Hour later.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : बिल ले सकते हैं। यह बिल कराकर इसके तुरन्त बाद जीरो ऑवर ले लेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है, सभी लोग चाहेंगे कि जीरो भी जल्दी होना चाहिए। पहले बिल करा लेते हैं और उसके तुरन्त बाद जीरो ऑवर ले लेंगे। उसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल होगा।

जितेन्द्र रेड्डी जी, आपको क्या कहना है।

…(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, we would not have time for 'Zero Hour' later since we have to take up Private Members' Business at 3.30 p.m. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको क्या कहना है, मैं इनके बाद आपको मौका देती हूँ।

…(व्यवधान)

12.20 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Need for exemption from GST on ongoing Government sponsored schemes

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, thank you very much for giving me this opportunity today. … (*Interruptions*)

This is a very important matter. We have given a notice for Adjournment Motion. … (*Interruptions*) The implementation of GST should not apply on the on-going Government-sponsored programmes and schemes like Mission Kakatiya, Mission Bhagiratha, irrigation projects, and the double bedroom housing scheme meant for homeless poor people as these programmes and schemes have already been budgeted as per the earlier taxes, VAT, etc. … (*Interruptions*) The financial impact of the GST on these projects will severely hamper the progress of these projects.

There will be huge implications for the State on work contracts, bringing in an additional burdern of Rs. 19,200 crore if the 18 per cent GST is implemented. … (*Interruptions*) Our hon. CM of Telangana has written to the hon. PM on this. The hon. Finance Minister is also aware of this. … (*Interruptions*) Many a time, this has been taken up in the GST Council. If it is taken up from five per cent to 18 per cent GST, there will be a lot of burden. The budgetary allocations will have to be re-worked. … (*Interruptions*)

These are programmes for the poor people. They are for public use. They are already under execution and implementation. So, the on-going projects should not be taxed as per the new GST at 18 per cent. … (*Interruptions*)

We request our hon. Finance Minister who is here sitting in front of us to please listen to us and give a statement on this small thing. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसी अपेक्षा मत कीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: There will be a lot of litigation on this. So, I request the hon. Minister to please make a statement. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे रोज-रोज एक जीएसटी पर बोलना शुरू करेंगे तो गड़बड़ होगी। इसके लिए काउन्सिल है।

…(व्यवधान)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Madam, it has implications for Rs. 1 lakh crore worth projects. They will all come to a standstill. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You have raised your matter and he has heard it. I cannot compel him.

… (*Interruptions*)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Madam, I request the Minister, through you, to please intervene in this matter. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। Everyday, something will come up.

… (*Interruptions*)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Madam, he is willing to respond. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you want to say something?

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I will bring to the notice of the Council what Shri Reddy has raised. … (*Interruptions*)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Thank you, Sir.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अनन्तकुमार जी ने मुझसे पूछा कि यह बिल लेना है, मैंने उनसे कहा कि कल भी जीरो ऑवर नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष : आज पक्का जीरो ऑवर करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आज भी अगर जीरो ऑवर नहीं हुआ, तो यह ठीक नहीं रहता है, क्योंकि मेंबर्स अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखना चाहते हैं। कृपया आप जीरो ऑवर अलाऊ करें। बिल आप सोमवार को लें। हम तो कोआपरेट कर रहे हैं, रात के 7-8 बजे तक बैठ रहे हैं। यह अच्छा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : यह छोटा सा बिल है। इसके बाद जीरो ऑवर लेंगे।

…(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): हम जरूर जीरो ऑवर करेंगे। यह छोटा सा बिल है, इसे पहले करते हैं। इसके बाद जीरो ऑवर करेंगे।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप शान्ति से बैठिए। आप थोड़ा शान्ति सीख लीजिए।...(व्यवधान) आप बुलडोज करने का मत कीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको मौका दे दूँगी। इसके ठीक बाद जीरो ऑवर ले लूँगी। मैं आपको मौका दे दूँगी।

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, yesterday also we did not have 'Zero Hour'. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do not worry about that.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इसके तुरन्त बाद जीरो ऑवर ले लूँगी। अभी इसे जल्दी करा देते हैं। आज लंच नहीं करेंगे। आज जीरो ऑवर जरूर करेंगे।

…(व्यवधान)

12.24 hours

INDIAN INSTITUTE OF PETROLEUM AND ENERGY BILL, 2017*

HON. SPEAKER: The House will now take up item No. 12 – Indian Institute of Petroleum and Energy Bill.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

> "कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था होना घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अनुमति दी। सदन में एक नया कानून बनाने के लिए मैं आपकी अनुमति से सदन की अनुमति चाहता हूँ।...(व्यवधान) जब वर्ा 2014 में आन्ध्र पुनर्गठन का कानून बना।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर भी ले लेंगे। आज जीरो ऑवर लिये बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं कह रही हूँ कि आज जीरो ऑवर लिये बिना मैं नहीं जाऊँगी।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : दोनों राज्यों का बँटवारा हुआ।...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): We co-operated for three Bills. ... (*Interruptions*)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, मैं आपको, खड़गे साहब को और सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा। कल जितने बिजनेस आइटम्स 'लिस्ट-ऑफ-बिजनेस' में थे, पूरा इस सदन ने पहली बार कम्प्लीट किया। इतना ही नहीं, कल का दिन संसदीय इतिहास में एक अनोखा दिन था, एक रिकॉर्ड भी बना दिया, यानी तीन बिल्स, सब ने मिलकर, सबके सहयोग से हमने चर्चा करके पारित भी कर दिये।

माननीय अध्यक्ष : सभी सहयोग कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

---

* Moved with the recommendation of the President.

श्री अनन्तकुमार : मैडम, मैं आपके द्वारा यह बता रहा हूं।...(व्यवधान) आप 'ज़ीरो आवर' जरूर लीजिए, लेकिन इस बिल के बाद लीजिए, इतनी ही हमारी प्रार्थना है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, 'ज़ीरो आवर' ले लेंगे।

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): We are supporting the Government in this regard. ... (*Interruptions*) The Government should be considerate. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आज फ्राइडे है, इसलिए मैं भी बोल रही हूं कि लंच ब्रेक मत करो, कंटीन्युएशन में काम करो।

...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : मैडम, लंच-ब्रेक मत करिए।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: It is not good. ... (*Interruptions*) You should allow us to participate in the Zero Hour. Shri Dharmendra is here. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जी, बार-बार से इस प्रकार से प्रस्ताव नहीं लाइए। अगली बार ऐसा नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम सभी लोगों ने सपोर्ट करके बिल पास किए। पर, अब 'ज़ीरो आवर' नहीं लेना अच्छा नहीं है।...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : यह आपका ही निर्णय है, जिसे हम पूरा कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्षा जी, जब वर्ष 2014 में 'आंध्र प्रदेश रि-ऑरगेनाइजेशन एक्ट' बना, उस बिल में, उस व्यवस्था में जब दोनों राज्यों का बंटवारा हुआ, दो अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयां बनायी गयीं। दोनों राज्यों के विकास के बारे में बात की गयी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य आगे कैसे बढ़ेंगे। संसद के दोनों सदन, लोक सभा और राज्य सभा ने उस पर विस्तार से चर्चा की। पहले भी चर्चा हुई। यह उस चर्चा का एक बढ़िया उपज था, एक सोचा-समझा हुआ निर्णय था कि आंध्र प्रदेश में विश्व स्तर का एक पेट्रोलियम इनर्जी इंस्टीच्यूट बनाया जाएगा।

12.27 hours (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

उपाध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश नया बन रहा है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। आंध्र प्रदेश के मन में यह हुआ कि अपनी अर्थनीति को कैसे आगे बढ़ाएं। वर्ष 2014 में जो कमिटमेंट था, एक एक्ट के माध्यम से, प्रधान मंत्री जी की विशेष जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के विकास के लिए जो वचन संसद ने उन्हें दिया था, एक-एक करके उन सारे विषयों को हमें पूरा करना है। उसी के अन्दर शिड्यूल-13 में वहां की स्किल मैनपावर को बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग खोला जाएगा। यह सूचना मैं आपको सहर्ष देना चाहूंगा। पिछले एकैडमिक ईयर से आंध्र यूनिवर्सिटी के कैम्पस आई.आई.पी.ई. की पढ़ाई शुरू की गयी है। एक सोसायटी बनाकर इसे एक इंस्टीच्यूट का प्रारूप दिया गया है। उसकी प्रारंभिक वित्तीय व्यवस्था भी की गयी है और इसकी एक वर्ष की पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है। आई.आई.टी., खड़गपुर को उसे मेनटेन करने की जिम्मेदारी दी गयी है और इसी साल दूसरे बैच का एडमिशन भी हो जाएगा।

उपाध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रांत है। चालीस साल पहले भारत के ऊर्जा क्षेत्र में मुम्बई के ऑयल फील्ड का, गैस फील्ड का एक व्यावसायिक उपक्रम शुरू किया गया। कई सालों में यह समझ में आ रहा है कि उससे ज्यादा रिसोर्स कृष्णा-गोदावरी बेसिन में है, जिसे हम लोग 'के.जी. बेसिन' के नाम से जानते हैं और मानते हैं। के.जी. बेसिन में चुनौतियां अलग हैं। वहां गहरा समुद्र है और ऑयल के बजाय गैस की उपलब्धता ज्यादा है। दुनिया में एनर्जी को खोज निकालने के लिए, विशेषकर हाइड्रोकार्बन एनर्जी को खोज निकालने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी, समय-उपयोग टेक्नोलॉजी, उसको सही व्यावसायिक ढाँचे तथा व्यावसायिक मॉडल की आवश्यकता होती है।

उपाध्यक्ष जी, कोई भी चीज सिर्फ रिसोर्स एवेलेबल होने से नहीं होती है, बल्कि उसको मोनेटाइज करने के लिए अच्छे मानव शक्ति की भी आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, राज्यों का पुनर्गठन हुआ और आंध्र प्रदेश में आई.आई.पी.ई. करने का निर्णय किया। पिछले मार्च-अप्रैल महीने में कैबिनेट ने यह फैसला किया कि उसे एक अलग संस्था बनाकर स्वतंत्रता दी जाए। अब तक वर्ष 2016-17 के अकेडेमिक ईयर में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग के दो कोर्स में पचास-पचास विद्यार्थियों का एडमिशन हो चुका है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए दो सौ एकड़ जमीन भी उपलब्ध करायी है।

जैसा मैंने अभी कहा कि आईआईटी, खड़गपुर उसके मेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में काम करेगा। इसको एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की मान्यता देने के लिए, मैं आपके सामने यह बिल लेकर

आया हूं। उसकी प्रारंभिक तथा आर्थिक व्यवस्था हुई है। इसमें सरकार ने लगभग साढ़े छह सौ करोड़ रूपये से ज्यादा व्यय करने की व्यवस्था भी है। इस महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को एक कानूनी ढाँचों में परिवर्तित करने के लिए, एक स्वतंत्र आडेंटिटी देने के लिए तथा एक नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट बनाने के लिए मैं आपके माध्यम से सदन की अनुमति चाहता हूं। मैं निवदेन करता हूं कि माननीय सदन इस पर चर्चा करके परामर्श दें।

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to declare the institution known as the Indian Institute of Petroleum and Energy to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to dwell on the legislation under the title, 'The Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017'.

Sir, actually it is in pursuance of the bifurcation of Andhra Pradesh that two States – Telangana and Andhra Pradesh came into being. हम सबको वह दिन याद है और इस पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सारा हंगामा हुआ था, जब इन राज्यों के बाइफर्केशन की बारी आई थी। हमारी कांग्रेस पार्टी की यह प्रतिबद्धता तथा पॉलिटिकल कमिटमेंट था कि वहां के आम लोगों का जो ओपिनियन था, उसको मानते हुए इनका बाइफर्केशन किया जाए, विखंडित किया जाए। अगर हिन्दुस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए भुगतना पड़ा है, तो वह कांग्रेस पार्टी है। अब न हमारे साथ तेलंगाना रहा और न ही आंध्र प्रदेश रहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट से पीछे नहीं हटी। यह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए देश आगे है और पार्टी पीछे है। हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, उसको पूरा किया। मैंने सोचा था कि हमारे माननीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र बाबू एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसी के चलते आंध्र प्रदेश रि-ऑर्गनाइजेशन एक्ट, 2014, जिसके 13 शेड्यूल में यह था कि वहां पर एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए। जिसको ये लोग आई.आई.पी.ई. कहते हैं, क्योंकि यह कमिटमेंट के अंदर है। इसका कारण क्या था? The objective is to meet the quantitative and qualitative gap in the supply of skilled manpower for the petroleum sector and to promote research activity needed for the growth of the sector.

On behalf of my Party, I would like to congratulate the endeavour of the Government of Andhra Pradesh because the State Government had given 200 acres of land free of cost and I think, this should be emulated by other States as well. A stretch of 200 acres of land was given free of cost for setting up IIPE in Sabhabharam Mandal in Visakhapatnam. IIPE has been registered under Andhra Pradesh Society Registration Act 2001. A temporary campus of IIPE has been set up for academic session of 2016-17. This was mentioned by the hon. Minister also. The Cabinet has approved a sum of Rs. 655 crore as capital expenditure to set up IIPE and a contribution of Rs. 200 crore towards its Endowment Fund in addition to a contribution of Rs. 2000 crore from oil companies towards the Endowment Fund. I think, the oil companies and other Multi-National companies

and corporate bodies of our country should come forward to offer Endowment Fund for other States also. We are in desperate need of having requisite funds for setting up such institutes of importance. It is because this sector contributes 16 to 17 per cent to the GDP of our country. However, we are lagging behind in setting up dedicated institutions in this sector. There is a huge demand for skilled manpower for growth in this sector.

प्रधान जी, आप बड़े यंग मिनिस्टर हैं। आपका नसीब भी बहुत अच्छा है। आप नसीब वाले मिनिस्टर हैं, क्योंकि सत्ता में आने के पहले ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल का भाव 112 से 115 डॉलर प्रति बैरल था। आपके आते ही यह कभी 50, कभी 46, कभी 51, मतलब 51 से ज्यादा यह नहीं हुआ। ...(व्यवधान) मतलब तेल की दुनिया में आपके ऊपर एक बहुत बड़ी मेहरबानी बरसती रही। ...(व्यवधान) लेकिन फिर भी आपका दिल आम गरीबों के लिए मेहरबान नहीं हुआ। इतनी सारी सुविधा होते हुए भी आपने क्या किया? जो सब्सिडी देते थे, आपने कहा कि इसे हटा देना चाहिए। पहले दो रुपये, अभी चार रुपये, आप निर्णय ले चुके हैं कि सारी सब्सिडी रेजीम खत्म करेंगे। आप बहाना देते हैं कि यह ठीक नहीं, क्योंकि हम तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम चला रहे हैं, मतलब बीपीएल लोगों को यह सुविधा मुहैया होगी। 18 करोड़ हिंदुस्तानी, जिनको यह सुविधा मिलती थी, आपने उन लोगों को खारिज कर दिया। आपका बहाना है कि यह गरीब के लिए ठीक है, लेकिन जो गरीब नहीं हैं, उनके लिए पैसा देना बेकार है। 18 करोड़ हिंदुस्तानवासियों, जो 5-6 दिन पहले या एक महीना पहले गरीब थे, आज क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया हिंदुस्तान के ऊपर, वे सारे अमीर बन चुके हैं। इसमें खास कर बंगाल में एक करोड़ चालीस लाख आबादी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको इसमें क्या लाभ हुआ? 115 डॉलर प्रति बैरल से घट कर 50 डॉलर प्रति बैरल की सुविधा मिलते हुए भी आपने क्यों आम जनता के खिलाफ इस तरह के कदम उठाए हैं? यह बड़ी हैरानी की बात है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 18 करोड़ लोग, जिनको सब्सिडी मिलने वाली थी, क्या वे अब गरीबों की लिस्ट से बाहर आ चुके हैं, कैसे आ चुके हैं? क्या आप लोग ज्यादा रामचरित पढ़े हैं या ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़े हैं, इसलिए ये सारे 18 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गये हैं?

दूसरी बात, आज इंडियन एक्सप्रेस में क्या निकला है? Refinery project *Navaratna* EIL under probe for contract to Dubai company. CVC asked for papers for this 6.25 crore contract and PPRs for CBI probe. हम सब जानते हैं कि हिन्दुस्तान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। हमने 80 के दशक में इंटीग्रेटिड पॉलिसी बनाई थी। हमारे देश में मिडल क्लास बढ़ रहा है,

कन्जम्पशन पावर बढ़ रही है। जब मिडल क्लास बढ़ेगा, कन्जम्पशन बढ़ेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, तब हमें सबसे ज्यादा जरूरत एनर्जी की पड़ेगी। इसे नजर में रखते हुए हमने इंटीग्रेटिड एनर्जी पॉलिसी बनाई थी। अब आप पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, ड्राफ्ट नेशनल एनर्जी पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑयल और नैचुरल सैक्टर पर और ज्यादा विचार किया जाए। अभी भी हिन्दुस्तान में पावर सरप्लस है लेकिन एनर्जी की काफी पावर्टी है। We are still suffering from poverty of energy. पर कैपिटा ऑयल कन्जम्पशन कम है, फिर भी हम दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर हैं। हमारे देश में पर कैपिटा एनर्जी कन्जम्पशन कम है। आज हमारे सामने बड़ा मौका है क्योंकि यूरोप, चीन में मैक्रो इकोनामिक हेडविंड्स के कारण एनर्जी की कन्जम्पशन धीरे-धीरे थमेगी, तब हमारे देश में मैक्रो इकोनामिक टेलविंड्स के कारण एनर्जी कन्जम्पशन बढ़ेगा। आपको इस समय अच्छी पॉलिसी अपनानी चाहिए ताकि हम अपनी जरूरतों के साथ आगे जा सकें।

महोदय, बॉम्बे हाई में ईज़ी ऑयल मिलता था, राजस्थान में मिलता था। लेकिन डेढ़ दशक में हिन्दुस्तान में कोई मेजर ऑयल डिस्कवरी नहीं हुई है इसलिए इम्पोर्ट पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है। हमें इस डिपेंडेंसी सिंड्रोम को हटाना चाहिए। सेल कंपनी की बात दुनिया में हो रही है। इस कंपनी की हिन्दुस्तान में क्या अपारच्युनिटी है? एक्सपर्ट कहते हैं कि हिन्दुस्तान में सेल गैस की पोटेंशिएलिटी है। अगर ठीक से एक्सपर्ट किया जाए तो अगले 200 साल के लिए हम निश्चिंत हो सकते हैं।

महोदय, रिलांयस हिन्दुस्तान में एक अच्छी बेस्ट सैटिड इंडस्ट्री है। रिलांयस की रिफाइनरी की परफार्मेंस और पब्लिक सैक्टर रिफाइनरी की परफार्मेंस में इतना फर्क क्यों है? इसकी रिकवरी अच्छी होती है जबकि हम फेल होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं -Distillate yield at PSU refineries started to improve since 2012-13 following certain technological and performance improvement but it has now started registering decline. Reliance has been making the highest gross refining margin and rated the best in the world. हमारे पीएसयू क्यों नहीं कर सकते? छः कोर सैक्टर हैं, इनमें ऑयल उत्कृष्ट सैक्टर है। हम इस सैक्टर की परफार्मेंस पर अच्छी तरह से जोर दें तो देश के लिए अच्छा होगा। हम सुनते हैं कि कच्छ में कुछ डिस्कवरी हो रही है, पुंछ और लद्दाख के बारे में भी सुन रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के कारण आप घुस नहीं सकते हैं, एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आपको सदन में बताना चाहिए कि इसका कारण क्या है? लद्दाख में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है? ऑयल सैक्टर को लेकर हम सबको चर्चा करनी चाहिए।

DR. KAMBHAMPATI HARIBABU (VISAKHAPATNAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017. I thank the hon. Prime Minister, Narendra Modi ji and our hon. Minister of Petroleum and Natural Gas, Dharmendra Pradhan ji for taking the decision to establish the Indian Institute of Petroleum and Energy in the State of Andhra Pradesh, particularly at Visakhapatnam. I thank both of them on behalf of the people of Andhra Pradesh.

As you all are aware, when the State of Andhra Pradesh was divided into Andhra Pradesh and Telangana, there was not even a single institution of national importance in the divided Andhra Pradesh because all the institutions were left in Telangana, particularly at Hyderabad. The Reorganisation Act assures the people of Andhra Pradesh establishment of many institutions of national importance, particularly institutions relating to the Ministry of HRD. Seven institutions were to be established. Out of seven, five have already been established. They are: IIM at Visakhapatnam, Indian Institute of Technology at Tirupathi, Indian Institute of Science and Educational Research at Tirupathi, IIIT at Kurnool, and National Institute of Technology at Tadepalligudem. So, five institutions have already been established. Two institutions are yet to be established. One is the Central University at Ananthapur and the other is the Tribal University at Vijayanagaram District, which is the neighbouring district of mine. I hope the Government is taking steps to establish these two remaining institutions which come under the Ministry of HRD.

As far as the Andhra Pradesh Reorganisation Act is concerned, it assures the establishment of Petroleum University in the State of Andhra Pradesh and this assurance is being fulfilled by our young and dynamic Minister of Petroleum and Natural Gas, Dharmendra Pradhan ji. He personally came to Visakhapatnam to lay the foundation stone for the Petroleum University. I am very happy to mention what the hon. Minister stated in that inaugural function. He, while addressing the public and also the students who newly joined this Institute, told them one thing.

That is, after four years, the students of this Institute are going to get the degrees. He said that after four years he foresaw a situation where the students of this Institute will have degrees in one hand and the appointment letter in the other. That was the assurance he had given on that day. I could still recollect the brightness in the faces of those young students who joined this Institute on that day.

This Bill is being introduced to declare it as an Institution of national importance. The Institution will have the governance structure which will consist of the Board of Governors, the General Council, and the Academic Senate. I hope the hon. Minister will give autonomy to this Institute to design its own curriculum. The Bill also ensures legal mandate to award degrees for the students who have studied in this Institute similar to the IITs and the IIMs.

The courses offered in this Institute are in two streams. One is B.Tech in Petroleum Engineering and the other one is B.Tech in Chemical Engineering. The capital expenditure for this Institute is being estimated at Rs. 655 crore and the Endowment Fund is being estimated at Rs. 400 crore. The same is being allocated and is expected to be spent over a period of four to five years.

I would request the hon. Minister to allocate the funds that are required as per the construction of the buildings of the Institute so that the Institute comes up with necessary infrastructure at the earliest. I would request the hon. Minister that the basic infrastructure should be completed in such a way that at least one year the students who have joined this Institute should spend in the new campus so that they have the feeling of belonging to the campus of that Institute. Therefore, I request the hon. Minister to consider this. Sir, this institute is being established to create skilled man power in the field of petrochemical engineering and also to provide research activities for this sector. Why has this institute been established in the State of Andhra Pradesh? As the hon. Minister has explained in his speech, after the Bombay High, Andhra Pradesh is going to emerge as the hydrocarbon

hub in future. As you are all aware, KG Basin is one of the promising fields where we can explore huge volumes of crude oil and natural gas.

I thank the Government of Andhra Pradesh for coming forward to allot around 200 acres of land free of cost to set up this institute there. Whatever institute is being offered to the State of Andhra Pradesh, our Chief Minister Shri Chandrababu Naidu is very fast enough to say, 'you give me the institute, we will give you the land free of cost, kindly set up the institute at the earliest'. That is the request made by our Chief Minister because he is showing a lot of interest to get all the institutes that are being assured by the Government of India and this is one of them.

This institute has started functioning temporarily from the campus of the College of Engineering of Andhra University in which I studied engineering and where I also worked as a Teacher. I am very happy that this institute has started functioning from this very campus. Recently I visited the Institute of Petroleum and Energy. I interacted with the students as to what they are doing, how teaching is going on etc. I was very happy to interact with the students of the new institute and I hope that this institute will become an institute of national importance which will be having world-class infrastructure so that the students will get priority in appointments after passing out from this institute.

Sir, why is this institute being established in Andhra Pradesh? Andhra Pradesh is having about 974 kms. long sea coast and KG Basin promises a huge potential for exploitation of crude oil and natural gas. All the petroleum companies of India, which are known in the field of petrochemicals, such as Oil India, ONGC, Reliance, Cairn, GSPC are there in the KG Basin. ONGC is planning to invest about Rs. 78,000 crore in the coming year, Rs. 10,000 crore investment on onshore activities and Rs. 68,000 crore on offshore activities. It has signed a MoU with the Government of Andhra Pradesh for investment of Rs. 78,000 in the Investors' Summit which was held at Visakhapatnam in January, 2017 for exploitation of crude oil and natural gas resources in the KG Basin. Cairn India is

planning to invest about Rs. 3,240 crore in Ravaa field in the KG Basin. Reliance and British Petroleum, in a joint venture, are planning to invest Rs. 40,000 crore in D6 gas field in the KG Basin. We have the HPCL Refinery in Visakhapatnam. It is also expanding its capacity by investing about Rs. 16,000 crore. A Petrochemical Complex is coming up with an investment of Rs. 20,000 crore.

Sir, I mentioned about the presence of hydrates in the Bay of Bengal. The hon. Minister is aware about the discovery of hydrates in the KG Basin area. I am happy to mention here that about 134 trillion cubic feet hydrates is estimated to be available in the Bay of Bengal. This hydrate is nothing but a solid, which will be looking like ice form of water. It has to be exploited from KG Basin. There is no technology, at present, to exploit it because they have to operate it under high pressure, high temperature environment. Now, Japan and Canada are doing research in this field.

I wish that this Institute of Indian Petroleum and Energy will undertake research activity in the exploration of these hydrates. When these hydrates are exploited, India will become self-sufficient in energy field.

With these words, I conclude. Thank you.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill in the Lok Sabha.

But before I speak on the Bill, I have two questions for the hon. Minister. Firstly, why did the Government increase the price of subsidized LPG by four rupees per cylinder; and why will it be done every month? This is an anti-people decision, of which our leader, Sudip Bandyopadhyay had spoken earlier. I also say that this anti-people decision should be withdrawn.

Secondly, this Bill was cleared in the Cabinet on 12th April, 2017, and the Bill has now come to Lok Sabha. I want to know from the hon. Minister as to why did he go and lay the foundation-stone of the new campus even before it was cleared by the Cabinet, and even before the Bill came to Lok Sabha. He should not have done that. Laying a foundation-stone before even the Bill is cleared by the Cabinet, should not have been done… (*Interruptions*)

So, having said this, I say that this Institute is very essential. It is being set up in Vizag, which already has a petroleum refinery. It is close to the Krishna-Godavari Basin where oil has been found. It is also close to Kakinada where HPCL is setting up a new petrochemical complex. So, it is ideally situated.

The Government of Andhra Pradesh has given 200 acres of land at Sambhavaram where the Minister went to lay the foundation-stone. The IIT Kharagpur already teaches petroleum; they have got a subject called 'Exploration Geophysics'. They are mentoring this Institute; and already four professors are working there. More professors will be appointed after consultation with the IIT professors. The intake is 50 students for Petroleum Engineering and 50 students for Chemical Engineering. So, already, 96 students have started studying in this Institute; and the course is very important.

This Institute of Petroleum and Energy is being set up as a follow up of the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 where it was promised that Andhra Pradesh will have a new petroleum institute. In fulfillment of that objective, this has been done and a Bill has been brought.

Now, I want to say that it is very essential not only to develop petroleum sector but also to develop alternative sources of fuel. India is already deficient. We are importing 70 per cent of our petroleum products refinement. That is why research on non-conventional hydrocarbons as well as new sources like liquefied natural gas, bio-fuel and renewable should be used in India so that we can reduce our dependence on imported fuel, which is causing a huge outflow of our foreign exchange.

Now, as far as this Institute is concerned, it is being structured in the likes of the IITs. The only thing is that the hon. Minister has to bring another Bill so that it can be declared as an Institute of national importance.

13.00 hours

That has to be included in Entry 64, Schedule VII, of the Union List. That has to be done. I would like to request the hon. Minister to examine whether there is any need to bring a separate Bill for that purpose.

The Ordinances of the Institutes will be set up by the Central Government. The first Statute and the first Ordinance will be made by the Central Government and thereafter the power would go to the Board. The Central Government would also provide for General Council of the Institute and also provide for the Board of Governors. In this connection, I want to invite the Minister's attention to the Indian Institutes of Management Bill which was passed in this House only recently. There, the Government intervention has been withdrawn from the IIMs altogether. They said that all decisions will be taken by the Board of Governors and the President will not be the 'Visitor' to the IIMs. Now, I want the Minister to follow this path and make this new Institute free from the apron strings of the Government. Let all these things be decided by the Governing Council of the Institute itself.

As I said, it is of great importance to find more petroleum sources. It is said that the Bay of Bengal Basin is floating on oil. Oil exploration had started in the Sundarban's area of West Bengal but that was given up. I think, Schlumberger or

some American company was doing it. Now, it has been given up. I would urge the hon. Minister, since he is here, so that the exploration for petroleum can take place in the Bay of Bengal Basin of West Bengal.

The Cabinet has approved Rs. 65.46 crore as capital expenditure and given Rs. 400 crore as endowment fund. The Bill states clearly that this will be slowly reduced. In coming days, slowly, the Central Government grant would be reduced and expenditure or shortfall will be met from the endowment fund for which Rs. 400 crore has already been allocated. The idea is that ultimately the Institute will be raising some of the finances from its own sources and, I hope, the Minister would do the needful in this matter so that the Institute is not short of fund. In total, about Rs. 1,000 crore are being given for the development of the Institute. As I said, the Government of India is doing well by investing so much money in energy. By 2022-23, the capital expenditure would come down to Rs. 4.16 crore. The initial capital expenditure is for constructing the buildings, laboratories, etc. So, slowly, it will taper down. Then, the Institute will run from its own income and from its endowment fund.

There is also an Indian Institute of Petroleum at Dehradun where ONGC has its Headquarters. This new Institute will do Under-Graduate studies. I would like to request the Government to also initiate the Post-Graduate courses immediately, which are already there in IIT Kharagpur in West Bengal, and also to start doctoral research. This is a good step. It fulfils the aspirations of the people of Andhra Pradesh. It is in keeping with the Andhra Pradesh Reorganisation Act and it meets the challenge of India's energy needs in the future.

With these words, I support this Bill which is well-intentioned.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, thank you very much. I rise to speak on the Indian Institute of Petroleum Energy (IIPE) that is going to be set up at Visakhapatnam in Andhra Pradesh. If the hon. Minister requires to appease the people of Andhra Pradesh for the future of his political party, we are totally with him; we support him. We are happy that Andhra Pradesh, which is not really a new State, will see further development. It is the original State and Telangana is the new State. We are very happy about it. But this seems to be a political decision. Who are we, after all, to question anything?

These days, these times are times when we should be talking about energy synergy. I recollect, in Neemuch, I think that is in Madhya Pradesh, the hon. Prime Minister, about three months ago, had laid out his plans, his dreams for renewable energy. He had promised in his speech that he would usher in an energy revolution by harnessing sources of energy such as solar and wind power. We all know that Shri Modi is very much in favour of alternative energy. He has implemented it, to a great extent, in Gujarat when he was the Chief Minister and he wants his dream to be implemented at a national level. However, the way the newly restructured Ministry of Coal, Power, New and Renewable Energy has moved ahead, it has to be acknowledged. It has received yeoman applause from many sources which normally should not have been applauding it. The present Government had confidence to increase the renewable energy target from 20,000 MW of solar energy capacity to 100,000 MW by 2022, a stupendous five-fold increase. The Government also wants to put in place 60,000 MW of wind power capacity. Although these tall figures may sound very impressive to a lay person, it should be kept in mind that both wind and solar actually can produce, at peak utility, only 20 per cent of their capacity. Thus, meaning that a 100 MW solar energy plant at the best of its capacity can produce only 20 MW. The hon. Members may question as to why I am talking about another Ministry when we should be talking about petroleum and energy sources from hydrocarbons or fossil fuels or conventional sources. It is because, I believe, both should be connected as

the hon. Prime Minister has thought of bringing and harnessing both these things and moving ahead in the future.

One needs to be encouraged. More funds need to be poured into it while the other needs to be discouraged and slowly, methodically, it should be trimmed. That is where the whole world is moving. Our dependence on fossil fuels needs to be challenged. We have to learn to challenge our own abilities. People should be encouraged to increase their dependence on renewable energy. While the whole world is now trying to find ways to have less dependence on fossil fuels, this Bill is asking the Parliament to pour in a lot of money into research to promote the use of petroleum products which is simply not comprehensible, not understandable by somebody, ...* like me. I am talking about myself.

I have a suggestion. Just call this Institute, the Indian Institute of Energy. While the proposed university can work towards developing better technology, involving renewable energy, it should simultaneously work towards reducing our dependence on hydrocarbons. At the moment, there is a National Institute of Solar Energy under the ministry of Power, Coal and New and Renewable Energy. There is a Pandit Deen Dayal Petroleum University in Gandhinagar. There is a Power Management Institute run by NTPC in Noida. There is an institute of Drilling Technology operated by ONGC in Dehradun. What I suggest is why not bring all of these together under one umbrella like you have All India Institute of Medical Sciences. The hon. Health Minister has done a lot of good work. Similarly, on those lines, why not bring all these institutes under one umbrella, put in money and ask them to work on methods on how to get rid of those which create emission, which pollute the atmosphere and whose use damages the earth and move away from those sources of energy into alternative energy.

The structure of these institutions could be on the same lines as the proposed institute with the only difference that the research would be focussed on

* Not recorded

finding new renewable sources of energy and encouraging their adoption throughout the country.

Interestingly, when I read the Bill, Section 9 which defines the functions and objectives of this institution, I found something very funny to which I would like to draw the attention of the hon. Deputy Speaker Sir. I am reading Section 9 Sir: -

> "Promote research and development for the benefit of oil, gas and petrochemical industry and the energy sector through the integration of teaching and research, foster close educational and research interaction through networking with national, regional and international players in the oil, gas and petrochemical industry and the energy sector, giving broad focus to the functioning of the institute in the area of petroleum and petroleum related technologies under the wide umbrella of energy and doing all such things, not specifically covered above as may be necessary incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the institute."

Sir, that means we are going to encourage the usage of petroleum and petrol products.

I would like to mention the last point which is also interesting and it is there in this.

Even the General Council has members only from hydrocarbon industry who will obviously not like the country to move away to renewable energy. This Bill proposes that the institute would be advised by a General Council, in Section 15.

Let us take a look at the composition Sir. The Council will comprise upto 20 Members including Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas who shall be the Chairman; Chairman, Indian Oil Corporation; Secretary, Oil Industry Development Board; Chairman, Gas Authority of India, and more importantly, persons not less than two but not exceeding four representing the private entities in the field of petroleum sector operating in the country to be nominated by the Chairperson.

The membership composition implies that traditional thought and traditional mindset will not only continue, it shall be further strengthened with private enterprise. And how many players are there in the petroleum sector in India? I can recollect only Essar and there is one smaller company called Reliance and a few others. So, those two companies will have two members and that is enough. The idea here for the nation should be to evolve out of hydrocarbons and not to evolve into it further.

Thank you Sir.

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): Hon. Deputy Speaker, I wish to express my gratitude to our hon. Leader Puratchi Thalaivi Amma and thank you for allowing me to speak on the important Bill, the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017.

The Bill establishes the Indian Institute of Petroleum and Energy, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. It declares the institute as an institution of national importance. The institute aims to provide high quality education and research focusing on the themes of petroleum, hydrocarbons and energy. We would like the Government to start an institute of same kind in Tamil Nadu where the Government excels in exploration and exploitation of petroleum, oil and gas resources.

The Institute will not only be declared as an institute of national importance but also the research would focus mainly on fields such as liquefied natural gas, biofuels and renewables. The Bill mandates that a Board of Governors also be formed along with the Institute's General Council.

The Senate is the principal academic body responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination in the Institute. The Director of the Institute will be appointed by the Central Government. The accounts of the Institute shall be audited by the C&AG of India.

The extraction of hydrocarbon from Tamil Nadu has become a burning issue and has raised apprehension in the minds of the people of Tamil Nadu, particularly the farmers of the Cauvery delta region. The Union Cabinet has approved the proposal to extract hydrocarbons from Neduvasal, Nallandarkollai, Vanakkankadu, Kottaikadu, Vadakadu and nearby villages in Pudukkottai District of Tamil Nadu.

This has raised apprehension among the villagers that this may be a move to extract hydrocarbons which is against the interests of the farmers. The agitated farmers are protesting continuously against this move. Still the Government is unwilling to scrap the Neduvasal hydrocarbon extraction project. The Union

Government, instead of solving this burning issue, is adding fuel by their move to sign the MoU.

Our beloved leader hon. Puratchi Thalaivi Amma had strongly opposed any move to extract such gases, as this could adversely affect the farm lands, agricultural activities and food security. The Tamil Nadu State Government has made a categorical statement that it would not allow any such project in the State.

Sir, while we oppose the extraction of hydrocarbons from farm lands in Tamil Nadu, the Tamil Nadu Government with faith and hope, has declared about 23,000 hectares spread across 45 villages in Cuddalore and Nagapattinam Districts as Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Region (PCPIR). The Centre would allocate Rs. 1,146 crore for improving the infrastructure such as road and rail connectivity in the region.

The PCPIR would be a specifically created investment region for establishment of manufacturing facilities for producing petroleum, chemicals and petrochemicals along with associated services and infrastructure meant for domestic consumption and export.

The Centre had approved setting up four PCPIRs in Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha and Tamil Nadu. The industry sources said the region would deal with petroleum refinery and downstream products. It does not have anything to do with oil or gas exploration as the region will be confined only to petroleum refinery. The PCPIR project was expected to attract a total investment of Rs.92,160 crore.

Under these circumstances, I urge the Union Government to stop the extraction of hydrocarbons in any form from Neduvasal and neighbouring villages in Pudukkottai. I strongly urge the Union Government to close all the wells already dug for pilot projects and cancel the land lease agreements between the ONGC and the farmers and handover the lands to the farmers ensuring that the interests of the farmers are fully safeguarded.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Deputy Speaker, Sir, at the outset, let me congratulate the hon. Minister for bringing out such a wonderful Bill, the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017.

The issue is that right now there are some institutes existing in the country. They are run by some of the petroleum companies only. What will be their status right now? You are not only creating a new institute but also you are creating an institute of national importance, what was needed for long. Therefore, I congratulate the Minister.

But as far as energy is concerned, all over the world, hydrocarbons and shale gas are issues coming out presently in the energy sector. But during the Standing Committee study tour, when we visited some of the ONGC centres, we found that we failed in many of the wells that are dug for shale gas. So, this is the institute, which will give us some directive and guidance in that regard as it is a research institute. I feel that there will be more stress on research work rather than on academic education in the institute. If it is only for academic study, the students will get their degrees and join some jobs. But, I think, the main stress should be on research work.

When the shale gas production started throughout the world, the risk came down and the petroleum industry was shattered a bit because by that time they had purchased crude oil at a higher price which the market price came down, which caused a huge loss to the companies. But no one knows it. We feel that as the market price of crude oil goes down, the price of petrol will equally go down. But the petrol companies faced losses because they had purchased the crude oil at a higher price.

When we are going to form this institute, let me first congratulate the people of Andhra Pradesh. They must be very happy today that an institute of national importance has been bestowed to them. They must have been requiring it for a long time since two States have been formed out of one and they needed some booster from the Central Government.

Then, the next most important thing of the course at the institute is its curriculum and syllabus. The curriculum should be of a global standard. If it is not of a global level, again we will be coming down in comparison with other global universities. So, the significance of research standard has to be kept in mind. We are going to form a board there. We know about the functions of the board as to what they are going to do.

Then, do we have the teachers, the educationists of that global standard and quality, who can teach our students in that institute? When we form an institute of national importance, it is all about imparting education with regard to new technology. Today, the technology changes rapidly all over the world. Therefore, we should have staff, which is well versed with the latest technological changes, to impart education of a very high quality to our students. That is what we require. So, I would also like to know from the hon. Minister as to what is our preparation in this regard?

When the Government is giving national importance to this institute, I have a few suggestions. The most important thing, I think, is that the Government is giving it financial assistance also. For the next three years, Rs.200 crore is being provided through this Bill. Generally, when such institutes are formed, they are not backed with financial assistance. But this is a Bill through which the Government is providing a financial aid to this institute and hence the people of Andhra Pradesh must be very happy about it.

Sir, I feel that Mumbai, particularly the coastal belt of Mumbai is also an appropriate place for such an institute. The headquarters of petroleum companies are also in Mumbai. Therefore, I request the Government to think of setting up of an institute of national importance in Mumbai also because one institute will not be able to cater to the needs of the entire country.

Sir, a number of wells dug with the intention of shale gas have failed in the Northeast. The rate of failure is much more than what we are gaining out of it. We need to do a study for that. Then again research is required. Therefore, I demand Bill that many more such institutes should be set up. I also request the Government to bring all the existing institutes under one umbrella cover of this institute. Thank you.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. Please give me some more time to speak as this institute is going to be set up in my constituency. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, no. You have to speak only about the institute.

… (*Interruptions*)

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) : Sir, this institute is coming under my parliamentary constituency. Thank you, Sir.

First of all, I would convey my thanks to our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji; our dynamic hon. Minister, Shri Dharmendra Pradhan ji and our Chief Minister Shri N. Chandrababu Naidu for granting an institute of national importance to Vangali Village, Sabbavaram Mandal in Anakapalli constituency. The location of the institute is nearly 25 kilometres from Visakhapatnam Airport. I also convey my sincere thanks to our Chief Minister for granting 200 acres of land, which is very expensive. The price of one acre of land is about two crore rupees. So, the cost of this land comes to more than Rs. 400 crore and the State Government has given it free of cost.

As the House knows, in accordance with 13th Schedule of Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, the Indian Institute of Petroleum and Energy has been set up. I thank the NDA Government for establishing this institute. I also thank the authorities for sanctioning this institution and starting this institution in the present academic year itself in order to save the students' future. One hon. Member wanted to know why they have laid the foundation stone. It is only in the interest of the students that they laid the foundation stone and commenced the class work in a temporary accommodation at Andhra Pradesh University, keeping in view the future of 100 students – one batch for petroleum and one batch for chemical engineering.

The institute will provide high quality education and conduct advance research in all aspects relating to the conventional hydrocarbons. Another important feature of the Bill is that the institute is expected to be a domain-specific

energy institute which will serve as a fountainhead for nurturing world-class technical human resources capable of serving as leaders and innovators in the field of petroleum technology and energy. If possible, the Government may think of making it an international institute having foreign collaborations and exchange programmes with the institutions in the developed countries in the near future.

In this connection, I want to make some suggestions for the kind consideration of the hon. Minister. While appointing the non-gazetted staff, he should give instructions to the institute, they should recruit local people instead of recruiting people from outside the State. This will give an opportunity to the local youth of the State to secure jobs.

Regarding allocation of funds to the institute, I suggest to the hon. Minister to release funds smoothly so that the construction of the institute takes place at a fast pace. If possible, a committee may be constituted to oversee the work of infrastructure and other works on a priority basis. The Government has provided budgetary support for capital expenditure which is spread out till 2022-23. I suggest to the hon. Minister that the Government should adhere to this schedule strictly and there should not be any extension beyond 2023.

I would also like to give a small suggestion. In every educational institution, even in IITs, the Governments are spending thousands of crores of rupees for giving education to students. After finishing their education, all our students are going to the foreign countries for their higher studies and jobs. I am not objecting to that, but when we are investing crores of rupees for providing education in this country, we should also try to stop brain-drain to other countries. At least, in this petroleum and energy institute, I request the hon. Minister to take care of this aspect. In all our institutions – private and government – we are producing job-seekers for multinational companies. At least, this institution should not provide job-seekers for the private companies like Reliance Industries or public sector companies like HPCL or private universities. At least, some of the students should be the job-makers. For that, the syllabus or the content we teach to

the students should be useful for their future innovations. So, I request the hon. Minister to start an incubation centre on par with the institution so that the creative or innovative minds of the youth of this country could be utilised for the development of this country.

The other thing is that because of industrialisation, decentralisation and IT revolution, the jobs had been increasing day by day, but today, because of automation, the jobs are decreasing. I request the hon. Minister that we have to give training to the present students to meet future challenges arising out of automation and business activities getting more and more Internet based so that after some time, they do not get insecured in respect of their jobs.

Some people have asked questions about starting this institute in Andhra Pradesh. It is because after Gujarat, it is Andhra Pradesh which is having the longest coastline. We have major ports, rail connectivity, road connectivity, and we have natural resources, but unscientifically our State got divided three years back without any capital; without any educational institutions; and without anything else and with a Rs. 16,000 crore deficit Budget. But, with his experience, our hon. Chief Minister with the cooperation and blessings of our hon. Prime Minister is running the Government for the last three years with great difficulty. But I would like to thank the Government of India once again for sanctioning seven educational institutions in three years. It is a great achievement of our State after Independence as no other State got seven institutions in these three years.

I also request the hon. Minister to please introduce yoga to meet the future stress challenges. Nowadays, what is the major problem in the country for the youth? It is only stress. Therefore, on par with the syllabus you please introduce yoga also for the students so that they will definitely be fit both physically and mentally. I would request the hon. Minister that along with education we should also teach students ethical values, culture, tradition, etc. This is the legacy that we can give to the future generations and not our assets or properties. Thank you once again for giving me this opportunity.

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017. Our TRS Party is supporting the Bill.

Petroleum is the only single import to our country, which shows an impact on the entire economy even on vegetable prices in the States. We are happy that the Government is setting up the Indian Institute of Petroleum with an investment of Rs. 655 crore as capital and Rs. 250 crore as endowment, and declaring this institution as an institute of national importance.

We are glad that the institution is being set up in our erstwhile capital of Andhra Pradesh. Now, it is our new neighbouring State of Andhra Pradesh. Our country has achieved a lot in the field of technology, but still we are behind in some important areas. In the institution, the curriculum not only includes petroleum but it includes environmental-friendly alternate to petroleum like bio-fuels and other renewable energy. But we are not concentrating on the development of multi-field stock bio-gas plant for our farmers, which will give a substitute for LPG and Urea.

When these two States were divided, it was clearly mentioned in the State Reorganization Bill, 2014. There are some institutions over there and really we are happy for it. We are supporting Andhra Pradesh, and we are always giving our support to a new State for its development and we are for it.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI): Thank you very much.

PROF. A.S.R. NAIK: We are also requesting you that there are many pending issues in the Telangana State also. It is already mentioned in the Reorganization Bill that the Indian Institute of Management (IIM) would be there and we have allocated land for it, but three years have passed and there is no initiation from the Government side or the particular Department. Another issue is the Horticulture University promised under the State Reorganization Act 2014, which is still pending as well as the Tribal University. As you know, there are 10 crore tribals in the country. If tribals have some educational institutions, it gives them

confidence to pursue higher education. It is very important. Already a sum of Rs.100 crore has been allocated. Why is the Government not taking any initiation in this regard? I would request the Ministry, through you, to take initiation for the establishment of a Tribal University in Telangana.

As you know, the Steel Authority of India have approached Bayyaram Iron Ore Mines. Earlier, one lakh acre was given on lease. I would like to state here that we fought for it and were not in favour of the agreement. Three years have lapsed. It is located in the tribal parliamentary constituency. No initiative has been taken by the Government. So, I would request the Government, through you, to expedite the pending proposals.

We welcome whatever steps the Central Government have been taking concerning Andhra Pradesh. We are happy. It is also a new State. Kindly concentrate on Andhra Pradesh. Whatever proposals have been stated in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, I would request the Government to take initiation to expedite the same. Thank you, Sir.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, I am very much happy to be here to discuss one of the important Bills in the area of petroleum and energy sector. The Indian Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017 was tabled by our hon. Minister, Shri Dharmendra Pradhan. He is a dynamic Minister. I have no doubt. I have some experience as I have been a Member of the Standing Committee on Petroleum for the last three years. I found that such dynamism does not exist in the petroleum companies, particularly in our PSUs.

We have a lot of institutions under the Petroleum Ministry but the functioning of such institutions is not good. The Oil Industries Development Board was established in 1975 under the Oil Development Act of 1974. We have established many institutions like Directorate General of Hydrocarbons, Oil Industry Safety Directorate, Centre for High Technology, Petroleum Conservation Research Association, etc. for improvement of energy requirement of our country, and also for bringing in improvement in our petroleum industry.

Day before yesterday a Report was submitted on Centre for High Technology. We need new technology. But such institutions are not working well. Recently, the Ministry has appointed a permanent Director in one of the institutions. It is a welcome step. Only when we strive to strengthen our own industry, we can meet the challenges.

I would like to state that the first institute established in this area is in 1960 – the Indian Institute of Petroleum, Dehradun, Uttarakhand with the technical support of the CSIR, Uttarakhand. The second institute came into being in 2008 in Rai Bareilly, Uttar Pradesh by an Act of Parliament. It was given national status in 2008 itself. This institute received support from ONGC, HCPL, BPCL, Oil India, IOCL, OIDB, and acadamic support with IIT, Kanpur. The Indian Institute of Petroleum & Energy, Visakhapatnam, Andhra Pradesh was established in 2001 under the Societies Act of Andhra Pradesh. This was elevated to the status of an institution of national importance.

It is good. The Financial Memorandum of the Bill says, and I quote:

> "The establishment of the Institute involves total capital expenditure of Rs.655.46 crore and an endowment fund of Rs.400 crore (Rs. 200 crore from Budgetary support and Rs.200 crore from five Oil Public Sector Undertakings). Around half of the interest accruing from endowment fund of Rs.400 crore will be utilised to meet the deficit against the recurring expenses and remaining recurring expenses will be met through students fees, donations and other earnings of the Institute such as research and development, consultancies, students placement fees, etc."

It is very difficult. The OIDB is the biggest organization in the country. They are charging cess from each oil subscriber. That gets accumulated in the Finance Department. It comes to more than Rs.1.5 lakh crore in the hands of the Government. But they have given the merger amount for the utilization of such an important institution.

I am going to conclude within two minutes. Shri Tathagata Satpathyji has already mentioned about the Board of Governors. But, as per the composition of General Council, only the Indian Oil Corporation and the OIL are there. But, we do not have representation from the ONGC, OIDB and others institutions.

We are looking for oil security. The requirement met in our country is through import of oil. But now the imported crude price is quite less. I came to Parliament in 2009. At that time, the budgetary support for the oil subsidies was more than Rs.1.00 lakh crore. Now, it is zero. Now, people subsidise the Government.

There is one more thing. The expense of vehicles on oil is comparatively higher than the expense of electric vehicle. The scenario is changing world over from oil-run vehicle to electric-run vehicle.

I have only one more point. The joint venture of oil companies is going to be a private entity. The Secretary (Petroleum) himself is the Chairman of the private PETRONET. Therefore, the JV of the oil companies is not going to be a private entity. It is a part and parcel of the Government. The Government is looking for the merger of all the oil companies to form a bigger oil company. I

would request the Government to take the admission of this Institute under the JEE. But, recently, we have had many complaints about this Joint Entrance Exam. It included incidence of bribe, capitation fee and so on. This led to the subversion of the admission process. The eligible candidates could not get admission in this Institute. I would request the Minister to look into this matter personally especially about the Rajiv Gandhi Institute. I would also request the Minister to start one such Institute in Cochin, as there are many major institutions like HPCL, BPCL and the PETRONET is also there in Cochin. I hope the Government will start one such Institute in Cochin. Thank you.

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Sir, at the very outset, I thank the Chair for permitting me to speak on the Indian Institute of Petroleum Energy Bill, 2017 with an aim to take the nation forward in education, training and research relating to the field of petroleum and energy. The Government has established an Institute of Petroleum and Energy in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. I congratulate the hon. Prime Minister and the hon. Petroleum Minister Shri Dharmendra Pradhanji for acceding to the aspirations of youths of Andhra Pradesh.

The Indian Institute of Petroleum and Energy is one of the prestigious Institutes granted to Andhra Pradesh after the bifurcation of the State in 2014. The Government of India has fulfilled the commitment to establish a Petroleum University in the successor State of Andhra Pradesh as per the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014. The Institute is expected to be a domain specific energy institute that should serve as the fountain head for nurturing world class technical human resources who are capable of serving as leaders and innovators in the field of petroleum technology and energy.

The objective of this university should be to meet the quantitative and qualitative gap in the supply of skilled manpower for the petroleum sector and to promote research activities needed for the growth of the sector. The academic and research activities of this Institute should derive strength from the Institute's proximity to sector related activities such as KG Basin, Visakhapatnam refinery and the planned Petrochemical complex at Kakinada.

The research work carried out by the Institute should not be confined to petroleum but alternate and renewable energy need to be given equal importance. Research activities should be opened to all the researchers of the top institutes of the country so that the IIPE becomes the global consultant and a research hub for energy.

However, to make the institute a world class university, adequate infrastructure has to be provided. The institute cannot function and provide

qualitative research and internship programmes with only four faculty members. The Government needs to consider this aspect. Only then the credibility of the university will increase and can focus on the various programmes and the research to be carried out by the institute.

With this, I once again congratulate the Government for setting up IIPE in Andhra Pradesh and support the Bill.

I would like to take this opportunity to thank the Prime Minister for launching the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana to provide 5 crore poor women with free LPG connections for providing clean cooking fuel. The Yojana has been formulated to ensure that no rural and below poverty line family resorts to cooking using wood, charcoal, cow dung or other unhealthy fuel sources. Rural households in the country have always had limited or no access to modern utilities like LPG, but with Prime Minister's initiative, poor women in rural areas and even in remote areas now avail the facility of gas connections. However, the Government should release more connections as lakhs of people below poverty line are still waiting for this facility. The Government should not restrict a poor woman to avail free cooking gas connection if she does not have the Aadhaar Card.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Within a short span of time, our respected Shri Dharmendra Pradhan ji, Minister of Petroleum under the inspiration of the hon. Prime Minister established a very high-standard institute - the Institute of Petroleum and Natural Gas. I congratulate the people of Andhra Pradesh and the Government of Andhra Pradesh because it is a great achievement on the part of the hon. Member.

I also congratulate Shri Dharmendra ji because there is one petroleum institute which was inaugurated by the Congress Party. They inaugurated it and forgot it completely. But it is Shri Dharmendra Pradhan who has granted Rs. 350 crore and made it workable. Again, I request hon. Minister to see that it starts working again.

We cannot deny that Shri Narendra Modi is very accurate, honest and down to earth in keeping the commitment at the right moment and in the right direction. This Institute of Petroleum and Energy is a part of our Government's promise and commitment to the Andhra Pradesh when it was bifurcated. As such, in 2017, this year, as per the commitment, the Minister of Petroleum established this high-standard institution and sanctioned Rs. 655.45 crore which is a huge amount. This will be a world-class institution to mould our budding youth and to find a resourceful human beings. This Institute will fill the gap of qualitative and quantitative need for oil sector by promoting research and development work in both petroleum and petroleum related energy sector. Our budding youth will be well versed in advanced knowledge and technology which are so far lacking in the universities of our country, to compete everywhere and become global leaders in the time to come.

This institute which is established presently in Andhra Pradesh will provide knowledge in both conventional and non-conventional hydrocarbon related resources, liquid gas and bio fuel. High technical knowledge in such areas will surely create high quality human resource for the country and for the world. This institution is being given a status which is at par with IITs. This institute in Andhra

Pradesh includes advanced programme at postgraduate level and it has got the sanction and legality to grant postgraduate degrees and doctorate degrees which is a great thing. This additional advantage for our talented and inquisitive youth is a source of blessing. Previously, our students had to go to foreign countries to get such knowledge. Only this time, because of the Petroleum Ministry and our hon. Prime Minister, our students are getting the opportunity to get all the knowledge required to be a global leader in our country itself.

As we know, the oil sector is now flourishing like anything. But oil was discovered for the first time in Assam when a British officer in the early 1880s discovered some oil-like substance in the soil stuck in the leg of an elephant. He followed the elephant and he engaged some labourers to dig the place. He asked the labourers, "Dig boy, dig." It is said that the name Digboi has originated this way. This is how the first oil town Digboi came into existence. Presently, there are four refineries in Assam. ONGC is also working there. But I have come to know that though the Oil India is getting lots of profit, the ONGC is in loss. ONGC is a world class organisation and it has got work everywhere in the world. I think it should flourish. Only with a high standard establishment, you can do it; otherwise it is not possible. So, I would urge the hon. Minister to restart the Sivasagar Petroleum Institute in Assam. He has given money for it to be started again with high quality professors. I hope he will establish such type of institutes all over the country, especially in the north-eastern region because there is dearth of talented and skilled people. Thank you.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी द्वारा भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 सदन में लाया गया है, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की स्थापना की मंजूरी से संबंधित है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री के सामने अपने राज्यों से जुड़े कुछ सवालों को रखना चाहता हूं। केंद्र सरकार बिहार राज्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की स्थापना करे तो यह बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का विशेष पैकेज भी हो सकता है। इसकी घोषणा स्वयं सरकार कर चुकी है। हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी करते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बांका में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की स्थापना की जाए। हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा होगा? इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय मंत्री जी यह भी बतायें कि बिहार के पटना भागलपुर, बांका, मुंगेर तथा अन्य जगहों पर सीएनजी एवं पीएनजी की व्यवस्था कब तक होगी?

मैं माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र बांका बाराहाट में गैस बॉटलिंग प्लांट की स्थापना के लिए मंजूरी दी है और वहां आज कार्य भी शुरू हो गया है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से लगातार आग्रह भी करता रहा हूं। मैं चाहूंगा कि बांका बाराहाट के गैस बॉटलिंग प्लांट का कार्य पूर्ण हो।

मैं माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अहम बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल के समर्थन मे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि आज जरूरत है कि हम पेट्रोलियम और रिन्युअबल एनर्जी के प्रति गंभीरता से चर्चा करें। इस बिल में पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के सेटअप होने की बात आ रही है। मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि हम केवल पेट्रोलियम पर एक वर्ल्ड क्लास टेक्नीकल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी जब पेरिस गये थे, तब प्रकाश जावेड़कर जी एन्वायरन्मेंट मिनिस्टर थे। उन्होंने वहां जाकर रिन्युअबल एनर्जी के प्रति कोपा एग्रीमैंट भी साइन की थी। अगर हम इसी इंस्टीट्यूट को एक इंस्टीट्यूट ऑफ नैशनल इम्पोर्टैंस फॉर पेट्रोलियम एंड रिन्युअबल एनर्जी करते, तो शायद कहीं न कहीं वे सारे ऑस्पैक्ट्स भी कवर होते।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से पता लगता है कि इस इंस्टीट्यूट को सेटअप करने में लगभग एक हजार करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। मेरा कहना है कि जो पेट्रोलियम कम्पनीज हैं, जो इस इंस्टीट्यूट के बायो-प्रोडक्ट्स पर रिसर्च एंड डेवलपमैंट होगी, उससे अपने आपको और डेवलप करने का काम करेगी। हम उनका हिस्सा क्यों न इस इंस्टीट्यूट में डालने का काम करें? हम जब नैशनल इम्पोर्टैंस का इंस्टीट्यूट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें सैंट्रल गवर्नमैंट से हजारों करोड़ों रुपये लेने पड़ते हैं। आज हमारे पास एसआरए, रिलायंस और प्राइवेट कम्पनीज हैं, तो क्यों न हम उन कम्पनीज के सीएसआर के फंड्स को डायवर्ट करके, चाहे वहां बिल्डिंग बनानी है, इन्फ्रास्ट्रक्चर करना है या कोई रिसर्च करना है, उसके लिए पैसा लगायें। हम वहां जो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, वह कहीं न कहीं हमारे देश में काम आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस इंस्टीट्यूट से हजारों बच्चे डेवलप होकर जायेंगे। लेकिन हम आज भी देखते हैं कि पेट्रोलियम के ऊपर जो बच्चे रिसर्च करते हैं, वे एजुकेशन हमारे इंस्टीट्यूट से लेते हैं, लेकिन एजुकेशन लेने के बाद कतर, दुबई, यूएसए आदि ऐसी कंट्रीज जहां ऑयल एक्स्पिडिशन बड़ी तादाद में होते हैं, वहां पर चले जाते हैं। ...(व्यवधान) हमें कहीं न कहीं एक सीमा बांधनी पड़ेगी कि जो बच्चे इन इंस्टीट्यूट्स से पढ़कर निकलेंगे, उन पर कम से कम पांच साल तक उन इंस्टीट्यूट्स की रिसर्च में काम करने का प्रतिबंध लगायें।

अंत में, मैं मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि यह इंस्टीट्यूट्स ज्यादातर केजी बेसिन पर काम करेगा। मेरा कहना है कि इसके अलावा और भी एरियाज हैं, जैसे पानीपत और भटिंडा में रिफाइनरी है। हमें इनके आस-पास भी इंस्टीट्यूट्स डेवलप करने पड़ेंगे, जो नैशनल इम्पोर्टैंस से अटैच्ड हों, मगर इन रिफाइनरीज में भी हैल्प कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

14.00 hours

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि निश्चित ही कुछ माननीय सदस्यों को भ्रम या भ्रांति है, क्योंकि यदि वे इस विधेयक को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि परम्परागत हाइड्रो कार्बन्स के साथ ही चूंकि ऊर्जा क्षेत्र विकसित हो रहा है और गैर-परम्परागत हाइड्रो कार्बनों के साथ ही साथ नये स्रोत, जैसे द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में आ रहे हैं, तो संस्थान भारतीय और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी स्थिति प्राप्त करने और बनाये रखने के लिए इन क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से अनुसंधान करेगा। जब यह स्पष्ट कर दिया गया है, तो फिर हमारा यह सोचना कि ये इंस्टीट्यूट केवल हाइड्रो कार्बन्स को लेकर, जो परम्परागत हाइड्रो कार्बन्स हैं, उन्हीं के बारे में सिखायेगा और शोध करेगा, तो ऐसा नहीं है।

हम जानते हैं कि जो परम्परागत हाइड्रोकार्बन्स के स्रोत हैं, वे घटते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि गैर-परम्परागत और नए स्रोतों पर ध्यान दिया जाए। इसमें एक तकनीकी विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारी धरती का जो भूगर्भ है, उसके अंदर पत्थर के रूप में ऑयल शेल्स एंड टार सैंड्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर एक कम्पाउण्ड होता है, जिसे तेल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसे हल्का करने के लिए, उसकी विस्कोसिटी को घटाने के लिए एक विशेष तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। मुझे लगता है ऐसे संस्थान बनाने से हम अपनी कमिटमेंट को ऑनर कर ही रहे हैं, साथ ही हम उस दिशा में भी काम करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में इन ऑयल शेल्स का बड़ा भण्डार है, जिसका प्रयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित रूप से किया जा सकता है।

किसी भी सरकार का चरित्र यदि सही हो और वचन प्रतिबद्धता हो तो निश्चित रूप से वह जो कहती है, करके दिखाती है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी को, कि वह इतना अच्छा विधेयक लाए हैं और इस प्रकार के इंस्टीट्यूट की स्थापना आन्ध्र प्रदेश में करने जा रहे हैं। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान इस प्रकार के राज्य हैं, जहां हाइड्रोकार्बन्स एवं गैर-परम्परागत हाइड्रोकार्बन्स का भरपूर भण्डार है, इसलिए वहां भी इस प्रकार के एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। समय कम है, इसलिए अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा। Henry Petroski had said 'science is about knowing and engineering is about doing'. Hon. Deputy Speaker, Sir, I want to say that our Government believes in knowing and then doing the right thing. With this, I wholeheartedly support this Bill and I congratulate the hon. Minister.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : डिप्टी-स्पीकर साहब, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि बहुत जरूरी बिल लेकर आए हैं और यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत महत्व है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के स्रोत बहुत कम हैं और ऐसे स्रोतों की तलाश की जा सकती है, इसके लिए स्कोप है। इकोनोमी की ग्लोबलाइजेशन होने के कारण हम विदेशों से भी गैस वगैरह मंगवा सकते हैं। यह सच है कि देश में जो पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज हैं, उनके एक्सपेंसेज दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और उसे कम करने के लिए अच्छे टेक्नोक्रैट्स की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आप आज जो बिल लाए हैं, इससे हमारे जो युवा वहां एजुकेशन लेंगे, उसका बहुत बड़ा फायदा फ्यूचर में देश को मिलेगा। पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के स्रोतों से दूर हैं, हमारे पास कोयला नहीं है, इसलिए वहां इस किस्म की इंस्टीट्यूशन बननी चाहिए। आप आज जिस प्रकार की नेशनल इम्पोर्टेंस की पेट्रोलियम एंड एनर्जी इंस्टीट्यूशन आन्ध्र प्रदेश के लिए लेकर आए हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूट पंजाब में भी बने तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वह सरहदी क्षेत्र है। दूसरा, मैं मंत्री जी से यह भी मांग करना चाहता हूं कि जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स जोड़ते हैं, मगर बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिनमें फार्मर्स और कन्ज्यूमर्स के लिए कभी रेट चेंज नहीं होता है। क्रूड ऑयल की जो एक्चुअल प्राइस है, उसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। सबसे ज्यादा टैक्सेस अगर किसी प्रोडक्ट पर लगते हैं तो वे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगे हैं। इन टैक्सेस को कम करने की जरूरत है, विशेषकर कृषि क्षेत्र के लिए। मैं यही मांग करता हूं। धन्यवाद।

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): Hon. Deputy Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak.

The National Institute of Petroleum and Energy Bill, 2017 aims to set up an Indian Institute of Petroleum and Energy at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. It also declares the Institute as an institution of national importance. I appreciate the aim of the Bill as it provides high quality education and research focusing on the themes of petroleum, hydrocarbons and energy. The Government is going to pump in Rs.655.46 crore. It is stated that this budgetary support for capital expenditure is expected to spread out till 2022-2023. Would the hon. Minister state what is the plan of action in place as of now particularly when our aim is very challenging and the amount to be spent is so huge?

The said Institute is expected to be a domain-specific energy Institute that will serve as the fountain-head for nurturing world class technical human resources capable of serving as leaders and innovators in the field of petroleum technology and energy. What spadework has been put in place as of now or proposed to be put up for taking the Institute further?

The said Institute is aimed at extending high quality education and conduct advance research in all aspects relating to the conventional hydrocarbons. I appreciate the exalted aim. Will the hon. Minister state as to how he intends to go about and what initiatives have already been put in place to achieve this aim of quality education and conducting advance research in petroleum and design?

About the constitution of the Board of Governors which is responsible for the general superintendence, direction and control of the affairs of the Institute and having a General Council of the Institute, *inter alia*, would review from time to time the broad policies and programmes of the Institute and suggest measures for the improvement, development and expansion of the Institute. I would like to know from the hon. Minister what measures were put in place to make the functioning of the institute transparent and accountable. Will the institute have autonomy to steer clear of the impending issues that it would face while

navigating towards an institute of excellence and national importance and setting a benchmark for other such institutions in other fields like agriculture, science *et al*?

Coming back to the aims of the Bill, where do we stand on these themes? How much prepared are we? What are our challenges in the field of petroleum and energy? Have we analyzed them? Where are we placed *vis-a-vis* other countries in terms of technology and state of art innovations in the field of petroleum and energy?

There is a need to have a re-look or a fresh look at the whole gamut of issues or concerns involved in providing education and research when our institutions find hardly a place of excellence in 100 out of 200 best institutions of the world?

There is an urgent need to bring in foreign faculty, who are experts and who know what is happening and what new developments and innovations are taking place in the realm of petroleum and energy sector?

I hope the hon. Minister too would endorse this view that there is a lot of room for improvement and we should strive towards making the National Institute of Petroleum and Energy a centre for excellence in the real sense of the term and not make it as an achievement of the Government of the day that it has gifted an institute to a State and forgotte patronizing and monitoring it.

I am representing West Bengal. Would the hon. Minister consider setting up an institution of national importance to cater to the emerging and challenging needs in the domain of petroleum and energy in West Bengal?

Lastly, I would request the hon. Minister to withdraw the decision taken by the Ministry to stop LPG subsidy.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे तीन मिनट समय देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार को इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार एक राष्ट्रीय महत्व की भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की स्थापना विशाखापटनम में करने जा रही है और इसमें करीब एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च होगा। हमें आशा है कि यह संस्थान देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक होगा। मैं माननीय मंत्री जी को भी इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं। करीब 20 प्रतिशत कच्चे तेल का उत्पादन हमारे देश में होता है और 80 प्रतिशत हम लोग बाहर से आयात करते हैं। दिन प्रति दिन कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता-बढ़ता रहता है। अभी पिछले 10-15 वर्षों के रिकॉर्ड अनुसार यह निचले स्तर पर है। इससे काफी हद तक हमारी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, किन्तु मेरा मानना है कि यह लाभ आम नागरिक को नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इसका लाभ गरीबों को भी मिलना चाहिए। इसी प्रकार से, देश में 50 प्रतिशत से अधिक गैसों का उत्पादन हो रहा है और शेष के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। फिर भी गैस का दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं हो रहा है? देश में आज घरेलू गैस लगभग छः करोड़ परिवारों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से अधिक संख्या गरीब परिवारों की है।

एलपीजी का दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं करना चाहिए। साफ ईंधन के लिए गैस आवश्यक है, इसलिए इसे कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है। मेरा सुझाव और आग्रह है कि सरकार को घरेलू एलपीजी के दाम में कमी करनी चाहिए, इसके दाम में वृद्धि करना ठीक नहीं होगा।

सरकार को आवश्यक रूप से विचार करने का समय आ गया है कि कच्चे तेल का उत्पादन कैसे बढ़े, इसका देश में प्रचुर मात्रा में भण्डारण हो, लेकिन इसका उत्पादन नहीं बढ़ा रहा है। इसके लिए ओएनजीसी ने पहले जिम्मेवारी ली थी, आज वह उस जिम्मेवारी से हट रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि ओएनजीसी को सुधारने की आवश्यकता है।

मैं बिहार से आता हूँ। सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना 'हल्दिया-जगदीशपुर पाइप-लाइन परियोजना' वहाँ लग रही है। यह बिहार के कई जिलों से गुजरेगा, किन्तु इसका कोई लाभ बिहार को नहीं मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस पाइप-लाइन परियोजना का जाल पूरे बिहार में फैलाने की अनुमति दें ताकि वहाँ की आम जनता को कम दामों पर एक साफ ईंधन मिल सके।

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगाँव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 'भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017' पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हुआ हूँ।

हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी और पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वे एक बहुत महत्त्वपूर्ण बिल इस सदन में लाये हैं। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इंडियन इंस्टीट्युट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की स्थापना को मंज़ूरी दी है। यह संसद में पारित अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान होगा। डिग्रियाँ प्रदान करने के लिए इस संस्थान का संचालन, ढाँचा और अधिकारी उसी तरह के होंगे जैसा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में है। एक अलग अधिनियम पेट्रोलियम एवं ऊर्जा-अध्ययन के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र बनने के लिए संस्थान को अपेक्षित दर्जा प्रदान करेगा।

जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में वर्णित है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची की प्रतिबद्धता के तहत इस संस्थान को स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुशल श्रम-शक्ति की आपूर्ति की मात्रा के गुणात्मक अंतर को पूरा करना और क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस आइआइटी के अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधि को इस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में, जैसे के.जी. बेसीन, विशाखापत्तनम् रिफाइनरी और काकीनाड़ा जैसे प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल परिसर तक इस संस्थान की पहुंच से मजबूती मिलेगी।...(व्यवधान) महोदय, अभी मैंने शुरू किया है।

HON. DEPUTY SPEAKER: We have to finish quickly because we have to take up `Zero Hour'.

श्री ए.टी.नाना पाटील: इस विधेयक के माध्यम से सरकार जनहित के एक और वादे को पूरा करने जा रही है। आज पूरा देश जानता है कि पिछली सरकार ने जो भी वादे किये थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार ने जनता से जो वादे किये हैं, उसके साथ-साथ पुरानी सरकार के बचे हुए वादे को भी पूरा करने जा रही है।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि जीएसटी हो, आधार कार्ड हो, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात हो या देश में कालाधन समाप्त करने का वादा हो, वर्तमान स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय के स्थायी कैम्पस की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले विशाखापत्तनम् में अतकापल्ली गांव में 200 एकड़ जमीन बिना मूल्य के सरकार को प्राजेक्ट के लिए दिया है। मैं आंध्र प्रदेश की जनता और वहाँ की सरकार का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय मंत्रिमंडल अर्थात हमारी सरकार ने संस्थान के कैंप्स के लिए 655.46 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के लिए एक 'एन्डोमेन्ट फंड' की स्थापना भी की गई है। इसमें अपने अंशदान के रूप में 200 करोड़ रुपए की राशि भी सरकार ने दी है, जो कि उसके द्वारा दी गई 600 करोड़ की राशि से अलग होगी। ये तेल कंपनियों द्वारा मुहैया कराई गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की योजना के अनुसार इन कैंप्स में आधुनिक सुविधा से उपयुक्त प्रयोगशालाएं होंगी। ये कैंप्स ई-लाइब्रेरी एवं वाई-फाई सेवाओं जैसी अन्य आधुनिक सुविधाओं से भी लैस होंगे। विश्वविद्यालय ने केमिकल और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बी.टेक पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करना आरंभ कर दिया है। कुछ ही समय से यह संस्थान स्नातक और डॉक्ट्रेट स्तर जैसे उच्चतम पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करना भी शुरू करेगा। महोदय, मुझे दो मिनट दीजिए। यह संस्थान विश्व स्तरीय तकनीकों के माध्यम से मानव संसाधनों का पोषण करने के लिए मूल स्त्रोत के रूप में कार्य करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार ने इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है, ताकि यहाँ पर उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं उपलब्ध हों। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह संस्थान निकट भविष्य में भारतीय और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी ख्याति प्राप्त करेगा तथा पेट्रोलियम ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक गैस, जैविक-ईंधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से अनुसंधान और विकास करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि यह प्रस्तावित संस्थान एक आधुनिक सुविधायुक्त प्रीमियर संस्थान के रूप में खुद को स्थापित करेगा। मैं आँध्र प्रदेश की जनता तथा सरकार को इस अवसर पर बधाई देता हूँ, क्योंकि वहाँ एक विश्वस्तरीय तथा प्रौद्योगिकीय शिक्षा का संस्थान स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ-साथ हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी का भी हृदय से स्वागत करता हूँ।

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान बिल पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के माध्यम से विशाखापट्नम में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम स्थापित किया जा रहा है, वह एक बहुत अच्छा इनिशिऐटिव है। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम के अलावा अन्य ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज़ की खोज की जा रही है। भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर खोज करने का बहुत अच्छा स्कोप है। हम अपने देश में सिर्फ 20 पर सेंट ही कच्चे तेल की पूर्ति कर पाते हैं, बाकी तेल हमें दूसरे देशों से लेना पड़ता है। भगवान ने भारत की धरती को बहुत से खनिज पदार्थ दिए हैं। हमारे यहाँ कोयला, पेट्रोलियम आदि कई खनिज पदार्थ हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स की वजह से नई उम्र के लड़के जो डिग्रियाँ हासिल करेंगे, उनके माध्यम से इस क्षेत्र में नई खोज होगी। आज इस प्रकार की नई खोज की जरूरत है। मेरे द्वारा बोलने से पहले भी यह बात चली थी कि पंजाब के भटिंडा में भी एक तेल की रिफाइनरी है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूट भटिंडा में भी खोला जाए। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ टैलेन्ट की कमी नहीं है। पेट्रो-कनेडा कंपनी और अमेरिका में जितनी भी ऑयल सैक्टर की कंपनियाँ हैं, वहाँ भारतीय इंजीनियरों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमें मजबूरी के कारण यहाँ के संस्थानों से डिग्रियाँ प्राप्त करने के बाद इन जगहों पर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र को और आगे लेकर जाने की जरूरत है। आज नॉर्थ इंडिया में भटिंडा, संगरूर और ऐसे चार-पाँच अन्य स्टेट्स जुड़ते हैं। वहाँ एयरपोर्ट भी है। वहाँ रेलवे भी पहुँचती है। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इस ओर भी कृपया ध्यान दें और नॉर्थ इंडिया में भी एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी दिया जाए, ताकि हमारे जो टैलेन्टिड इंजीनियर्स हैं, वे इसी देश में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। धन्यवाद।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का इनिशिऐटिव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी खोलने का है। देहरादून में इससे संबंधित एक संस्थान है, लेकिन आज जिस तरह सरकार ने देश की एक बड़ी आबादी की समस्याओं और उनकी चुनौतियों को ऐड्रेस किया है, उससे डिमाण्ड काफी बढ़ गई है।

उज्ज्वला एक ऐसी योजना है जिसके तहत हम बड़े व्यापक तरीके से गांव में प्रवेश कर चुके हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि एनर्जी शब्द बहुत ही व्यापक है। दुष्यंत जी ने कहा कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देने की जरूरत है। दुनिया के बाजार में आज सोलर और विण्ड एनर्जी पर शोध हो रहे हैं। हमारे यहां भी इस क्षेत्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने एक नया आयाम देने का काम किया है। निश्चित तौर से हमें शोध प्रबंधन को मजबूत करने की जरूरत है। जैसे-जैसे हम पेट्रोलियम क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और गांव, खेत-खलिहान में इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है, हम वहां तक प्रवेश कर चुके हैं। बीपीएल परिवारों में जाने के बाद हमें सेफ्टी का भी प्रबंधन करना चाहिए। इसलिए ऐसे संस्थानों के खुलने से अंतर्राष्ट्रीय मानक का संस्थान इसे बनाने के लिए हमें दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों से भी समझौता करना चाहिए। उस समझौते के तहत हमारे यहां भी रिसर्च वर्क हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान यह बने, इससे कई तरह के लाभ, चूंकि ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है, इस पूंजी को जितना परिष्कृत करेंगे, उतना अच्छा होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी है, इसी तरह से आगरा में तेल रिफाइनरी से जो गैस निकलती है, हमारा विज्ञान पता नहीं कहां तक सक्षम है, वह लगातार 24 घण्टे जलती रहता है। हम उसको यदि टैपिंग करें, उसकी बॉटलिंग करें तो उससे काफी लाभ होगा, इसलिए रिसर्च के माध्यम से इसकी टैपिंग और बॉटलिंग का भी प्रबंध करना चाहिए। धन्यवाद।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much. I rise to support the Bill in its full spirit and text. I take this opportunity to congratulate the then UPA Government led by Dr. Manmohan Singh ji for having taken a bold decision to bifurcate Andhra Pradesh so that this Institute is established as part of its commitment. Also I take this opportunity to congratulate this NDA Government led by Shri Narendra Modi ji for honouring the commitment made by the UPA Government. I would like to congratulate also the Chief Minister of Andhra Pradesh and the State Government for providing such a land for establishing this Institute of national importance and prestige.

This is the need of the hour and there is no doubt about it because in the petroleum sector we do not have an institute of national importance. The Statement of Objects and Reasons also talks about an institute of national importance. We have to convert it into an Institute of global importance. Our standing in this field internationally is nil. Indian oil and gas companies are having presence in 21 countries. Still we do not have expertise and manpower in oil exploration. We are lacking in that area and we have to address that issue. I feel that this Institute will provide and deliver professional experts in the field of oil and gas. So, I support the Bill.

14.24 hours (Hon. Speaker *in the chair*)

The lack of professionals in this sector has to be addressed. We know that 70 to 75 per cent of our oil requirement is being imported. A major chunk of our foreign exchange is being spent towards this sector. Still we do not have self-sufficiency in the oil sector. I had a talk with Shri Veerappa Moily, the then Minister. According to him, even in the State of Rajasthan we are having abundant resources of oil. But unfortunately we are not able to explore oil in Rajasthan, and even in Assam. So, my suggestion is that prime importance or significant importance should be given to oil exploration for which self-sufficiency in oil exploration technology is also highly required. I hope this Institute will help a lot towards that end. That is the suggestion.

There are so many other Institutes, like the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum in Assam, in Bengaluru, in Raebareli. My suggestion is, all these Institutes should be brought within the purview of the Indian Institute of Petroleum and Energy so that they could also be developed. The fourth suggestion is that IOCL, HPCL, BPCL, ONGC and all other organisations in the petroleum and natural gas sector should be protected in public sector itself.

Lastly, I would like to make a request pertaining to my constituency. In my constituency, Hindustan Petroleum Company has stopped its entire operations 20 years back and 27 acres of land is lying idle for the last 20 years. I have written to the Minister about this many times. No positive response has come from him so far. So, I urge upon the hon. Minister to start some institute in that area and utilise that land.

With these words, I conclude.

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान विधेयक, 2017 के समर्थन में खड़ा हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय पेट्रोलियम मंत्री, धर्मेन्द्र प्रधान जी को बधाई देता हूं कि वे पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो विधेयक लाए हैं। हम समझते हैं कि आन्ध्र प्रदेश के साथ-साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए यह एक मिसाल बनेगी और विकास की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। वहां से हमारे नौजवान उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करके पेट्रोलियम के क्षेत्र में आएंगे। वे अपनी विशेषज्ञता का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जिससे पेट्रोलियम के कामों में सहूलियत होगी। हम चाहते हैं कि इसी तरह से, जैसे कल हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपने बयान में कहा था कि वर्ा में 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि इसी तरह से ट्रांस्पोर्ट विश्वविद्यालय की भी व्यवस्था की जाए। जिसमें बच्चे पढ़ें और हमारी सड़कों की जो स्थिति है, दुर्घटनाएं होती हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं बंद हों।

इसी तरह से हमारे रेल मंत्री, सुरेश प्रभु जी ने कहा था कि रेल विश्वविद्यालय की स्थापना हो तो हम चाहते हैं कि रेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो। जिसमें हमारे नौजवान उच्च कोटि की विशेषज्ञता हासिल करके आगे आएं और देश हित में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से दो-तीन बातें आग्रह करना चाहूंगा। भारत में रिसर्च की स्थिति बहुत दयनीय है। यदि आप दुनिया के मानचित्र में देखें तो पाएंगे कि प्रतिभा की कमी नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी बिल मील का पत्थर साबित होगा। यह आवश्यक है। मेरा कहना है कि शोध और विशेषज्ञों पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हम दुनिया से एक या दो नहीं, बल्कि 70-75 प्रतिशत आयात करते हैं, जबकि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लेकिन यदि हम विशेषज्ञ के अभाव में 70 सालों में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं, जिसमें यू.पी.ए. की सरकार के बाद एक बड़ी पहल हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और धर्मेन्द्र प्रधान जी ने की है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि नॉर्थ इलाके में, जहां सबसे पहले असम में रिसर्च की आवश्यकता है, यह बात आप जानते हैं, क्योंकि जब आप चाइना बॉर्डर के इलाके में जाएंगे, वहां रिसर्चर पर बहुत ज्यादा शोध की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स को नॉर्दर्न इलाके में भी लाने की आवश्यकता है। जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के साथ अल्टरनेटिव एनर्जी पर भी आपको बहुत ज्यादा खोज करने की आवश्यकता है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।

बिहार के हल्दिया प्रोजेक्ट पर बहुत गंभीरता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा अंतिम बिंदु यह है कि हमारे यहां बरौनी रिफाइनरी है और 70 सालों में सिर्फ एक ही सबसे बड़ी रिफाइनरी है। उसको कैसे डेवलप किया जाए? मेरा एक सुझाव यह है कि सी.आर.एस. के माध्यम से जो सबसे ज्यादा धन अर्जन करने वाली कंपनी है। आप की जो ओ.एन.जी.सी. है, आप इंस्टीट्यूट को उसी के धन से डेवलप कर सकते हैं, अगर मंत्रालय से आवश्यकता कम पड़ेगी।

पूर्णिया, बंगाल, कटिहार, बायसी और किशनगंज इलाकों में अत्यधिक पेट्रोलियम पदार्थ पाने के लिए, देखा गया है कि जो बरौनी से पूर्णिया का इलाका जो गंगा के इस पार में हल्दिया के बीच में है। उस पर शोध करने की आवश्यकता है। आपसे मेरी मांग है कि पूर्णिया, बायसी, बंगाल और असम के बीच जो अत्यधिक भंडारण है, उस भंडारण को खोजने की आवश्यकता है। भारत में भंडारण की कमी नहीं है, लेकिन शोध और रिसर्च में कमी है। मैं आपको ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने के लिए बधाई देता हूं। लेकिन आप सिर्फ उनकी संख्या बढ़ा दीजिए। आई.आई.टी., रुड़की से आपने जो कम्पेयर किया है, वह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि इनकी संख्या और बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर एक सार्थक चर्चा माननीय सदस्यों के माध्यम से कराई है। 23 सम्माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव इस बिल पर दिये हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि यह बिल आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए आया था, लेकिन सारे मित्रों ने पूरे पेट्रोलियम इकोनोमिक्स और मौजूद हाइड्रो कार्बन इंडस्ट्री की भारत के संबंध में जो-जो चुनौतियां हैं, जैसे डिमांड्स फॉर ग्रांट पर डिस्कशन होता है, सबने वैसे ही सुझाव दिये हैं। यह मेरे लिए मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगा। मैं उसे अन्य समय में काम में भी लगाऊंगा। आज उत्तर देते समय आपने इंस्टीट्यूट के बारे जो कुछ मूलभूत सुझाव दिये हैं, उन्हें मैं आदर के साथ ग्रहण करते हुए अपने विषय को सीमित रखूंगा।

महोदया, इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि अगर अमरीका में शैल गैस का उद्भावन नहीं होता तो शायद विश्व की राजनीति और अर्थनीति दोनों कुछ और होतीं। शायद आज विश्व में तेल के दाम 100 डालर पर बरकरार रहते और खाड़ी के देशों में पूरे तनाव का वातावरण जारी रहता। अमरीका ने शैल गैस का उद्भावन किया, आविष्कार किया, उसके कारण आज विश्व में तनाव घटा है और तेल के दाम पचास डालर के ऊपर नहीं जा रहे हैं। मेरे मित्र अधीर जी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे प्रधान मंत्री जी सौभाग्यशाली हैं, देश की जनता सौभाग्यशाली है, इसलिए विश्व में तेल के दाम इस स्थिति में हैं। अधीर जी इसका मूल कारण यह है कि आज रिसर्च और विज्ञान ने ही इस प्रकार के नये आयाम को खोज निकाला है और इसलिए आज शैल गैस की अर्थ नीति बन पाई है। अगर ह्यूस्टन में दो-तीन अच्छे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट न होते तो शायद इंस्टीट्यूट और लेबोरेटरी के एक्सपेरिमैन्ट, कमर्शियल एक्सपेरिमेन्ट ऑयल और गैस फील्ड में नहीं होते। जो एक्सपेरिमेन्ट्स तीस सालों तक चले, उसके कारण आज विश्व में तेल की एक नई इकोनोमी उभरकर आई है। मैं आभारी हूं कि जिस परिस्थिति में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल पर मेरे मित्र तथागत जी ने कहा कि यह राजनीतिक निर्णय है। मैं तथागत जी को बताना चाहता हूं कि मैं पिछली लोक सभा में नहीं था, आप यहां थे, आप ही लोगों ने उस पर निर्णय करके फैसला किया था कि एक नया इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हम आपकी प्रशंसा न करें, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम आपके आभारी हैं, देश की पुनर्रचना में आप लोगों ने भी योगदान दिया है। पिछली सरकार ने सही तरीके से पुनर्गठन के अवसर पर देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश में नेशनल इम्पार्टेंस की एक इंस्टीट्यूट तय की। लेकिन मैं आभारी हूं कि आपने पेट्रोलियम और इनर्जी के लिए एक इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश में तय किया। मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक फ्यूचरिस्टिक इम्पैक्ट रहेगा तथा आगे आने वाले समय में आंध्र प्रदेश में क्या-क्या होगा। इसका लाभ सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, इसका लाभ देश की अर्थ नीति को होगा, विश्व की अर्थ नीति को होगा, भारत के नौजवानों को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी और जिस विषय पर चर्चा की गई है, सिर्फ हाइड्रो कार्बन क्यों। मैं अपने मित्र राघव लखनपाल जी का

आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस विषय पर सबका ध्यान आकर्षित किया। इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इनर्जी के बारे में रिसर्च या पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि वैकल्पिक, नॉन-फॉसिल हाइड्रो कार्बन के बारे में, आल्टरनेटिव इनर्जी के बारे में भी चर्चा होगी।

श्री हरि बाबू ने अपने भाषण में एक महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख किया। विश्व में नैक्स्ट जनरेशन की इनर्जी के बारे में कई प्रकार की चर्चा होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सोलर, विंड, हाइड्रोजन से इनर्जी उत्पन्न होगी, नये-नये प्रकार के कंजर्वेशन के बारे में चर्चा हो रही है, बायो-फ्यूल्स के बारे में चर्चा हो रही है, ऐसे ही एक विषय गैस हाइड्रेट के बारे में चर्चा हो रही है। जापान, अमरीका, चाइना और भारत ये चार अग्रणी अर्थव्यवस्था गैस हाइड्रेट के बारे में शोध कर रहे हैं। गैस हाइड्रेट यही होती है जो आइसक्रीम बन जाती है। हजारों मीटर जमीन के नीचे समुद्र की गहराई में, सीबैड पर जब वातावरण अत्यधिक ठण्डा हो जाता है, हाइड्रो कार्बन, पैट्रोलियम पदार्थ आईसक्रीम का रूप ले लेता है। अभी जो विश्व में तीन-चार जगहों पर पर्याप्त मात्रा में गैस हाइड्रेट की अनुसंधान की सफलता मिली है, उसमें मैं गर्व के साथ इस लोक सभा के पटल पर भारतीय जनता को सूचित करना चाहता हूँ कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन एक प्रोलिफिक बेसिन बनती दिख रही है, जिसमें आने वाले दिनों में कई सौ वर्षों तक, शायद भारत की एनर्जी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। चुनौती कहाँ है? चुनौती इसी में है कि उसको कैसे हम मॉनिटाइज़ कर पाए। उसको कैसे हम बाहर ले कर आ पाए। मैं इसीलिए आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम को इसके लिए सही जगह चुना है। आन्ध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य बन रहा है, जहां रिफाइनरी है। जहां के.जी. बेसिन, जो दुनिया की, हमारा तो सपना यह होना चाहिए कि आज ह्युस्टन का जो स्थान विश्व की तेल अर्थनीति में है, विज्ञान के अनुसंधान में है, व्यवसाय में है, वह के.जी. बेसिन का भी हो।

यह अलग बात है कि मेरे कुछ मित्रों को प्राइवेट सैक्टर के बारे में एक पैथोलॉजिकल हेट्रेडनेस है। उनकी वह समझ है। उनकी जो सोच है, वे वही कहेंगे। बाकी आज इस देश की सहमति है, विज्ञान, व्यवसाय, संस्थान आदि इन सभी का एक मेलजोल बिठाना पड़ेगा। आज अमरीका अगर विकसित हुआ है। हम पांच चीज़ों में अमरीका के साथ सहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमरीका के विकास के मॉडल को हम नज़रअंदाज़ भी नहीं कर सकते हैं या विश्व के किसी भी आधुनिक इलाके के विकास मॉडल को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उन्होंने इस तालमेल को ठीक से बना कर रखा है। क्या हमारे वाइज़ैक, विशाखापटनम, काकीनाडा या राजामुंदरी आने वाले दिनों में ह्युस्टन नहीं बन सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये ह्युस्टन बन सकते हैं। इसका मूल बीज शायद यह इण्डियन इंस्टिट्युट ऑफ पैट्रोलियम एण्ड इंजीनियरिंग से ही निकलेगा। आने वाले दिनों में रिसर्च, विज्ञान और अनुसंधान इन सब पर जोर दिया जाएगा, अर्थ का कोई अभाव नहीं रहेगा। आंध्र प्रदेश सरकार का मैं आभार प्रकट करूंगा कि

उन्होंने दो सौ एकड़ जमीन बिना पैसा के उपलब्ध कराई है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सही कदम उठाया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: धमेन्द्र जी, आपने मिथनॉल के बारे में कुछ सोचा है?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : दादा, आज कम से कम आईआईपीई के बारे में सोचें। बाकी आप कभी भी सवाल पूछिए, मैं तो सौभाग्यशाली रहूंगा कि आपने प्रश्न पूछा और मैं उसका उत्तर भी दूंगा। आज तो हम आईआईपीई के बारे में सीमित रहें। इसमें आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा है कि आंध्र प्रदेश में क्या-क्या होने वाला है। कोई जरूरी नहीं कि जो क्रूड ऑयल उत्पादित होगा, विश्व में क्रूड ऑयल उत्पादित हो रहा है, भारत में क्रूड ऑयल उत्पादित हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि ये सारा ट्रांस्पोर्टेशन फ्युल में ही आएगा। आने वाले दिनों मे भारत में किसी सामान्य व्यक्ति के घर में कोई अर्थनीतिक परिवर्तन होता है, तो उसके अपने घर में फर्क दिखने लगता है। उसके पहनावे में, उसके रहन-सहन में, उसके घर में परिवर्तन आता है।

पर्यावरण के बारे में हम सब सजग हैं। मेरे प्रधान मंत्री कोप-21 में खुद को प्रतिबद्ध कर के आए हैं कि दुनिया हमारी जिम्मेदारी को समझे। अभी अमरीका ने हाथ खींच लिया कि हम कोप-21 को नहीं मानते हैं। प्रकाश जी उसका समझौता कर के आए थे। प्रधान मंत्री जी ने विश्व को कहा कि भारत पर्यावरण में सबसे आगे हैं। हम कोई प्रदूषणकारी देश नहीं हैं। हम तो सबसे कम प्रदूषणकारी देश हैं। दुनिया के प्रदूषणकारी हमें समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब अमरीका ने हाथ खींचे तो प्रधान मंत्री जी ने विश्व के नागरिकों को कहा कि भारत अपनी जवाबदेही पूरी करेगा और हम कोप-21 के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो हाइड्रोकार्बन आएगा, उसको हमें ट्रांस्पोर्टेशन फ्यूल में परिवर्तित करना है। हमें क्या करना चाहिए, यह संस्थान उसकी क्या जिम्मेदारी लेगा, आने वाले दिनों में क्या गरीबों के घरों में प्लास्टिक की कुर्सी नहीं बननी चाहिए? क्या गरीब लोगों को पहनावा नहीं पहनना चाहिए? नग्न लोग अगर टैरीकॉटन के सस्ते कपड़े पहनते हैं तो क्या यह नहीं होना चाहिए? आज की आधुनिक जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यकता में, हमारे परिधानों में, हमारे दिन प्रति दिन के जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं, जो पैट्रोकैमिकल प्रोडक्ट से बनती हैं। यह जो माइक्रोफोन हमारे हाथ में है, यह भी पैट्रोकैमिकल प्रोडक्ट है।

तथागत जी, आप अपने कान पर लगाकर जिससे सुन रहे हैं, यह भी क्रूड ऑयल से ही निकलकर आता है। इसलिए आप थोड़ा पूर्वाग्रह छोड़ दीजिए, मैं हूँ, ठीक है, मेरे प्रति आपका बड़ा आदर है, मैं आभारी हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सांसद हैं।

श्री तथागत सत्पथी: हम तो आपको सपोर्ट करते हैं।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : आप क्या करते हो, यह सब जानते हैं। इस विषय में हम थोड़ा बड़ा सोचें। मैं इस सदन का आभारी हूँ कि आप सबने एक-आध कुछ सुझाव दिया है, एक-आध कुछ मौलिक प्रश्न उठाया, आपने

अपने इलाके की अपेक्षा को भी कहा, यही तो संसद का उद्देश्य है, लेकिन सबने यह सहमत किया कि यह रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए, यह सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस होना चाहिए, इसमें पर्याप्त अनुसन्धान होना चाहिए, रोजगार के बारे में सोचा जाना चाहिए। लोकल रोजगार पर निश्चित रूप में ध्यान दिया जायेगा। जो सारा नॉन-टीचिंग स्टॉफ होगा, बाहर से लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, आन्ध्र प्रदेश के नौजवान उसमें आयेंगे। आपने सेफ्टी के बारे में कहा, उसके बारे में भी अध्ययन होगा। यह भी कहा कि सरकार क्यों पैसा खर्च कर रही है और पेट्रोलियम कम्पनियों को भी उसमें करना चाहिए। मैं इस सदन को अन्त में यह भी सूचित करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार का पैसा है, उसके साथ-साथ, यह भी व्यवस्था थी कि भारत सरकार ही उसको बनायेगी, यही पिछली बार आप लोगों ने, पिछले दिनों में कानून बनाते हुए उसको तय किया था, उस प्रतिबद्धता को हम स्वीकार करते हैं, उसको दोहराते हैं। उसके साथ-साथ ऑयल कंपनी भी अपना कान्ट्रिब्यूशन करेगी। दोनों मिलकर देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आन्ध्र प्रदेश स्थित यह इन्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को आपकी अनुमति होगी, आपकी स्वीकृति होगी, उसी पर एक विश्व स्तर का एक इंस्टीट्यूशन बनाया जायेगा, जो आने वाले दिनों में पेट्रो कैमिकल में, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, गैस इकोनॉमी में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में और सारे प्रकार की एनर्जी के व्यवसाय को, वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में, सारे प्रकार की वैकल्पिक ऊर्जा और भारत में लम्बे समय तक गरीबों को, प्रधान मंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, सस्ती दर पर ऊर्जा पहुँचाना, निरन्तर ऊर्जा पहुँचाना, स्वच्छ ऊर्जा पहुँचाना, सुरक्षित ऊर्जा पहुँचाना। इसके लिए हमारी यह सरकार प्रतिबद्ध है। यह इंस्टीट्यूट इस प्रकार के कामों में नींव का पत्थर होगा। इसके लिए आपकी स्वीकृति चाहिए। मैं अध्यक्षा जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस वितर्क को यहाँ रखने का मौका दिया। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to declare the institution known as the Indian Institute of Petroleum and Energy to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration.

The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 5 Constitution of Board of Governors

HON. SPEAKER: Shri N. K. Premachandran, are you moving your Amendment Nos. 1 to 4 to clause 5 ?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I am not moving Amendment Nos. 1 to 5.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 to 8 were added to the Bill.

Clause 9 Functions of Institute

HON. SPEAKER: Shri N. K. Premachandran, are you moving your Amendment Nos.6 to 9 to clause 9?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Yes, Madam.

I beg to move:

Page 3, line 45, –

after "admission"

insert "of meritorious students". (6)

Page 4, line 5, –

after "integration of"

insert "learning,". (7)

Page 4, line 16, –

after "students"

insert ", faculties, researchers". (8)

Page 4, line 18, –

after "employees"

insert ", students, researchers and faculties".

(9)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 6 to 9 moved by Shri N. K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clause 10 Powers of Board

HON. SPEAKER: Shri N. K. Premachandran, are you moving your Amendment Nos.10 to 13 to clause 10?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes, Madam.

I beg to move:

Page 5, line 24, –

after "of the Institute"

insert "so as to maintain the international standard". (10)

Page 5, line 44, –

after "charges"

insert "reasonable and affordable to the students". (11)

Page 6, lines 10 and 11, –

for "Central Government"

substitute "Union Cabinet". (12)

Page 6, line13, –

for "or any authority"

substitute "not below the rank of a Head of Department". (13)

Madam, the fees of the Institute should be reasonable and affordable and disposing of the land should be with the permission of the Union Cabinet, not by the Central Government. It is because, there is a Supreme Court judgement that the public sector undertaking property shall not be disposed of without having concurrence of the Union Cabinet, not the Central Government.

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 10 to 13 moved by Shri N. K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clauses 11 to 14 were added to the Bill.

Clause 15 Constitution of General Council

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran to move Amendment Nos. 14 to 16 to Clause 15.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 6, *after* line 44, -

insert "(aa) the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change in the Central Government who shall be the Co-Chairperson.". (14)

Page 7, line 17, -

for "Chairperson"

substitute "Central Government". (15)

Page 7, line 21,-

after "meeting"

insert "with the prior permission of the Central Government". (16)

Madam, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change representatives are not there in any of the Council or Senate because the Ministry of Petroleum is closely connected to the Ministry of Environment. Their representations should also be there. If the Minister can assure, I will withdraw.

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 14 to 16 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 15 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 15 was added to the Bill.

Clause 16 was added to the Bill.

Clause 17 Senate

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No. 17 to Clause 17?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I am not moving my Amendment.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clauses 17 to 32 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 17 to 32 were added to the Bill.

Clause 33 Statutes how made

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No. 18 to Clause 33?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes madam, I beg to move:

Page 10, line 36, -

after "section provided"

insert "with the prior approval of the Central Government and the same shall come into force from the date of notification in the official gazette". (18)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 18 to Clause 33 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 33 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 33 was added to the Bill.
Clauses 34 to 36 were added to the Bill.

Clause 37 Tribunal of Arbitration

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment No. 19 to Clause 37?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I am not moving my Amendment.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clauses 37 to 45 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 37 to 45 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: I beg to move:

"That the Bill be passed. "

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed. "

The motion was adopted.

———————

माननीय अध्यक्ष : श्री कामाख्या प्रसाद तासा - उपस्थित नहीं।

श्री गोपाल शेट्टी।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्षा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा विषय छोटा-सा है। मैं पूरा पढ़ लूंगा।

अध्यक्षा जी, केन्द्र की जो योजनाएं चलती हैं, पूरे देश भर में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, उन पर अमल नहीं किया जाता है। चाहे केन्द्र के अधिकारी हों, चाहे राज्य के अधिकारी हों, उन्हें ऐसा लगता है कि शहर में सब श्रीमंत लोग ही रहते हैं। मुम्बई जैसे शहर में 60 प्रतिशत लोग झोपड़-पट्टी में भी रहते हैं। इसलिए केन्द्र की सभी योजनाओं का लाभ मुम्बई शहर के और देश के सभी शहरों के लोगों को मिलना चाहिए।

अध्यक्षा जी, केन्द्र सरकार की जो एम.एस.डी.पी. स्कीम है, यह स्कीम महाराष्ट्र के सिर्फ चार जिलों और उन 50 कस्बों में ही लागू है। इससे भी मुम्बई शहर को वंचित रखा गया है। हमारे नक़वी जी, जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम करते हैं, इन्होंने पूरे देश भर में माइनॉरिटी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। हमारे मुम्बई शहर में, खासकर, जो मालवणी परिसर है, जहां पर 75 प्रतिशत मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, वहां की लड़कियों के पढ़ने के लिए वहां एक भी कॉलेज नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चियां दसवीं कक्षा के बाद स्कूल जाते ही नहीं हैं। मेरी सोच है कि अगर बच्चियां पढ़ेंगी तो उनसे शादी करने वाले लड़के भी उनसे ज्यादा पढ़ेंगे। इससे देश की जो ये सारी समस्याएं हैं, वे खत्म हो जाएंगी। मलाड में इसके लिए 40 सालों से एक ज़गह रिज़र्व है, लेकिन न तो केन्द्र की सरकार और न ही राज्य की सरकार इसके लिए कोई पहल करती है। मैं मांग करता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी यहां पर एक विश्वविद्यालय खोला जाए।

केन्द्र सरकार की जो योजना है, जिसके लिए नक़वी जी बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, यह विश्वविद्यालय यहां पर खुलने से माइनॉरिटी समाज के बच्चों को इससे लाभ मिलेगा।

अध्यक्षा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. मनोज राजोरिया एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदया, पिछले कुछ वर्षों से रेलवे क्रॉसिंग पर आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अंडरब्रिज बनाये गए हैं। ये अंडरब्रिज सैद्धांतिक रूप से सफल प्रतीत हो रहे हैं, किंतु व्यावहारिक तौर पर गंभीर समस्याओं को जन्म दे रहे हैं।

महोदया, योजना के तहत सर्वाधिक अंडरपास ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये गए हैं, जहाँ से पूरी ग्रामीण आबादी का आवागमन होता है, साथ ही खेतों में आने-जाने का प्रमुख रास्ता भी यही है। वर्षाकाल में इनमें जल भराव होने तथा पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। रात्रि में किसानों व ग्रामीणजनों के आवागमन में पानी का अनुमान नहीं लगने के कारण कई वाहन, गाड़ी, दो पहिया वाहन आदि डूब जाते हैं, गिर जाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़, मध्यप्रदेश में अधिकांश अंडरपास की यही स्थिति बनी हुई है। जिनसे अधिकांश जगहों पर ग्रामीणजनों तथा जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको भारी असुविधा हो रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षाकाल में अंडरपास से ग्रामीण क्षेत्र के आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश प्रसारित करें, जिससे जनमानस विशेषकर ग्रामीणजनों व किसानों को राहत महसूस हो सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री शरद त्रिपाठी, श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री राजीव सातव, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर, श्री नागेन्द्र सिंह तथा कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रोड़मल नागर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Madam, there is a 100-bedded ESIC hospital in my constituency at Ulhasnagar. It is more than four decades old. It comprises 13 buildings. Though the hospital is more than four decades old, it lacks the basic facilities like there is no potable X-ray machine. It does not have pulse oximeter, defibrillator, bedsides monitor and fumigation machines. No surgery takes place. The hospital does not even have an ambulance. Many of the equipments are 40 years old.

Structural audit of this building was carried out by the IIT, Mumbai and it was declared as 'damaged beyond repair'. It has been advised to demolish the building and go for re-development. The West Zone of ESIC has sent the proposal here to the headquarters at Delhi. The hospital urgently needs to be shifted to a temporary location. Even many of the posts are vacant here. Against the sanctioned workforce of 248, only 138 posts are filled. Therefore, I request the hon. Minister, through you, Madam Speaker, to urgently sanction the re-development of this hospital, move the existing building to a temporary rented

location and also provide the basic facilities so that lakhs of people would be benefited from this.

Also, build a super specialty hospital in the place of the existing hospital when they carry out the re-development.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. मनोज राजोरिया को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र स्थित छत्तरपुर रेल सुविधाओं की दृष्टि से अभी भी काफी पीछे है। झांसी से खजुराहो तक मात्र एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी। अभी पिछले दिनों 13 जून से खजुराहो से भोपाल तथा भोपाल से खजुराहो महामना एक्सप्रेस ट्रेन चलनी प्रारंभ हुई है। इस ट्रेन की जो समय-सारणी है, उसका समय ठीक नहीं होने के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को इस ट्रेन की सुविधा का जो लाभ मिलना चाहिए, वह उतने अच्छे ढंग से नहीं मिल पा रहा है। यह ट्रेन भोपाल से सुबह 6.50 पर चल कर टीकमगढ़, छत्तरपुर होते हुए खजुराहो दोपहर एक बज कर 40 मिनट पर पहुंचती है और खजुराहो से शाम 4 बज कर 15 मिनट पर चलकर भोपाल में रात्रि 10. 55 पर पहुंचती है।

अध्यक्ष महोदया, टीकमगढ़ तथा छत्तरपुर बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और यहां के लोग जब शासकीय कार्य हेतु भोपाल जाते हैं, वे शाम की ट्रेन से जाते हैं, तो उनको वहां पर रात्रि में रूकना पड़ता है। दूसरे दिन भोपाल में अपना काम करा कर फिर शाम को उनको ट्रेन उपलबध नहीं होती है। अगले दिन जब भोपाल से प्रातःकाल ट्रेन मिलती है, तो उसी दिन टीकमगढ़, छत्तरपुर वापिस आते हैं। उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे दो दिनों तक होटल में ठहरने का अपना खर्च वहन कर सकें।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि टीकमगढ-छत्तरपुर के लोगों की कठिनाइयों को अनुभव करते हुए, महामना एक्सप्रेस की समय-सारणी को परिवर्तित करते हुए, इसको खजुराहो से सुबह पाँच-छह बजे के आस-पास चलाया जाए, ताकि यह ट्रेन 11 बजे के आस-पास भोपाल पहुंच जाए और शाम को भोपाल से छह बजे के आस-पास चलायी जाए, ताकि खजुराहो रात्रि 12 बजे तक पहुंच जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इतना लंबा-चौड़ा न बोलें। अब, अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर, श्री नागेन्द्र सिंह तथा कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*SHRI SANJAY KAKA PATIL (SANGLI): Hon'ble Madam Speaker, due to excessive rain, water level gets increased which leads to flood like situation during monsoon. This rain water can be used for irrigation purposes. I am thankful to you for allowing me to speak on it during this 'Zero Hour'. I would like to draw the attention of the Central Government towards this important issue. Ours is an agriculture dominated country. Around 80% people are dependent on agriculture and agricultural related works for their livelihood. Hence to develop farming, it is our duty to provide better irrigation facilities to the farmers in order to help them to overcome their problems. During the Atal Bihari Vajpayee regime, the river linking programme was initiated. But due to the lack of co-ordination between the Central and State Governments during UPA regime, it could not progress further. Under this programme, it was envisaged to connect rivers, rivulets, lakes, ponds and other sources of water to divert this water towards the drought affected areas so that it can be used for irrigation. Through you Madam, I would like to request the Central Government to formulate a new irrigation policy and this important programme should be revived once again. Better co-ordination with State Governments should be developed and more funds should be infused in this project. I am sure by doing this, our farmers would get a new life by overcoming these drought related problems.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Sanjay Kaka Patil.

SHRI B. SENGUTTUVAN (VELLORE): Thank you, Madam, for affording me this opportunity to speak on a matter of considerable importance to the Tamil people. There are two villages, namely, Pallisandhai Thidal and Keezhadi situated on the bank of Vaigai river in Sivagangai district of Tamil Nadu. The Archeological Survey of India has been conducing excavations in about 200 areas and they have undertaken excavations in two areas. About 3000 artifacts and other

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

articles have been recovered from the excavated sites. They have been transported to Bengaluru instead of being kept in an onsite museum.

The person, who has been in charge of excavation, has been transferred all of a sudden and inexplicably. Therefore, there is a considerable delay in completing the excavation. I urge the Ministry of culture to immediately nominate another officer to do the work and expand the area of excavation and construct an on-site museum as directed by the Madras High Court. Thank you, Madam.

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Madam Speaker, I would like to raise a very important public issue in this august House regarding the financially backward classes among the forward communities.

Most of the welfare schemes announced by the Government relate to the upliftment and benefits to all the prevailing communities except the forward community.

Madam, the Sinhu Commission was formed in 2006 for identifying the financially backward classes among the forward communities, which fall under the Below Poverty Line and to frame welfare schemes in terms of education, housing, healthcare through financial assistance and job creation.

The Commission had recommended the formation of a national commission and a welfare corporation for forward communities and a permanent commission for forward communities at the national and State level. The recommendations were submitted to the Centre six years ago. Unfortunately, nothing has happened till now.

Madam Speaker, the Centre had formed a new National Commission for Backward Classes, which was the authority of hearing the complaints and grievances of socially and educationally backward classes. It has the powers of a civil court for this purpose. This is a welcome measure. The forward communities under BPL are also suffering with similar problems.

Therefore, forming a national-level commission for the development of forward communities has become essential. It is, therefore, urged upon the

Government to ensure that even the people belonging to forward castes under the below poverty strata need help from the Government. Therefore, the recommendations of the Sinhu Commission, including forming a National Forward Commission as well as Forward Corporation on the lines so formed by the Government of Kerala may be considered.… (*Interruptions*)

The Government should take immediate initiative to constitute it for the upliftment of backward sections of Forward communities. This can also meet the end of social justice. … (*Interruptions*)

Thank you.

15.00 hours

*SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Hon'ble Speaker Madam, it is a matter of pain and great shame that even after so many years of independence of the country, the birthplace of pioneer of Indian Renaissance, Raja Rammohan Roy i.e. Radhanagar, Khanakul and birthplace of Ramkrishna Paramhansa – Kamarpukur, Goghat and adjoining areas are reeling under severe flood situation. People of the pilgrim spot Tarakeshwar are suffering like anything due to the flood. Our Hon'ble Chief Minister Mamata Banerjee is trying her best to support lakhs of marooned people.

Rivers like Damodar, Mundeshwari, Dwarkeshwar, Rupnarayan are flowing through Arambagh. Due to siltation, the river beds have risen, and the rivers are in spate. Local people are so annoyed with the Damodar Valley Corporation that they call it "Dobano Bhashano Corporation i.e. the corporation which causes flood. As per planning, the dams should regulate 10 lac cusec water but that 's not happening.

Due to siltation, the present condition of Durgapur barrage is critical. To alleviate the situation the Ghatal Master Plan must be implemented immediately. Moreover the dams should be desilted as early as possible.

I draw the kind attention of the Central Government to take all necessary steps to control flood situation so that the history of lower Damodar Valley is rewritten. That new history will not mix with the tears of the flood affected people. Rather the alluvial soil will usher in a wonderful future for the common man in the coming days. Thank you.

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान अन्नदाता कहलाता है। हमें यह भी ज्ञात है कि देश में किसानों का वर्तमान और भविष्य प्रकृति के हवाले हैं। हमने देखा है कि सदन में वर्षों से किसानों के हितों की चिंता के लिए और उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए लगातार चर्चा होती आई है। मैं आज बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए जितने भी बेहतरीन प्रयास हुए हैं, माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान किसानों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। किसान कच्चे माल का उत्पादक है, वह उत्पादन करता है, बाजार में बिक्री करता है, लेकिन वह कच्चे माल से बनने वाले बाए प्रोडक्ट से होने वाले मुनाफे के लाभांश से वंचित रह जाता है। जैसे 75 ग्राम आलू से बनाया गया चिप्स का पैकेट बाजार में 25 रुपए के मूल्य में बिकता है जबकि किसान को कच्चे माल का मूल्य 50-75 पैसे ही मिलता है।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि इस तरह के बाए प्रोडक्ट से होने वाले मुनाफे का लाभांश किसानों का दिया जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. मनोज राजोरिया, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. किरीट पी. सोलंकी, श्री सी.पी. जोशी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रीति पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट) : माननीय अध्यक्ष जी, असम का 2/3 एरिया बाढ़ में बह गया था। मैं इस एरिया के लिए इंटर मिनिस्टीरियल टीम बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, इसमें एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री रहेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि 2000 करोड़ रुपए दिए, 250 करोड़ रुपए भी दिए। 2000 करोड़ रुपए नार्थ-ईस्ट, 250 करोड़ रुपए असम, 100 करोड़ रुपए ब्रह्मपुत्र कोर्स स्टडी के लिए दिए गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इंटर मिनिस्टीरियल टीम में एक टीम बनाई जाए जो रिपोर्ट बनाए ताकि असम में काम करने की सहूलियत हो सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री जॉर्ज बेकर और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Madam Speaker, I thank you for giving the opportunity to bring to the notice of the Government the issue of implementation of VII Pay Commission recommended pay-scales for UGC to the

university and college teachers in the country. The implementation of these scales is due from 1st January, 2016.

Due to non-implementation of the pay-scales, the academicians, who are in a dignified position, are compelled to come on to the roads and participate in dharnas etc. Due to their participation in the agitation, sometimes the academic schedule is also disturbed. I wish to make a request to the hon. Minister who is working hard to bring some reforms in the education system. If the pay-scales are implemented on time, then they can help the Government in reforming the education system. No Government has denied it and no Government is going to deny the implementation of these pay-scales. Why are they prolonging it for the last 2-3 years? Hence, they are agitating because of this issue. So, I once again request the Ministry, through you, Madam, to implement their pay-scales on time.

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक बेहद दुखद घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वर्ष 1952 में हेलसिंकी ओलम्पिक्स में व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक दिलवाने का काम जाने-माने रेसलर स्वर्गीय खाशाबा जाधव ने किया था। लेकिन आज महाराष्ट्र में स्वर्गीय खाशाबा जाधव जी के बेटे ने उस पदक को नीलाम करने का ऐलान किया है। यह बहुत दुखद और शर्मनाक बात है। उसका इस पदक को नीलाम करने का कारण है कि वर्ष 2009 में महाराष्ट्र सरकार ने कुश्ती के लिए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाने का ऐलान किया था, लेकिन वह आज तक नहीं बना।

अध्यक्ष महोदया, मैं पिछले नौ साल से खाशाबा जाधव जी को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिलवाने की मांग कर रहा हूं, लेकिन केन्द्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही राज्य सरकार ने ध्यान दिया। खाशाबा जाधव जी जैसे ओलम्पिंक विनर, जिन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा करके हेलसिंकी ओलम्पिक्स में देश का नाम रोशन किया था, आज अगर उनका बेटा वह पदक नीलामी में बेचना चाहता है, तो यह बहुत शर्मनाक बात है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उनके जन्म गांव कराड में कुश्ती स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाने के साथ-साथ उन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया जाये।।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र,श्री कपिल मोरेश्वर पाटील, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री जॉर्ज बेकर, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री अरविंद सावंत, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, श्रीमती रक्षाताई खाडसे, श्री राहुल शेवाले, श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे और श्री

राजीव सातव को श्री राजू शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Hon. Speaker, Madam, at present, the weaving industry, particularly, the handloom weavers and small traders are facing lots of difficulties to sustain and continue their work. The GST has increased the burden on weavers as more than 90 per cent of the power-loom units are in the small and minor sector, and 12 per cent tax is being paid for the yarn used in weaving and tax is also being paid for processed textiles. Hence, the additional tax in the form of GST is unjustified.

In my Arani Parliamentary Constituency, there are thousands of handloom weavers engaged in weaving and textiles sector traditionally for several decades. Most of them are illiterate and depend solely on weaving industry for their livelihood. They have no access to computers and cannot even think about filing GST online. The GST rules and online filing are impossible and absolutely out of reach of these traditional weavers. With their very meagre income they cannot afford to have computers or engage any computer-literate accountants.

Therefore, I would urge upon the Union Government to consider these ground realities and hardships faced by weavers, and exempt the handloom weavers and small traders from the ambit of GST. Thank you, Madam.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I support the issue that has been mentioned by the hon. Member.

HON. SPEAKER: Yes.

Shri Rabindra Kumar Jena and Dr. Kirit P. Solanki are also permitted to associate with the issue raised by Shri V. Elumalai.

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Thank you very much, Madam. The Government has recently proposed a strategic disinvestment for Air India, and my submission is for the Government to reconsider it.

My argument goes like this that for decades together Air India has stood the test of time and I am sure that everybody will agree with me in the House and outside the House that Air India has really served the country so very well. Whenever we needed Air India's service for evacuation of any Indians anywhere in the world, it was Air India, and for various pilgrimage, etc. Air India was used. Even our hon. Prime Ministers very proudly travel by 'Air India One'.

Air India has been a hub of training pilots, training engineers and today, if we have private airlines, it is thanks to Air India's training programme.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Air India is our national carrier.

SHRI DINESH TRIVEDI: Yes, it is, and all the countries in the world protect their national carrier. … (*Interruptions*)

Madam, I will take one more minute, and I guarantee you that I will be done. I have always compared Air India with AIIMS. Today if we have the private hospitals, thanks to AIIMS for providing technicians, doctors, nurses, etc.

In conclusion, when it comes to private sector and if you see the NPAs, they are in lakhs and lakhs of crores of rupees. Banks give them restructuring and all the other facilities. That is also Government money. Recently because of various management expertise and the new man who has come to the Railways, it has done very well and we are having operating profits. So, my urge and request to the Government is, that we are very proud of our national carrier. The problem was with the management. We have lucrative routes to the private airlines. All the problem is because of the management; and at the Government level, it was bad. Air India has the best of staff. I am sure, Air India would do proud to India. I urge the Government to kindly reconsider as it is already making an operating profit. Certain improvement is definitely required. All your seats are going full. I urge you, and through you, to the Government to kindly reconsider this proposal.

HON. SPEAKER: Shri Jitendra Chaudhury, Shrimati P.K. Sreemathi Teacher, Shri (Md.) Badaruddoza Khan, Shri Sankar Prasad Datta, Shri M.B. Rajesh, Dr. Sanjay Jaiswal, Shri Rajendra Agrawal, Shri Dushyant Chautala, Shri George Baker, Shri Naranbhai Bhikhabhai Kachhadiya, Shri Rabindra Kumar Jena and Shri N.K. Premachandran are allowed to be associated with the issue raised by Shri Dinesh Trivedi.

15.11 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS .... Contd.

(ii) Re: Exclusion of Ms. P.U. Chitra, the Asian Gold medallist from the list of the 24-member team from India to take part in the World Championship in London

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I would like to invite the attention of this august House relating to a most discriminatory nature of our Athletics Association of India towards a girl athlete of Kerala, P.U. Chitra. She is ranked as the number one in Asian Championship. She has the right to participate in the World Championship. In the last minute, the Athletics Association of India intimated the girl that she would not be part of the international event. Kerala High Court too intervened in this matter. It has given a clear verdict that she should be included in the list but the Athletics Association is hearing anybody. Hon. Minister is also helpless in this regard. How can the nation go on like this? She is a grassroot level poor girl from a village of Kerala. She is emerging as a national and international athlete but the Athletics Association is not promoting such promising athletes. My request to the Government is to order an inquiry on this incident to know as to what has happened and what type of injustice has been meted out to this girl athlete. Therefore, I seek an immediate inquiry from the Government so that justice is rendered to the girl. A case is before the Kerala High Court also. Therefore, I would urge the Government to please look into the matter. I think, the hon. Minister would like to respond on this matter. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Dr. Kirit P. Solanki are allowed to be associated with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): The case of athlete of Kerala, U.C. Chitra, is a matter of concern. I would definitely bring this to the notice of the hon. Minister of Youth Affairs and Sports for appropriate action. … (*Interruptions*)

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि समुचित ज्ञान के अभाव में, देश के अन्न पैदा करने वाले किसान, खासकर फल और सब्जियां पैदा करने वाले किसान अपनी फसलों को उगाने के लिए और ज्यादा उत्पादन के लिए अन्धाधुन्ध रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। किसान अनजाने में ऐसा कह रहे हैं, जबकि हमारी सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड योजना लाई है और उनको इस बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन उस किसान से बड़ी गलती उसका व्यापार करने वाले कर रहे हैं, जो रासायनिक दवाइयां फलों-सब्जियों पर छिड़क रहे हैं। उन दवाइयों को डालकर वे उनको जल्दी तैयार करते हैं या फिर बासी सब्जियों को ताजा दिखने के लिए उन पर केमिकल्स डालते हैं। मेरा कहना है कि इसके कारण देश में किडनी, लीवर आदि संबंधी गंभीर बीमारियां लोगों में फैल रही हैं। गरीब लोग इन बीमारियों के महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार उनको मदद देती है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी डिमाण्ड रखिए, लम्बा वक्तव्य मत दीजिए। सवा तीन बज रहे हैं।

श्री सुशील कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदया, इसके लिए जब हम अनुशंसा करते हैं तो आधी-अधूरी राशि प्रधानमंत्री सहायता योजना से मिलती है। मेरा कहना है कि इसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, जिससे किसान को इस बारे में बताया जाए और उस पर कुछ पाबन्दियां भी लगाई जाएं। उनको ज्ञान भी दिया जाए और उनको संयमित भी किया जाए, क्योंकि किसानों के बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, उनके भी लीवर और किडनी खराब हो रही है। देश के अंदर सरकार इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप करे, जिससे किसानों को जागरूक किया जा सके और इस समस्या से देशवासियों को निजात मिल सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री आलोक संजर, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री दद्दन मिश्रा, श्री जगदम्बिका पाल, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता एवं डॉ.वीरेन्द्र कुमार को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri M.B. Rajesh. You can raise only one subject. How have you given notices of two subjects?

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Madam, I will raise only one subject.

HON. SPEAKER: Yes.

SHRI M.B. RAJESH: Thank you Madam Speaker. Contrary to the earlier assurance, now the Government is disinvesting strategic PSUs including BEML and other Defence PSUs.

BEML is ranked number one among the listed CPSUs in the country. The contribution of the BEML to the national exchequer in the last ten years alone is Rs.6,500 crore in terms of taxes and dividends. The Government is now, along with disinvestment of 26 per cent shares, handing over the management control to the strategic buyer. It was informed to the House last week. The private buyer will now have the control of assets worth Rs.50,000 crore of BEML. This is nothing but killing goose which gives you golden eggs.

I demand from the Government to kindly reconsider this decision to have a strategic disinvestment of BEML. If this Government's patriotic and national pretensions are sincere, please refrain from doing this anti-national act.

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन और श्री पी.के.बिजू को श्री एम.बी.राजेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Ganesh Singh.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You are not Ganesh Singh. Then Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं और निमंत्रण देता हूं कि सभी मेरी बात सुनें। एक माननीय एमपी होने के नाते मेरे ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूं। पिछले पांच सालों से एक माननीय एमपी होते हुए भी मुझे अभी तक 'दिशा' की मीटिंग के लिए न्योता नहीं मिला है। मेरे जिला मुर्शिदाबाद में पिछले पांच सालों से 'दिशा' की मीटिंग नहीं हुई है। मेरा एक गुनाह है कि मैं विपक्ष का एक माननीय एमपी हूं। एक कलैक्टर ने 'दिशा' की मीटिंग बुलाने के लिए हिम्मत दिखाई तो उनको तुरंत ट्रांसफर किया गया।...(व्यवधान) पहले यह विजिलैंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी थी, अब उसका नाम बदल कर 'दिशा' कर दिया गया है।...(व्यवधान) मेरे साथी बदरुद्दीन जी हैं।...(व्यवधान) पिछले पांच सालों से आज तक 'दिशा' की

एक भी मीटिंग नहीं हुई है। इस तरह की लोकतंत्र बंगाल में चल रहा है, मैं इस तरह के लोकतंत्र के खिलाफ हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप की बात हो गयी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पांच साल से 'दिशा' नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी और श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान को श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : अध्यक्ष महोदया, पिछले नौ मार्च को आदरणीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने रांची से टोरी-चंदवा के बीच एक नयी रेल लाइन का उद्घाटन किया था और एक पैंसेंजर गाड़ी की शुरुआत की थी, परन्तु वह गाड़ी भी अनियमित चलती है। गाड़ी का एक फेरा होने के कारण, हम लोगों को बहुत कठिनाई होती है क्योंकि झारखंड का पलामू क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित है, इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करूंगा कि गढ़वा रोड तक पलामू के पूरे क्षेत्र लातेहार, चतरा, डालटेनगंज और मणिका को लाभ देने के लिए जो रांची से टोरी पैसेंजर गाड़ी चलाई जाती है, उसके फेरा को आगे बढ़ा कर गढ़वा रोड तक चलायें और इसको दिन में दो बार चलायें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I raise a very important issue.

माननीय अध्यक्ष : बीच में डिस्टर्व नहीं करना चाहिए। मैं जितना काम कर पाउंगी मुझे करने दें, नहीं तो फिर खड़गे जी नाराज हो जायेंगे।

...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: It is relating to the landing channel for linear broadcast. The landing channel is an in-house channel and that is a slot available within their platform to the MSOs, LCOs and the DTH. The utility of this landing channel for the platform is that every time a viewer switches on the set top box, it automatically opens up on this channel. The purpose was to allow the MSO and LCO to use it either for its own service promotion or the promotion of the third

party brand for a price. The lending channel has become a new revenue source. This may not appear to be a bad thing in isolation. But with only one lending channel slot per network resulted in scarcity means the broadcast industry is exposed to an unfair and anti-competitive practice. The industry needs to set right this new abuse as it is marginalising good content and those channels which do not entertain such practices need to be curbed. They need an industry self-regulation as it will vitiate competition. It is an unfair practice despite being legal.

This is specially happening on English channels. Some broadcasters are using the lending channel slot for as many operators to gain high viewership through high sampling and reach for their channel. This results in spike in the viewership data for the channel as viewers take time to shift from one lending channel to the other. This defeats the very purpose of digitisation. This is forcing viewers to forced viewing through lending channel which is against the basic thrust of digitisation. The regulator should curb these practices and, thereby, false viewership data. The regulator and the Ministry of I&B need to fix this issue. My demand is that there should not be any BARC watermark during such promotions on lending channels.

Lastly, allowing any other channel at linear platform should be declared illegal or else, a technology needs to be innovated to centralise channel's activity remains same at the linear platform across the distribution platform. I am happy that the Chairman of the Standing Committee of Information & Broadcasting is also taking up this issue. But I would expect the Government also to respond to this issue. This is creating a very illegal thing throughout the country and is affecting the viewership to a great extent. A large amount of money is also being siphoned off by a certain group of TV channels.

HON. SPEAKER: Shri Gopal Shetty, Shri Sharad Tripathi, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Dr. Kulmani Samal, Shri Rabindra Kumar Jena, Shri Nishikant Dubey, and Shri Gajendra Singh Shekhawat are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पंजाब की विस्फोटक सिचुएशन की ओर दिलाना चाहता हूँ।

वहाँ हर रोज़ गैंगवार, लूटिंग, किडनैपिंग और क़त्लो-गारद् हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सोचने की बात है कि गैंगवार में जो लोग पकड़े गये, उनका लिंक लुधियाना में हुए एक पारसी के क़त्ल से जुड़ा हुआ है, एक लड़के को गोली मारी गयी, उसके साथ जुड़ा हुआ है।

दुख इस बात का है कि एक ओर यह हो रहा है और दूसरी ओर वहाँ की पुलिस सत्ताधारी लोगों को प्रौपर्टी पर कब्जा करवा रही है।

मैडम, सोचने की बात है कि कामागाटामारू जहाज़ के जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनमें से बाबा सोन सिंह भगना के साथ जो बचकर आये ज्ञानी लाभ सिंह जी, उनके पुत्र जगरूप सिंह को पुलिस ने...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Bairon Prasad Mishra, Shri Sharad Tripaty and Shri Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Prem Singh Chandumajra.

You have raised the matter.

...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, my 'Zero Hour' submission is in respect of deaf athletes who have participated in Deaflympics.

The medal winners in Deaflympics held in Samsun, Turkey had suffered grave insult and neglect from the Indian Sports Authorities. Yesterday, when the Deaflympics medal winners arrived at Delhi Airport, no one from the Sports Ministry was there to receive them. It was an inhuman insult to the medal winners who have returned to India after highlighting the pride of India in Deaflympics. Their travel itinerary and all other details have been furnished. It is quite unfortunate that deaf athletes who participated in Deaflympics in Samsun, Turkey returned after winning one Gold medal, one Silver medal and one Bronze medal, no one was there to receive these deaf athletes at the Airport. It is very unfortunate.

There is another incident of discrimination, Madam. The disabled athletes who participated in Paralympics will be getting Rs. 75 lakh if they win a Gold medal, but in Deaflympics, if they win Gold medal, they get only Rs. 15 lakh. This is discrimination.

These two aspects may be considered. I am seeking a response from the hon. Minister of Parliamentary Affairs. Mr. Ananth Kumar ji, please respond. This is a matter related to the deaf people. Kindly consider this view.

HON. SPEAKER: Shri Mullappally Ramachandran, Shri M. B. Rajesh and Shrimati P. K. Shreemathi Teacher are permitted to associate with the issue raised by Shri N. K. Premachandran.

श्री विजय कुमार हाँसदाक (राजमहल) : मैडम, आपका धन्यवाद।

मैडम, मैं अपने यहाँ के नेशनल हाईवे-80 के संबंध में बोलना चाहता हूँ। नेशनल हाईवे-80 बिहार, झारखंड और बंगाल को कनेक्ट करता है। जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैंने कभी इस रास्ते को भली अवस्था में नहीं देखा है। वहाँ दो बंगाल कनेक्टिंग पुल हैं, जो बीसों साल से खराब होने के बाद भी आज तक नहीं बने हैं। उस रोड के जो भी टेंडर्स होते हैं, वे तीन किलोमीटर, पाँच किलोमीटर या दस किलोमीटर के पैच में होते हैं। ये टेंडर्स लोकल टेंडरर्स द्वारा लिए जाते हैं, परंतु एक या दो साल के बाद इनकी अवस्था फिर खराब हो जाती है। मैं 'दिशा' की बैठक में भी अपने क्वेशचंस के जवाब माँगता हूँ, लेकिन वहाँ इनके कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं।

मैडम, आपके माध्यम से मेरी सरकार से यही गुज़ारिश है कि जो भी टेंडर निकाला जाए, कंप्लीटली एक बार में पूरा निकाला जाए और उसकी बढ़िया तरीके से उसकी देख-रेख की जाए। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri S.R. Vijaya Kumar, what is your issue? You have not mentioned any issue.

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Hon. Speaker Madam, heavy rains in Tamil Nadu in December 2015 caused enormous devastation to standing crops, property and public infrastructure besides loss of livelihoods and loss of human lives and cattle. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchi Thalaivi Amma* had requested the Union Government to release Rs. 25,912.45 crore to the State Government but the Union Government provided only Rs. 1,960 crore. Even a year later, after a Central team had inspected and given a

detailed report on devastation caused by heavy rains and cyclone in 2015, the Union Government has so far not provided adequate relief to Tamil Nadu.

HON. SPEAKER: You do not have to read the whole text. आपको पैसे मिलने हैं। Tamil Nadu wants it.

Shri P.R. Sundaram is permitted to associate with the issue raised by Shri S.R. Vijaya Kumar.

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Hon. Speaker Madam, I want to raise an important issue regarding coconut and arecanut farmers who are facing severe problem in Karnataka. Coconut and arecanut are the main plantation crops in our State. Coconut is grown over an area of 5.06 lakh hectares and arecanut is grown in an area of 2.64 lakh hectares. For the past three or four years, we have been facing drought in our State of Karnataka. Due to this, two lakh hectares of coconut and 52,000 hectares of arecanut plantation are completely dried. In this connection, our Chief Minister wrote a letter to the Union Government on 17.05.2017 seeking a special package of about Rs. 2,500 crore for arecanut and coconut farmers. In addition, they are giving input subsidy of Rs. 18,000 per hectare per crop as per NDRF guidelines for crop loss which is very unscientific and very meagre. I urge upon the Union Government to finance the NDRF subsidy for crop loss and release special package for coconut and arecanut farmers in our State.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मैं अहमदाबाद का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अहमदाबाद शहर बहुत तेजी से विकसित होता हुआ शहर है। वह मेगा-सिटी बन चुका है और उसकी पॉप्युलेशन 17 लाख से भी ज्यादा है। अहमदाबाद के बीच में से रेलवे लाइन का प्रसार भी होता है, जो अहमदाबाद शहर को दो हिस्सों में बाँटती है।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी डिमांड रखिए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : अहमदाबाद में केंद्रीय विद्यालय वहाँ के पश्चिमी हिस्सों में आए हुए हैं, लेकिन मणिनगर, इंद्रपुरी, अमरायवाड़ी और नरोड़ा जैसे इलाकों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है।

अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि अहमदाबाद के पूर्वी हिस्सों में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): Hon. Speaker Madam, on one hand we want India to win more medals in Olympics and Asian Games. On the other hand, the Government itself is discouraging the capabilities of our sportspersons by imposing GST on those sportspersons who are capable of coming into the league of medal winners. I would like to mention the sport of shooting where earlier renowned shooters were exempted from import duties and taxes for the expensive equipments they bought for the sport of shooting.

After GST has come into effect, the sport of shooting has become even more expensive. I am sure, Col. Rathore who is one of the few medal winners in this sport of shooting will subscribe to this. … (*Interruptions*) Shooting has won maximum amount of medals in the international arena. Therefore, I request the Government through you to exempt the renowned shooters from paying GST on the equipment they buy. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Gajendra Singh Shekhawat and Dr. Manoj Rajoria are permitted to associate with the issue raised by Shri Kalikesh Narayan Singh Deo.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Thank you very much, Madam.

Right now, Mumbai University is facing a very chaotic condition. They conduct examination for around 477 courses; out of that, generally the results are declared in the month of May or June. Now, it is already August but the results are not declared. Our youth leader Shri Aditya Thackeray met the honourable Governor of Maharashtra. He assured that by the 31st of July the results would be declared. Even that date has passed. The Mumbai University has miserably failed in this. The Vice-Chancellor instead of giving the examination papers for assessment manually has opted for an on-line basis assessment. For that, he issued

a tender. He issued the tender thrice. Ultimately, the tender was accepted at a 50 per cent lesser rate. I do not know the reason for that. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is a State matter.

… (*Interruptions*)

SHRI ARVIND SAWANT: Therefore, I demand the reason for issuing the tender thrice. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Shrirang Appa Barne, Shri Rahul Shewale, Dr. Shrikant Eknath Shinde and Dr. Heena Vijaykumar Gavit are permitted to associate with the issue raised by Shri Arvind Sawant.

SHRI NEIPHIU RIO (NAGALAND): Thank you for giving me the time, Madam.

I rise to the on-going Indo-Naga political dialogue and the peace process. You are aware that the framework between the Government and the NSCN was signed on the 3rd August, 2015 in the presence of the hon. Prime Minister, the Home Minister, a host of VIPs, and top officials.

Yesterday marks the completion of two years since the signing of the historic agreement. The Government of India realised that the Indo-Naga conflict is not a law and order problem but a political issue. So, the Government of India has been trying to resolve this through political means since the 1980s.

This is not only a Naga issue but also a national issue. That is why all the former Prime Ministers were involved. Shri Rajiv Gandhi and then Shri P.V. Narasimha Rao met NSCN leaders. Shri Deve Gowda met NSCN (IM) leaders on 3rd February, 1997 in Zurich. Shri I.K. Gujral made a statement in Parliament regarding ceasefire agreement between NSCN and the Government of India which came into effect on 1st August, 1997. Shri Atal Bihari Vajpayee met NSCN (IM) leaders at Paris in 1998. Dr. Manmohan Singh met the NSCN (IM) leaders in Delhi in the year 2004. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Niephiu Rio, it is okay. You have to complete now.

… (*Interruptions*)

SHRI NEIPHIU RIO : I appeal to the Government of India to work out a solution before the conduct of the forthcoming general assembly elections scheduled for February, 2018, in Nagaland. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, I know your demand.

… (*Interruptions*)

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में शाकाहारी परिवारों की बड़ी संख्या है। इन परिवारों के बच्चे जो होटल प्रबंधन की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, होटल में मांसाहार के बढ़े प्रचलन के कारण व्यावहारिक कठिनाइयों की वजह से होटल प्रबंधन के व्यवसाय में नहीं जा रहे हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा केवल शाकाहारी कुकिंग के लिए बीएस.सी डिग्री प्रोग्राम तीन सस्थानों गांधी नगर, भोपाल व जयपुर में प्रारम्भ किया गया है तथा शीघ्र ही भारत के 18 अन्य संस्थानों में प्रारम्भ करने की योजना के कारण इस क्षेत्र में विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि शाकाहारी छात्रों की संख्या होटल प्रबंधन में बढ़ाने व शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए केवल शाकाहारी के साथ होटल व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों में भी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाएं जिससे रिसर्च फॉर वेजीटेरियन फूड, जिसको हॉस्पीटेलिटी से भी जोड़ा जा सकता है, यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाए।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Rodmal Nagar and Shri Alok Sanjar are permitted to associate with the issue raised by Shri Ajay Mishra Teni.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं वित्त मंत्री जी और अनंत कुमार जी से जानना चाहता हूं कि यह ... * हवाला ऑपरेटर कौन हैi जो 4 करोड़ रुपया बैंगलौर से ट्रांसफर होता है और उसमें से तीन करोड़ रुपया दिल्ली में ... * में आता है...(व्यवधान) ये ... * क्या है?..(व्यवधान) बैंगलौर में एक मां कह रही है ...(व्यवधान) कि मेरे बेटे को ... * ने फंसाया है...(व्यवधान) यह ... * कौन है?...(व्यवधान) कर्नाटक का ... * को क्यों फंसा रहे हैं?...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, कोलार प्रोजेक्ट दिया गया, जिसमें दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया गया...(व्यवधान) कांग्रेस को ऊर्जा कौन दे रहा है...(व्यवधान) बैंगलौर के रिजॉर्ट में इतने लोगों को रखा गया है,...(व्यवधान) उनका पैसा कहां से आ रहा है?...(व्यवधान) कांग्रेस वाले इस बात का जवाब दें कि यह तीन करोड़ रुपया कहां से आया?...(व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे, श्री शरद त्रिपाठी, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रवीन्द्र कुमार राय, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री गोपाल शेट्टी को डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

15.35 ¾ hours

(*At this stage, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Tuesday, the 8th August, 2017 at 11.00 a.m.

15.36 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 8, 2017/Shravana 17, 1939 (Saka).